ELITE IAS

समसामयिकी

नवम्बर- 2018

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

English / Hindi

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

English / Hindi

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	एजेंडे पर आते सुरक्षा सरोकार	1-2

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी	3-3
3.	भारत के प्रधानमंत्रियों पर दिल्ली में संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा	4-4
4.	सरदार पटेल के 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण	5-5
5.	सीबीएसई ने स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियमों में बदलाव किया	6-6
6.	सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का	6-7
7.	उत्तर प्रदेश सरकार ने 'इलाहाबाद' का नाम बदलकर 'प्रयागराज' किया	7-8
8.	ऊर्जा मंत्री ने 'सौभाग्य' के अंतर्गत पुरस्कार योजना लांच की	8-9
9.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2018	9-9
11.	आयुष्मान योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार जरूरी	10-10
12.	असम स्थित माजुली द्वीप पर पहली बार रो-रो सेवा आरंभ की गई	11-11
13.	भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत: रिपोर्ट	11-12

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

14.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016: विश्लेषण	13-14
15.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए मंत्री समूह गठित	14-14
16.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु एसपीजी गठित	15-15
17.	महिला और बाल विकास मंत्रालय ने #MeToo पर जांच समिति गठित की	16-16
18.	निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी	16-17
19.	भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन नियमन, 2018 अधिसूचित	17-17
20.	सतत विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए संचालन समिति गठित	18-18
21.	महिला सुरक्षा सेवा 'वोडाफोन सखी' की शुरुआत	19-19
22.	अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर	19-20

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

23.	भारत और रूस के मध्य एस-400 मिसाइल सिस्टम सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर	21-21
24.	भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का चुनाव जीता	22-23
25.	भारत और चीन ने पहली बार सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये	23-24
26.	ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018: भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ	24-24
27.	भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर पहली त्रिपक्षीय बैठक की	25-26
28.	भारत और बांग्लादेश के बीच जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर	26-26
29.	भारत एवं जापान ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये	26-26
30.	भारत और ताजिकिस्तान के मध्य नौ समझौतों पर हस्ताक्षर	27-28
31.	अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु संधि समाप्त करने की घोषणा की	28-29
32.	अमेरिका और कनाडा के बीच नाफ्टा समझौते को लेकर सहमति बनी	29-30
33.	ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट: पाकिस्तान सीरिया से तीन गुना ज्यादा खतरनाक	30-31
34.	बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का नया कार्यक्रम	31-32
35.	चीन द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषणा	32-32
36.	भारत और अजरबैजान ने व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए	33-33
37.	मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला किया	33-34

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

38.	भारत में 2014 से करोड़पति करदाताओं की संख्या 60 प्रतिशत बढ़ी: सीबीडीटी	35-35
39.	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 77वें स्थान पर	36-37
40.	गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन	37-38
41.	एमएसएमई सेक्टर हेतु सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ	38-39
42.	सरकार द्वारा स्वर्ण बॉन्ड योजना जारी	39-40
43.	भारत छह साल में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा: IATA रिपोर्ट	40-41
44.	बिहार में तय समय से पहले ही पूरे राज्य में शत प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा	41-42

45.	WEF इंडेक्स में भारत बना 58वां सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाला देश	42-43
46.	अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर	43-44
47.	विश्व आर्थिक मंच द्वारा 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट जारी की गई	44-44

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

48.	भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास 'जेआईएमईएक्स 18' विशाखापत्तनम में शुरू	45-45
49.	भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया	46-46
50.	कोचीन में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण की घोषणा	47-47
51.	एमआईटी वैज्ञानिकों ने बेहद सूक्ष्म रोबोट विकसित किया	47-48
52.	भारत ने इजराइल के साथ 77.7 करोड़ रुपये की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किये	48-49
53.	वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की	49-50
54.	चीन ने विश्व के सबसे बड़े परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया	50-50
55.	हरियाणा सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक बल 'कवच' की घोषणा	51-51
56.	नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब जाने वाला अंतरिक्षयान बना	51-52
57.	'सौरा जलनिधि' योजना का शुभारंभ	52-52
58.	चीन द्वारा वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किये जाने की घोषणा	53-53
59.	पाकिस्तान साल 2022 में भेजेगा पहला अंतरिक्ष यात्री	53-54
60.	पाकिस्तान और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू	54-55
61.	चीन ने दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का पहला सफल परीक्षण किया	55-56
62.	चीन ने पहली बार एक साथ तीन हाइपरसोनिक विमानों के मॉडल का सफल परीक्षण किया	56-57
63.	सस्ती जल कीटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर' विकसित	57-57
64.	भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वयित गश्त का आयोजन	58-58
65.	बिहार की 'शाही लीची' को जी आई टैग प्राप्त हुआ	59-59
66.	भारतीय वायु सेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया	59-60
67.	कोंकण के अल्फोंसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया	60-61

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

68.	आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी की	62-62
69.	अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर	63-63
70.	भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 20 साल में गंवाए 79.5 अरब डॉलर: रिपोर्ट	63-65
71.	भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की घोषणा	65-66
72.	सूनामी प्रभावित इंडोनेशिया के लिए भारत ने 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री' आरंभ किया	66-66
73.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया	66-67
74.	लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018	67-68
75.	वायु प्रदूषण से हर साल 6,00,000 बच्चों की मौत: डब्ल्यूएचओ	68-69
76.	पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा	69-70
77.	कोका-कोला और नेस्ले सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां: ग्रीनपीस रिपोर्ट	70-70
78.	सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल तथा 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया	71-71
79.	सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया	71-72
80.	पर्यावरण मंत्रालय ने 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया	72-73
81.	दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत	73-74
82.	"तितली" चक्रवातीय आँधी	74-75
83.	पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिषेध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (Environment Pollution [1]Prevention and Control Authority – EPCA) का फिर से गठन	75-75
84.	वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'स्टैट' पहल आरंभ	76-76

अन्य `बरें

85.	विश्व खाद्य दिवस: 16 अक्टूबर	77-77
86.	डेनमार्क ओपन बैडमिंटन: साइना नेहवाल ने रजत पदक जीता	78-78
87.	दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का निधन	78-78
88.	वनडे में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा	78-78

89.	पंकज आडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय	78-78
90.	सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस हेमंत गुप्ता, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह और अजय	78-79
91.	महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया	79-80
92.	जेयर बोलसोनारो ब्राजील के नये राष्ट्रपति चयनित किए गये	80-80
93.	एशियाई हॉकी चौंपियंस ट्रॉफी 2018: भारत-पाकिस्तान संयुक्त विजेता	80-81
94.	टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कारों की घोषणा	81-82
95.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सियोल शांति पुरस्कार-2018' हेतु चयनित	82-82
96.	रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता ओसामू शिमोमुरा का निधन	82-82
97.	चीन ने विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया	82-82
98.	अदेल अब्दुल महदी इराक के नए प्रधानमंत्री बने	83-83
99.	उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी का निधन	83-83
100.	भारतीय मूल की मीनल पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया	84-84
101.	आईआरसीटीसी ने 'Ask Disha' चौट बॉट लॉन्च किया	85-85
102.	माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक पॉल एलेन का निधन	85-85
103.	नोवाक जोकोविच ने चौथी बार जीता शंघाई मास्टर्स ओपन खिताब	86-86
104.	पर्यावरणविद् प्रोफेसर जी डी अग्रवाल का निधन	86-86
105.	संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने इस्तीफा दिया	86-86
106.	नोबेल पुरस्कार 2018: विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर अर्थशास्त्र श्रेणी में विजेता घोषित	86-87
107.	कनाडा की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ली	87-87
108.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किये गये	88-88
109.	पृथ्वी शॉ बने टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय	88-88
110.	वैज्ञानिकों को पहली बार सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा का साक्ष्य मिला	88-88
111	नोबेल पुरस्कार 2018: रसायन विज्ञान श्रेणी के लिए तीन वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा	89-89

आलेख
एजेंडे पर आते सुरक्षा सरोकार

कुछ महीनों में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे को चाक-चौबंद करने में खासी तत्परता दिखाई है। सरकार का यकायक ऐसे कदम उठाना कुछ हैरान तो करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक स्वागतयोग्य पहल है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए की अगुआई में रणनीतिक नीतिगत समूह अर्थात एसपीजी का पुनर्गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सहयोग करेगा। एसपीजी के सदस्यों में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव शामिल होंगे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने में अंतर-मंत्रलयी स्तर पर सहयोग एवं समन्वय में इसकी ही मुख्य भूमिका होगी। वैसे एसपीजी की स्थापना वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, लेकिन पहले इसकी कमान कैबिनेट सचिव के हाथ में होती थी। अब यही दारोमदार एनएसए के पास होगा। इसके कारण पहले से ही शक्तिशाली संस्था एनएसए और ताकतवर हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय (एनएससीएस) में भी एनएसए को तीन नायब मिले हैं। इन तीनों के कार्यक्षेत्र का दायित्व भी अलग-अलग है। संयुक्त खुफिया समिति के पूर्व प्रमुख आरएन रवि अभी हाल में तीसरे उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। उनसे पहले रॉ के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना और रूस में भारत के पूर्व राजदूत पंकज सरन पहले ही एनएससीएस में मौजूद हैं।

ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षा नियोजन समिति यानी डीपीसी गठित करने की महत्वपूर्ण पहल के कुछ महीनों बाद देखने को मिल रहे हैं। डीपीसी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में चीफ ऑफ स्टाफ समिति के चेयरमैन, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, व्यय सचिव और विदेश सचिव शामिल हैं। इसका मकसद देश की सुरक्षा के सम्मुख चुनौतियों को देखते हुए उनका दीर्घकालीन समाधान निकालना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हाल में तीनों सेवाओं के लिए साइबर, अंतरिक्ष एवं विशेष अभियानों के लिए विशेष एजेंसियां गठित करने को मंजूरी दी है। सुरक्षा ढांचे के मोर्चे पर यह कायाकल्प एक ऐसे समय पर हो रहा है जब राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजन एक दोराहे पर खड़ा है।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक विशेष दृष्टिकोण के कारण एकीकृत नजरिये का अभाव ही रहा है। तीनों सेवाओं के साथ ही नागरिक एवं रक्षा एजेंसियां भी अक्सर अलग-अलग दिशाओं में काम करती हैं। ऐसा अनौपचारिक रवैया अक्सर वांछित नतीजे नहीं दे पाता और खतरे को भांपने से लेकर सुरक्षा बलों के ढांचागत प्रबंधन को अपेक्षित रूप से नहीं साध पाता। इसमें प्रत्येक सुरक्षा बल अपने स्तर पर ही एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। भारतीय रक्षा नीति से जुड़ी सुर्खियां अधिकांश मौकों पर जमीनी हकीकत से पूरी तरह अलग होती हैं। भारत के 250 अरब डॉलर के सैन्य आधुनिकीकरण पर प्रायः बात होती है। जब नई दिल्ली महत्वपूर्ण हथियारों को हासिल करने में जुटी हुई है तब इस पर भी संदेह गहरा रहे हैं कि क्या उसमें वह क्षमता है जिससे सैन्य सेवाओं में इन संसाधनों को दीर्घावधिक रणनीति के तहत भुनाया जा सके। वास्तव में भारत में 'समग्र रणनीति' का अभाव कई सवाल खड़े करता है।

जबसे हमारा तंत्र अपने अस्तित्व में है तब से ही रक्षा सुधारों के लिए आवाज उठ रही है। यह अभियान रक्षा नीति निर्माण के माध्यम से बिखरे हुए संसाधनों के एकीकरण और समन्वय पर जोर देता है। इससे भी बढ़कर यह अभियान ऐसे सरकारी बुनियादी ढांचे की हिमायत करता है जो राजनीतिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से लागू कर संसाधनों को उनके हिसाब से संतुलित कर सके। भारत में फिलहाल इसका अभाव नजर आ रहा है। समग्र रणनीति विमर्श और रक्षा के मोर्चे पर भारत की स्थिति के च में एक कड़ी बनाकर संसाधनों के संदर्भ में राजनीतिक निर्णयों की बेहतर अभिव्यक्ति हो सकती है। भारत के रक्षा ढांचे एवं प्रक्रियाओं का उद्भव और विकास मौजूदा प्रधानमंत्री के निजी नेटवर्क और प्राथमिकताओं से तय होता है, क्योंकि नीतिगत मोर्चे पर वही निर्धारक होने के साथ ही उसे अमल में लाता है। फिर जब प्रधानमंत्री कमजोर हुए हों या फिर उनके समक्ष कोई अन्य एजेंडा अधिक महत्वपूर्ण रहा हो तो उसका परिणाम नीति निर्माण के मोर्चे पर शिथिलता के रूप में देखने को मिला। रक्षा सुधारों के अभियान की शुरुआत से ही उसका जोर इस बात पर रहा है कि प्रभावी रक्षा नीति के लिए जरूरी है कि सरकारी संसाधनों के बेहतर एकीकरण के साथ ही उचित समन्वय हो, लेकिन इस मामले में खास सफलता नहीं मिल पाई। इस तंत्र में सुधार के लिए आवश्यक होगा कि भारत अपने दुर्लभ संसाधनों का राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध करे। प्रभावी रक्षा नियोजन एवं सैन्य ढांचा एक ऐसे संस्थागत प्रारूप का हिस्सा है जो राजनीतिक आग्रहों से पूरी तरह मुक्त हो, जिसमें संसाधनों को बेहतर तरीके से लामबंद किया जा सके और जिनके बेहतर इस्तेमाल से देश की शक्ति बढ़े। एक ऐसे समय में जब सैनिकों की संख्या से ज्यादा

तकनीक रणभूमि में ज्यादा अहम भूमिका निभाने लगी है तब भारत में अभी भी सुरक्षा बलों के ढांचे को चुस्त बनाने पर बहस की जरूरत पड़ रही है। भारत को अतिरिक्त सैनिकों की संख्या में तत्काल कटौती करनी चाहिए, क्योंकि वार्षिक रक्षा बजट का तकरीबन आधा हिस्सा वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जाता है। यह स्थिति अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी तरह 'मेक इन इंडिया' पहल की प्राथमिकताओं और जटिल रक्षा खरीद प्रक्रिया का भी एक दूसरे से तालमेल बिठाना होगा। दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक की भारत की छवि रक्षा विनिर्माण का गढ़ बनने की उसकी हसरतों से मेल नहीं खाती। तीनों सेवाओं के मुख्यालयों, सेवाओं और रक्षा मंत्रलय के मध्य एकीकरण पर बहस अभी भी जारी है। इसका कोई निष्कर्ष निकलना ही चाहिए।

रक्षा नियोजन की राह में अनिश्चितता का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत के संदर्भ में मानसिकता, ढांचे और प्रक्रियाओं में आमूलचूल बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ ही दुर्लभ संसाधनों पर कायम रहने वाला स्थाई दबाव रणनीतिक रक्षा नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में देर से सही, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे को दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि अभी आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि नीति निर्माता चुनौतियों की गंभीरता को समझ रहे हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी शोर में ऐसे अहम मुद्दों की अनदेखी और उपेक्षा नहीं होगी। आखिरकार सरकारें तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताएं जस की तस कायम रहेंगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कला, संस्कृति, समाज, तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी

चर्चा में क्यों?

☞ सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी।

मुख्य तथ्य

- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच 2010 में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
- पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच कर रही थी।
- 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने विवादित भूमि के मामले की सुनवाई नई बेंच में करने का आदेश दिया था।

क्या था मामला?

- इस्माइल फारूकी ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ना मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं था और वह चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा से विचार करे।
- सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि मस्जिद में नमाज मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए।
- मुस्लिम समुदाय यह भी चाहता था कि मुख्य मामले से पहले 1994 के इस फैसले पर सुनवाई हो। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला तथ्यों के आधार पर होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें।
- गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में जो फैसला दिया था उसके खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर कर रहे थे।

अयोध्या विवादः पृष्ठभूमि

वर्ष	विवाद
1949	बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई। सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर भीतर जाने वाले दरवाजे को बंद किया।
1950	फैजाबाद अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांग की गयी।
1959	निर्मोही आखड़ा ने याचिका दायर कर मस्जिद पर नियंत्रण की मांग की।
1961	सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका, मस्जिद से मूर्तियों को हटाने की मांग की गयी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

1984	वीएचपी ने राम मंदिर हेतु जनसमर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया।
1986	फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा हेतु मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए।
1989	राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के करीब पूजा की इजाजत दी।
1992	कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराया और अस्थाई मंदिर का निर्माण किया।
2003	इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ASI को विवादित स्थल की खुदाई का आदेश दिया।
2010	इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विवादित जमीन को तीन भाग में बांटने के आदेश दिए, अलग-अलग पक्षकारों ने हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
2011	सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर रोक रहेगी। साथ ही विवादित स्थल पर सात जनवरी 1993 वाली यथास्थिति बहाल रहेगी।
2016	विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
2017	सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि अयोध्या विवाद मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए इस्माइल फारूकी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन किया।
2018	सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से जुड़े वर्ष 1994 वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

भारत के प्रधानमंत्रियों पर दिल्ली में संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में तीन मूर्ति एस्टेट पर प्रस्तावित संग्रहालय की आधारशिला रखी।

मुख्य तथ्य

- तीन मूर्ति एस्टेट के 23 एकड़ क्षेत्र में "भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय" स्थापित करने का फैसला किया गया है जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत है।
- संग्रहालय इमारत परिसर का निर्मित क्षेत्र 10975.36 वर्ग मीटर होगा जिसमें 271 करोड़ रुपये की लागत से सभी स्तरों पर गैलरियों के साथ बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल होगा।

प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय

- प्रस्तावित संग्रहालय भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित होगा और इससे आगुन्तकों को आजादी के बाद देश को आकार प्रदान करने वाले नेतृत्व, उनकी पहलों और उनके त्याग के क्रम को समझने में मदद मिलेगी।
- प्रस्तावित संग्रहालय भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री से जुड़े संग्रह, उनके जीवन, कार्य और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के जरिए आधुनिक भारत का वर्णन करेगा।
- यह भारत के लोकतांत्रिक अनुभव का जीवंत वर्णन करेगा।
- यह प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय की भूमिका के बारे में जिज्ञासा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- प्रस्तावित संग्रहालय में एक अनुस्थापन स्थल, स्मृति चिन्ह दुकान, वार्ता / भाषण और विचार-विमर्श आयोजित करने के लिए स्थान, सेमीनार हॉल, ऑडिटोरियम, कार्यशाला क्षेत्र, पुस्तकालय, दस्तावेज रखने के लिए कक्ष, प्रयोगशाला और अभिलेखागार क्षेत्र होगा।
- संग्रहालय एक संस्थान होगा जहां आने वाले लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, उसके उद्भव, भूमिका और केन्द्रीय स्तर पर शासन की भूमिका के साथ-साथ प्रत्येक प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- यह संग्रहालय भारत के युवाओँ और अन्य लोगों को आधुनिक श्रव-दृश्य टेक्नोलॉजी के जरिए जानकारी प्रदान करेगा।
- प्रस्तावित संग्रहालय का डिजाइन भारत का प्रतीक होगा जिसे उसके जाने-माने नेताओं द्वारा वर्षों में आकार प्रदान किया है।

स्रोतः द हिंदू

सरदार पटेल के 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण

चर्चा में क्यों?

- विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया। यह समारोह सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया है।
- सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बताया गया है। मूर्ति का अनावरण करने के लिए समारोह में भारतीय वायु सेना द्वारा फ्लाई पास्ट किया गया. इसके अतिरिक्त, नौसेना और आईएएफ के बैंड द्वारा देशभक्ति संगीत गाया गया।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशेषताएं

- चीन स्थित स्प्रिंग टेंपल की 153 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा के नाम अब तक सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड था लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ने अब चीन में स्थापित इस मूर्ति को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है।
- 182 मीटर ऊंचे 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का आकार न्यूयॉर्क के 93 मीटर उंचे 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' से दोगुना है।
- मूर्ति बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने दावा किया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और महज 33 माह के रिकॉर्ड कम समय में बनकर तैयार हुई है।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है और ऊंचाई 522 फिट यानी 182 मीटर है. प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। इसके पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है।
- सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में करीब 2,989 करोड़ रुपये का खर्च आया। कंपनी के मुताबिक, कांसे की परत चढ़ाने के को छोड़ कर बाकी पूरा निर्माण देश में ही किया गया है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पृष्ठभूमि

- इस स्मारक की आधारशिला 31 अक्तूबर, 2013 को पटेल की 138 वीं वर्षगांठ के मौके पर रखी गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके लिये बीजेपी ने पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया गया।
- सरदार पटेल की यह मूर्ति राम वी. सुतार की निगरानी में हुई है। राम वी. सुतार को वर्ष 2016 में सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था! इससे पहले वर्ष 1999 में उन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है।
- इसके अलावा वे बांबे आर्ट सोसायटी के लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत अन्य पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। वह इन दिनों मुंबई के समुद्र में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की डिजाइन भी तैयार करने में जुटे हैं।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सीबीएसई ने स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियमों में बदलाव किया

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने हाल ही में स्कूलों को मान्यता देने संबंधी अपने नियमों में बदलाव किये जाने की घोषणा की है। इन नये नियमों के अनुसार सीबीएसई ने अपनी भूमिका शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित की है जबकि आधारभूत ढांचे के ऑडिट की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 अक्टूबर 2018 को इस विषय पर घोषणा की कि मान्यता देने वाले सीबीएसई के उप-कानूनों (इलसें) को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह नियम इसलिए बदले गये हैं ताकि त्वरित, पारदर्शी, परेशानी मुक्त प्रक्रियाओं और बोर्ड का आसानी से काम करना सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य तथ्य

- उप-नियमों में बदलाव के साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मान्यता के लिए 8,000 लंबित पड़े आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है।
- यह आवेदन 2007 से लंबित पड़े थे। अब स्कूलों को मान्यता लेने के लिए सिर्फ दो दस्तावेज जमा करने होंगे और आवेदन का निपटारा उसी साल हो जाएगा, जिस साल आवेदन किया है।
- वर्तमान में आरईटी कानून के तहत मान्यता और एनओसी देने के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन स्थानीय निकायों, राजस्व और सहकारी विभागों से मिलने वाले कई सर्टिफिकेट्स का सत्यापन करता है। आवेदन मिलने के बाद सीबीएसई उनका पुनः सत्यापन करता है और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अब यह प्रक्रिया राज्यों पर छोड़ दी गई है।
- सीबीएसई ने अपनी भूमिका में भी बदलाव करते हुए इसे सिर्फ शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित किया है। साथ ही आधारभूत ढांचे के ऑडिट की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई है।
- सीबीएसई बोर्ड अब उन पहलुओं को नहीं देखेगा जिनका निरीक्षण राज्य कर चुका है। अब सीबीएसई द्वारा स्कूलों का निरीक्षण परिणाम आधारित और शैक्षणिक तथा गुणवत्ता उन्मुख होगा।
- गौरतलब है कि देश भर में 20,783 स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें कम से कम 1.9 करोड़ छात्र और 10 लाख से अधिक शिक्षक हैं. मान्यता देने से जुड़े उप कानून 1998 में बने थे और अंतिम बार 2012 में उनमें बदलाव किया गया था। नये बदलावों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

स्रोतः द हिंदू

सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया

चर्चा में क्यों?

- सिक्किम ने 15 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र समर्थित फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड (FPA) जीता। सिक्किम को यह पुरस्कार राज्य को पूर्ण रूप से जैविक राज्य में तब्दील करने के लिए बनाई गई नीतियों के कारण दिया गया है।
- पुरस्कार आयोजकों ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की नीतियों से जहां 66,000 किसानों को फायदा हुआ है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य देशों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विश्व के 51 देशों में से विभिन्न राज्यों को नामांकित किया गया था। पहला पुरस्कार जीतते हुए सिक्किम सभी देशों से आगे निकल गया, वहीं ब्राजील, डेनमार्क, क्विटों, इक्वाडोर ने दूसरा पुरस्कार अपने नाम किया।
- पुरस्कार का सह-आयोजन करने वाली संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की उपमहानिदेशक मारिया हेलेना सेमेडो ने कहा कि यह पुरस्कार भूख, गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट के खिलाफ राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाई गई असाधारण नीतियों का सम्मान है।
- स्कूल के भोजन के लिए खाद्य पदार्थो की खरीद संबंधी नीति तैयार करने के लिए ब्राजील को सम्मानित किया गया है।
- अधिक जैविक खाद्य पदार्थो की खरीद संबंधी नीति बनाने पर डेनमार्क को सम्मान मिला है।
- शहरी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक्वाडोर की राजधानी क्विटो को भी सम्मानित किया गया है।
- सिक्किम के अनुभव से पता चलता है कि 100 फीसदी जैविक खेती एक सपना नहीं है बल्कि वास्तविकता है।
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को खत्म करने के साथ ही उनके स्थान पर स्थायी विकल्पों को प्रतिस्थापित करने पर सिक्किम को 2016 में देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था।

पृष्ठभूमि

☞ इस कार्यक्रम के दौरान एक फिल्म भी दिखाई गई जिसमें सिक्किम के काम करने के तरीकों, मार्केटिंग, किसानों में जागरूकता आदि कदम को दिखाया गया। इस दिशा में 2003 से कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो 2010 तक रखे गए सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन तक पूरा हुआ। राज्य की इस नीति ने सिक्किम को 100 प्रतिशत आर्गेनिक राज्य बनाया।

स्रोतः द हिंदू

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'इलाहाबाद' का नाम बदलकर 'प्रयागराज' किया

चर्चा में क्यों?

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस प्रमुख शहर को अब नए नाम प्रयागराज से ही जाना जाएगा।
- माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम बदल कर इलाहाबाद (अल्लाह आबाद) किया था। साथ ही, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संत लगातार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने की मांग उठा रहे थे। इलाहाबाद में भी देवभूमि से निकलने वाली दो पवित्र नदियां मिलती हैं इसलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है।

प्रयागराज का ऐतिहासिक दृष्टिकोण

- अकबरनामा और आईने अकबरी व अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन् 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी।
- माना जाता है कि अकबर ने यहां नया नगर बसाया जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। उसके पहले तक इसे प्रयागराज के ही नाम से जाना जाता था।
- इसके अतिरिक्त रामचरित मानस में इसे प्रयागराज ही कहा गया है।
- इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है कि संगम के जल से प्राचीन काल में राजाओं का अभिषेक होता था।
- सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में इस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन है। इसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है जहां गंगा और यमुना बहती हैं।

किसी स्थान का नाम कैसे बदला जाता है?

- सबसे पहले किसी शहर के स्थानीय लोग या जनप्रतिनिधि नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजते हैं।
- राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव पर विचार करती है और मंजूरी देने के बाद राज्यपाल की सहमति को भेजती है।
- राज्यपाल प्रस्ताव पर अनुंशसा देने के साथ अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजता है।
- गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकारए नाम बदलने की अधिसूचना जारी करती है।

पृष्ठभूमि

- पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए वर्षों से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की मांग उठती आ रही थी। मगर इस पर कभी भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।
- मार्च 2017 में योगी सरकार के उत्तर प्रदेश की सत्ता सँभालने पर उन्होंने यह वादा भी किया कि वे इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे। इसके बाद कई संतों ने इलाहाबाद को प्रयागराज करने की मांग उठाई।

स्रोतः द हिंदू

ऊर्जा मंत्री ने 'सौभाग्य' के अंतर्गत पुरस्कार योजना लांच की

चर्चा में क्यों?

☞ विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने बिजली वितरण कम्पनियों/राज्यों के विद्युत विभाग तथा उनके कर्मचारियों को संचालन क्षेत्र में 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद देने के लिए 15 अक्टूबर 2018 नई दिल्ली में सौभाग्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार योजना की घोषणा की।

मुख्य तथ्य

- यह पुरस्कार बिजली वितरण कम्पनियों डिस्कॉम/राज्यों के विद्युत विभागों के स्तर पर 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिए जाएंगे।
- सौभाग्य लांच होने के पहले 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु) ने 99 प्रतिशत से अधिक घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यह राज्य पुरस्कार योजना में शामिल होने योग्य बन गए हैं।

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे. यह श्रेणियां हैं:

- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अलावा अन्य राज्यों (बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं।

प्रत्येक तीन श्रेणियों में दो तरह के पुरस्कार होंगे

- 30 नवंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्यतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रथम डिस्कॉम/विद्युत विभाग को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि डिस्कॉम/विद्युत विभाग के कर्मचारियों में बांटने का तौर-तरीका राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) तय करेंग।
- इसमें से 20 लाख रुपये अधिक संख्या में घरों में विद्युतीकरण करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभाग के प्रभाग को दिए जाएंगे। राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) द्वारा नामित डिस्कॉम/विद्युत विभाग के पांच कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये कर्मचारी प्रबंध निदेशक से लेकर नीचे के लाईन मैन तक हो सकते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- दूसरी श्रेणी के पुरस्कार में 100 करोड़ रुपये संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग को वितरण अवसंरचना विकास में अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) इस राशि से किए जाने वाले कार्य के बारे में निर्णय लेंगे।
- 31 दिसंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभाग को राज्यों के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) द्वारा नामित पांच कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

सौभाग्य योजना:

☞ केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था। इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है।

स्रोतः पीआईबी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2018

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 13 अक्टूबर 2018 को पटना में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के तत्वाधान में केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2018 की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी की।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य में मानव संसाधनों के बारे में व्यापक जानकारी के साथ-साथ जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य वित्त संकेतकों को शामिल किया गया है। सीबीएचआई वर्ष 2005 से ही हर साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को प्रकाशित कर रहा है। यह प्रोफाइल का 12वां संस्करण है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2018: मुख्य तथ्य

- नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2018 के अनुसार देश में होने वाली संक्रामक बीमारियों में सांस संबंधी बीमारियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 69 प्रतिशत है और इनके कारण होने वाली मौतों की संख्या भी सबसे अधिक 23 प्रतिशत है।
- प्रोफाइल बयान करता है कि डायरिया के कारण होने वाली कुल मौतों में इसका योगदान 10 प्रतिशत का है।
- स्वाइन फ्लू देश में संक्रामक रोगों के कारण होने वाली मौतों की बड़ी वजह है। इसके कारण 16 प्रतिशत लोगों की जान जा रही है।
- एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम 7 प्रतिशत मौतौं की वजह बन रहा है तो एंसेफेलाइटिस चार प्रतिशत की।
- इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस चार प्रतिशत मौतों की वजह बन रहा है जबकि अन्य संक्रामक रोगों के कारण नौ प्रतिशत मौतें हो रही हैं।
- नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2018 के अनुसार पिछले कुछ सालों में सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी हो रही है और अब यह कुल जीडीपी का 1.28 प्रतिशत हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा सरकारी ऐलोपैथिक डॉक्टर यूपी में हैं।

उद्देश्य

- नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 (एनएचआरआर) परियोजना के प्रमुख अपेक्षित परिणाम निजी डॉक्टरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, कैमिस्टों और नैदानिक प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य संसाधनों के बारे में व्यापक आंकड़े उपलब्ध कराना और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ सबूत आधारित निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी स्थापित करना है।
- एनएचआरआर परियोजना में अस्पतालों, डॉक्टरों, क्लिनिकों, ब्लड बैंकों, फार्मेसियों, निदान परियोगशालाओं सहित सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करना शामिल हैं।

स्रोतः पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आयुष्मान योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार जरूरी

चर्चा में क्यों?

☞ हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पहली बार लाभ प्राप्त करने के लिए 'आधार' अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस योजना के तहत दूसरी बार इलाज के लिए आधार अनिवार्य होगा।

मुख्य तथ्य

- अगर आधार नहीं है तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा चुका है।
- पहली बार (इस योजना का) लाभ उठाने के लिए व्यक्ति आधार या मतदाता पहचान पत्र जैसे कोई पहचान पत्र दिखा सकता है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इलाज के लिए भर्ती होने पर पांच लाख रुपये प्रति परिवार सलाना कवरेज प्रदान करना है।

आयुष्मान भारत योजना:

- आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे 23 सितंबर को झारखंड से अखिल भारतीय स्तर पर लांच किया। इस योजना के तहत सरकार ने सभी परिवारों को 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज देने का लक्ष्य रखा है।
- इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम के तौर पर पेश किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना से करीब 50 करोड़ भारतीय लाभान्वित होंगे। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 445 जिले के लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियों को रखा गया है। नवीनतम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के हिसाब से गांवों के ऐसे 8.03 करोड़ और शहरों के 2.33 परिवारों को शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुताबिक गरीबों के लिए सरकारी से लेकर निजी अस्पताल तक इलाज की व्यवस्था होगी जो कि पुरी तरह कैशलेस होगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सारे सरकारी इंस्टीच्यूट जुड़े हैं। ऐसे में वहां इलाज कराना और आसान होगा। केरल में इस तरह कई अस्पतालों का कायाकल्प हो चुका है।

47,000 से अधिक लोगों ने उठाया लाभ:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार योजना के शुरु होते ही 47,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में बताया गया है।
- वहीं 92,000 से अधिक गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है। इस योजना के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों 14,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना को इन पांच राज्यों ने लागू करने से इन्कार कर दिया। ये राज्य तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, केरल और पंजाब हैं। इन राज्यों का कहना है, की यह इस योजना से असंतुष्ट हैं।

इन बीमारियों का इलाज करा सकते हैं:

- आयुष्मान योजना में शामिल करीब दस हजार अस्पतालों में 13 सौ से ज्यादा बीमारियों और इससे संबंधित पैकेज को इलाज में शामिल किया गया है। जिसमें कैंसर की सर्जरी, हार्ट की बाइपास सर्जरी, आंख-दांत का ऑपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। सरकार लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी किया है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

असम स्थित माजुली द्वीप पर पहली बार रो-रो सेवा आरंभ की गई

चर्चा में क्यों?

- असम सरकार तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा संयुक्त रूप से 11 अक्टूबर 2018 से माजुली द्वीप पर रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) सेवा आरंभ की गई. यह फेरी सेवा असम में पहली बार लॉन्च की गई है।
- रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) सेवा को असम स्थित नीमती तथा माजुली द्वीप के मध्य आरंभ किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस सेवा के लिए एमवी भूपेन हजारिका को तैनात किया है।

असम की रो-रो सेवा

- इस रो-रो सुविधा के कारण लगभग 421 किलोमीटर की सड़क मार्ग की दूरी घटकर मात्र 12.7 किलोमीटर रह गई है।
- सवारी जलयान का नाम एमवी भूपेन हजारिका रखा गया है. इसकी लम्बाई 46.5 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 13.3 मीटर है।
- यह जलयान एक बार में आठ ट्रक तथा 100 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता रखता है।
- इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि नदी में चलने वाले जलयान के लिए पर्याप्त है।
- इसके दो मुख्य इंजन है जबकि दो अन्य इंजनों को आपातकाल स्थिति के लिए रिजर्व में रखा गया है।

रोल ऑन रोल ऑफ (रो-रो) सेवा क्या है?

- रो रो फेरी सेवा से तात्पर्य उस प्रकार की यात्रा सेवा से हैं जिनकी सहायता से जल मार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर आरंभ की जाने वाली यात्राएं होती हैं।
- इसमें मौजूद जलयान द्वारा ट्रक, कार जैसे वाहनों सहित मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं।

माजुली द्वीप

- एक सितंबर 2016 को माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था. इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया. इससे पहले तक ब्राजील के माराजो द्वीप के पास यह खिताब था. नीज बुक में यह भी कहा गया कि माजुली द्वीप में 1.60 लाख लोग रहते हैं।
- माजुली का जिला मुख्यालय जोरहाट शहर है जो यहाँ से 20 किमी की दूरी पर है। माजुली जाने के लिए जोरहाट से नियमित परिवहन सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- माजुली जाने के लिए फेरी लेना जरुरी है क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं है। असम की राजधानी गुवाहाटी से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है।

स्रोतः द हिंदू

भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर 2018 को हाल ही में सड़क हादसों से सम्बंधित रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में देश में सड़क हादसों के बारे में जानकारी दी गई है।
- सड़क परिवहन मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल एक लाख 47 हजार 913 मारे गए और चार लाख 70 हजार 975 लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- देश में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं और इनमें मरने वालों की संख्या लगातार दूसरे साल घटी है जो पहले साल के मुकाबले क्रमशः 3.3 और 1.9 प्रतिशत कम है।
- इस आंकड़े के अनुसार हर दिन 1273 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिममें हर दिन 405 लोगों की मौत हुई।
- इस हिसाब से देश में हर घंटे 17 लोगों को सड़क हादसों में जान गंवानी पड़ रही है।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 राज्यों में सबसे ज्यादा 65 हजार 562 सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई लेकिन सबसे ज्यादा 20 हजार 174 लोग उत्तर प्रदश में मारे गए।
- इस दौरान तमिलनाडु में मरने वालों की संख्या 16 हजार 157 रही और वह दूसरे स्थान पर रहा।
- इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 38 हजार 783 सड़क दुर्घटनाएं हुई।

राज्यवार आंकड़े

- शीर्ष 15 राज्यों में 12 हजार 264 मौतों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है जबकि 10 हजार 609 मौतों के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर है।
- इसी प्रकार 10 हजार 444 मौतों के साथ राजस्थान पांचवें स्थान पर है।
- इस क्रम में कर्नाटक में 42 हजार 542 तथा महाराष्ट्र में 35 हजार 8523 और राजस्थान में 27 हजार 112 सड़क दुर्घटनाएं हुई।
- मृतकों की संख्या के हिसाब से राजस्थान 10 हजार 177 मौतों के साथ छठे स्थान पर है बिहार पांच हजार 554 मौतों के साथ 11वें और पांच हजार 120 मौतों के साथ हरियाणा 12वें स्थान पर है।
- सूची में पंजाब चार हजार 468 मौतों के साथ 14वें तथा छत्तीसगढ चार हजार 136 घटनाओं के साथ 15वें स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश में इस दौरान 53 हजार 399, हरियाणा में 11 हजार 258 तथा तथा बिहार में आठ हजार 855 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।
- छत्तीसगढ में इस अवधि में 13 हजार 563 तथा पंजाब में छह हजार 273 घटनाएं हुई हैं।

स्रोतः पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016: विश्लेषण

☞ नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन करने वाले इस नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास जरूरी दस्तावेज हों या नहीं।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रमुख तथ्य

- यह संशोधन 'अवैध प्रवासी' की इस परिभाषा में बदलाव करते हुए कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को 'अवैध प्रवासी' नहीं माना जाएगा।
- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परिभाषा के दायरे से बाहर कर देता है।
- भारत के वर्तमान नागरिकता कानून के तहत नैसर्गिक नागरिकता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है, जब वह आवेदन से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो।
- प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष के बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें. इससे वे 'अवैध प्रवासी' की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक और असम की समस्या

- नागरिकता को लेकर असम दो धड़ों में बंटा हुआ है, इस विधेयक को लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बराक घाटी के लोगों में मतभेद है।
- बराक घाटी में ज़्यादातर लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में लोग इसके विरोध में हैं। बराक घाटी के हिंदुओं में एक बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए विस्थापितों की है और इन बांग्लाभाषियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।
- जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों (मूल असमिया) को लगता है कि यह विधेयक क्षेत्र के जातीय अनुपात को बदलने का जरिया है और इस आधार पर ये इसके विरोध में हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 31 दिसंबर, 2017 को असम के लिये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन का मसौदा जारी किया गया जिसमें दो करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम हैं।

असम आंदोलन और असम समझौता

- 1971 में पूर्वी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हिंसक युद्ध आरंभ हुआ, उस दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने असम तथा निकटवर्ती इलाकों में शरण ले ली।
- बांग्लादेश बनने के बाद काफी लोग तो लौट गये लेकिन लगभग एक लाख लोग असम में ही रह गये. इसके फलस्वरूप वर्ष 1978 में असम के छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) द्वारा व्यापक आंदोलन आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य प्रवासियों को वापिस भेजे जाने की मांग की गई।
- इसी के चलते वर्ष 1983 में विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया तथा राज्य में हिंसक झडपें हुई।
- 1983 की इस भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिये बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई तथा 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला हुआ।
- वर्ष 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिये गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
- इस समझौते का पैरा 5.8 कहता है: 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा।
- ऐसे विदेशियों को बाहर निकालने के लिये तात्कालिक एवं व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

स्रोत: द हिंदू

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए मंत्री समूह गठित

चर्चा में क्यों?

☞ 'मी टू अभियान' में महिलाओं द्वारा अनेक लोगों पर आरोप लगाये जाने के बाद सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने संबंधी कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया है।

मंत्री समूह

☞ गृह मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मंत्री समूह के अन्य सदस्यों में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को शामिल किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मंत्री समूह के अध्यक्ष होंगे।

मंत्री समूह के कार्य

- मंत्री समूह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करके इन्हें अधिक मजबूत तथा प्रभावशाली बनाने के लिए तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
- मंत्री समूह कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मौजूदा कानूनों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में सिफारिश करेगा।
- अभी महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम प्रमुख कानून है. इसकी समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अन्य घोषणाएं

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रानिक शिकायत बॉक्स (शी बॉक्स) बनाया है जिसमें महिलाएं कार्यस्थल पर यौन शोषण के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- इस शिकायत को तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाता है जिससे कि इस पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।
- इस शिकायत पर सुनवाई की नियमित निगरानी की भी व्यवस्था की गयी है।

मी टू अभियान

- मी टू आंदोलन (#MeToo) यौन उत्पीड़न और हमले के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। अक्तूबर, 2017 में हॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में शामिल हार्वी वाइनस्टीन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए थे और वाइनस्टीन पर आरोप लगने के बाद दुनिया भर में रुडम ज्वव आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें यौन उत्पीड़न के खिफ्लाफ प्रदर्शन भी हुए थे। मी टू (#MeTooIndia) को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु एसपीजी गठित

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार ने 08 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों के मामले में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए सामरिक नीति समूह-एसपीजी का गठन किया है।

मुख्य तथ्य

- रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के साथ ही देश के सुरक्षा मामलों की दीर्घकालिक रणनीतिक समीक्षा समेत दूसरे कार्य करेगा।
- गृह मंत्रालय के सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि एसपीजी की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिव, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव और रक्षा सचिव इसके सदस्य होंगे।
- इनके अलावा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और मंत्रिमंडल के सचिव भी इस समूह में शामिल होंगे।
- राजस्व विभाग के सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव भी इस समूह के सदस्य होंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जब भी जरूरत होगी तो दूसरे मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी):

- रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) का गठन अप्रैल 1999 में किया गया था. तब सरकार ने इसका चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी को नियुक्त किया था।
- लेकिन सरकार ने 11 सितंबर 2018 को एक फैसले में एसपीजी का प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी के बजाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बनाने का फैसला किया।
- एसपीजी का गठन बाहरी, आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की मदद के लिए किया गया था। वो एसपीजी की बैठकों का संयोजन करेंगे, जबकि कैबिनेट सचिव फैसलों पर अमल को लेकर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।
- केंद्र सरकार ने एसपीजी के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 18 करने का भी फैसला किया है। इसमें 2 अतिरिक्त नए सदस्यों के तौर पर कैबिनेट सेक्रेटरी और नीति आयोग के चेयरमैन को शामिल किया गया है।

एसपीजी के अन्य सदस्य:

☞ एसपीजी के अन्य सदस्यों में आर्मी चीफ, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, RBI गवर्नर, विदेश मंत्रालय के सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव, राजस्व सचिव, एटॉमिक एनर्जी सचिव, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव, डिफेंस मिनिस्टरी के विभिन्न वैज्ञानिक सलाहकार और इंटेलीजेंस ब्यूरो के चीफ शामिल होते हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने #MeToo पर जांच समिति गठित की

चर्चा में क्यों?

☞ महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने #MeToo के तहत आए मामलों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है। वरिष्ठ न्यायविद् और कानून के पेशे से जुड़े लोग इसके मेंबर होंगे और सारे मामलों की जांच करेंग।

☞ देश भर में #MeToo कैंपेन के तहत आ रहीं यौन शोषण की शिकायतों के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

मुख्य तथ्य:

- गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और सिनेमा जगत की कई हस्तियों के खिलाफ #MeToo के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतें आई हैं। मेनका गांधी ने इन शिकायतों की जांच के लिए कमेटी की घोषणा की है।
- मंत्रालय के मुताबिक अगले एक या दो दिनों में कमेटी का गठन हो जाएगा, इसके बाद सभी संबंधित पक्ष आकर अपनी शिकायतें यहां रख सकते हैं।
- ये कमेटी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के मौजूद कानूनी पहलुओं और फ्रेमवर्क का अध्ययन करेगी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सलाह देगी कि इन्हें और भी कैसे मजबूत किया जा सके।
- मेनका गांधी ने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सामने आकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
- केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि चार सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक समिति रुडमज्वव अभियान से जुड़े मामलों की जनसुनवाई करेगी। वरिष्ठ न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों वाली यह प्रस्तावित समिति इस अभियान से जुड़े सभी पक्षों पर विचार करेगी।

विश्व में किस महिला ने शुरू किया था '#MeToo' मूवमेंट?

☞ 'रुडमज्वव' मूवमेंट की शुरुआत अमेरिकी महिला तराना बर्क ने यौन शोषण पीड़िताओं की सहायता के लिए वर्ष 2006 में की थी. दरअसल, वर्ष 1997 में 13 वर्षीय पीड़िता से बातचीत में बर्क ने कहा था की "MeToo (मेरे साथ भी हुआ)". इसकी चर्चा पिछले साल मिली जब ऐक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने 'MeToo' ट्वीट कर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई.

स्रोतः द हिंदू

निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी

चर्चा में क्यों?

☞ संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निजीकरण के मानवाधिकारों पर प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं का व्यापक रूप से निजीकरण मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है और गरीबी में रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिये पर ले जा रहा है।

☞ संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता फिलिप एल्स्टन ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की. इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र तेजी से या पूरी तरह से सरकार द्वारा की गई गतिविधियों के लिये परंपरागत रूप से जिम्मेदार होता है, जिसमें मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये जाते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

निजीकरण और मानवाधिकार

- निजीकरण उन मान्यताओं पर आधारित है जो कि मूलभूत रूप से उन लोगों से अलग है जो गरिमा और समानता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- निजीकरण का सर्वोपरि उद्देश्य लाभ है और समानता तथा गैर-भेदभाव जैसे विचारों को का इसमें कोई स्थान नहीं हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया कि निजीकरण मानव अधिकारों के लिये शायद ही कभी हितकर रहा है।
- कम आय वाले लोग विभिन्न तरीकों से निजीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली का निजीकरण किया गया है, इसलिये गरीबों पर कई अलग-अलग शुल्क और जुर्माना लगाया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप अक्सर गरीबों को एक नए और वित्तीय रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग विभिन्न शुल्कों का भुगतान नहीं कर पाते हैं इसलिये जल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते है।

टिप्पणी

- भारत में भी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। नीति आयोग ने भी कुछ योजनाओं को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चलाए जाने की घोषणा की है। नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित जिला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी निजीकरण तथा मानवाधिकारों की इस रिपोर्ट के बाद नीति आयोग को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने में सहायता प्राप्त होगी।

स्रोतः द हिंदू

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन नियमन, 2018 अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

- भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा 22 अक्टूबर 2018 को दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड नियमन, 2018 अधिसूचित किये गये हैं। जारी किए गए नियमन 22 अक्टूबर 2018 से ही प्रभावी हो चुके हैं।
- संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अधीनस्थ कानूनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आईबीबीआई में एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ व्यवस्था हो जिसमें नियम-कायदे बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ कारगर संवाद करना भी शामिल है।

मुख्य बिंदु

- संहिता की धारा 196 (1) के तहत आईबीबीआई के लिए यह आवश्यक है कि वह नियमन की अधिसूचना से पहले नियम-कायदे जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था को निर्दिष्ट करे, जिसमें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन करना भी शामिल है।
- इस अवधारणा और वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए हैं, ताकि नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके।
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है। इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को नियमन बनाने का अधिकार दिया गया है।
- इसके तहत इन शर्तों का पालन करना होगा : (क) संहिता के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना होगा, (ख) ये संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे, (ग) इन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बनाना होगा। इन्हें जल्द से जल्द संसद के हर सदन में 30 दिनों के लिए प्रस्तुत करना होगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नियमन जारी करने की प्रक्रिया

- आईबीबीआई आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए उन्हें कम से कम 21 दिन का समय देगा। यह आम जनता से प्राप्त सुझावों पर गौर करेगा और इन सुझावों पर अपनी सामान्य प्रक्रिया के साथ उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- नियम-कायदों की अधिसूचना जारी करने की तिथि से पहले ही यह काम आईबीबीआई को पूरा करना होगा. यदि संचालन बोर्ड प्रस्तावित नियमनों के बिल्कुल विपरीत रूप में इन्हें मंजूरी देने का निर्णय लेता है, तो उसे नियमन जारी करने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी।
- संचालन बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन नियमनों को तुरंत अधिसूचित करना होगा और आम तौर पर अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 दिनों के बाद उन्हें लागू किया जायेगा, बशर्ते कि इनके कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई तिथि निर्दिष्ट न की गई हो।

स्रोतः पीआईबी

सतत विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए संचालन समिति गठित

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सतत विकास कार्यक्रमों (एसडीजी) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।
- उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव करेंगे। समिति में आंकड़ा स्रोत मंत्रालयों और नीति आयोग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष आमंत्रित होंगे। इसका कार्य समय-समय पर संकेतकों में सुधार सहित राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की समीक्षा करना होगा।

उद्देश्य

- यह समिति राष्ट्रीय सूचकांक फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी और इन सूचकांकों को और बेहतर बनायेगी।
- समिति सतत विकास के लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय नीतियों ,कार्यक्रमों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा करेगी।
- समिति सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाये गए कार्यों की रिपोर्ट भी पेश करेगी जिसके आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जायेगा और कार्यों की प्रगति को बढ़ाया जायेगा।
- डाटा स्रोत मंत्रालय और विभाग विकास सूचकांक की जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय को देंगे. कारगर निगरानी के लिए विकसित आई टी उपकरणों का इस्तेमाल होगा।

सतत विकास लक्ष्य

- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर वर्ष 2000 में हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी आठ उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के नाम से जाना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया। 01 जनवरी, 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। हालांकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, एसडीजी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में और इसमें अगले 15 वर्षों के दौरान देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने की संभावनाएं है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महिला सुरक्षा सेवा 'वोडाफोन सखी' की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

☞ भारत में अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन-आइडिया ने महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित सेवा 'वोडाफोन सखी' की शुरुआत की। कंपनी का कहना हे कि वोडाफोन के नंबर का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं मुफ्त में इस सेवा का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस पहल के माध्यम से उन्हें कुछ विशेष सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

☞ प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु ने इस सेवा की शुरुआत करते हुए 'अब रूके क्यूं' अभियान का उद्घाटन किया। यह सेवा फीचर और स्मार्ट दोनों तरह के फोन पर निशुल्क उपलब्ध होगी।

'वोडाफोन सखी' की विशेषताएं

- इस सेवा के तहत संकट के समय में महिलाएं बिना इंटरनेट और बैलेंस के भी दस लोगों को अलर्ट भेज सकेंगी।
- अलर्ट के साथ महिला का लोकेशन भी संबद्ध लोगों को मिल जाएगा।
- इसके लिए उन्हें केवल एक नंबर 5500 पर कॉल करना होगा।
- इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में फोन में बैलेंस नहीं रहने पर भी वे दस मिनट तक बात कर सकेंगी।
- रिचार्ज करने के लिए महिलाओं को खुदरा दुकानों पर अपना मोबाइल नंबर बताने की जरूरत नहीं होगी।
- सखी सेवा को अपनाने वाली महिलाओं को 10 अंकों का एक प्रॉक्सी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए वे अपना रिचार्ज करा पाएंगी।
- वोडाफोन नंबर इस्तेमाल कर रही महिला उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800123100 पर फोन करके इस सेवा को शुरू करा सकती हैं।

वोडाफोन सखी की आवश्यकता क्यों?

☞ वोडाफोन द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारत में एक बिलियन से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं और देश की आधी से अधिक आबादी महिलाओं की आबादी है। फिर भी देश में 18 फीसद से भी कम महिला सब्सक्राइबर हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर महिलाएं फीचर फोन या बेसिक मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करती हैं. मोबाइल फोन के इस्तेमाल में यही अंतराल महिला सशक्तीकरण के आड़े आता है जिसे इस पहल से कम किये जाने की कोशिश की गई है।

स्रोतः द हिंदू

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर

चर्चा में क्यों?

☞ विश्वस्तर पर 11 अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया. इस दिवस को पहली बार साल 2012 में मनाया गया था।

☞ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को बढ़ावा देने के लिए इस दिन अलग-अलग देशों में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं जिसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा, पोषण, उनके कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल के प्रति उन्हें और समाजजनों को जागरूक किया जाता है।

उद्देश्यः

- इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है।
- इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि समाज में जागरूकता लाकर लड़कियों को वे समान अधिकार दिलाए जा सकें, जो कि लड़कों को दिए गए हैं।
- वर्ष 2018 के लिए इस दिवस का विषय- विथ हरः अ स्किल्ड गर्लफोर्स (With Her % A Skilled Girl Force) को निर्धारित किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

बालिकाओं हेतु उच्च गुणवत्ता की शिक्षा:

- बालिकाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में निवेश कर इन तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जाए जिससे रोजगार के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। सभी क्षेत्रों में लिंग उत्तरदायी कानून और नीतियों को बढ़ावा दिया जाए। विशेष रूप से विकलांग कमजोर, उपेक्षित, तस्करी और यौन शोषण की शिकार बालिकाओं के लिए।
- इसके अतिरिक्त किशोरावस्था में आवश्यक पोषण तत्वों में निवेश किया जाए और उन्हें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए। शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा के खिलाफ सहनशीलता समाप्त करना। बाल विवाह और जननांग विकृति को खत्म करने के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और नीति तंत्र को विकसित किया जाए।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव संख्या 66/170 को पारित किया. इस मंजूरी के साथ प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की गई। पहले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय बाल विवाह की समाप्ति रहा है।
- यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह बांग्लादेश में होते हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत:

- बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुआ था। पहला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस विश्वभर में 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया।

धनलक्ष्मी योजना:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'धनलक्ष्मी' नाम से एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बालिका शिशु के परिवार को नकद हस्तांतरण के द्वारा मूलभूत जरुरतों जैसे असंक्रमीकरण, जन्म पंजीकरण, स्कूल में नामांकन और कक्षा 8 तक के रखरखाव को पूरा किया जाता है. शिक्षा का अधिकार कानून ने बालिका शिशु के लिये मुफ्त और जरुरी शिक्षा उपलब्ध कराया गया है।
- किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार की सहायता से लागू किया गया है। यह किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (एआरएसएच) के माध्यम से किशोरियों को सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम एवं मासिक धर्म स्वच्छता के संवर्धन के लिए योजना है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

भारत और रूस के मध्य एस-400 मिसाइल सिस्टम सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

☞ अमेरिकी प्रशासन की ओर से प्रतिबंध की चेतावनी के बावजूद भारत और रूस ने 05 अक्टूबर 2018 को एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त रूस और भारत के बीच अंतरिक्ष में सहयोग हेतु एक समझौते पर दस्तखत किए गए।

☞ अंतरिक्ष सहयोग में हुए समझौते के तहत, रूस के साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क में भारत एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ती के दौरान इस समझौते पर मुहर लगाई गई। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत के गगनयान मिशन में सहायता दिए जाने का भी भरोसा जताया है।

भारत और रूस के मध्य हस्ताक्षरित 8 समझौते

- भारत के विदेश मंत्रालय और एमईए के मध्य 2019-2023 की अवधि के लिए परामर्श प्रोटोकॉल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन।
- रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन।
- मानव अंतरिक्ष अभियान हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी 'रोस्कोमोस' के बीच समझौता ज्ञापन।
- भारतीय और रूसी रेलवे मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन।
- परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना।
- परिवहन शिक्षा में विकास सहयोग हेतु रूसी परिवहन मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा रूसी लघु और मध्यम व्यापार निगम (आरएसएमबी) के मध्य समझौता ज्ञापन।
- रूसी प्रत्यक्ष निवेश निधि (आरडीआईएफ); पीजेएससी फोसाग्रो (फॉसएग्रो) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के मध्य उर्वरक क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने हेतु समझौता।

पुतिन-मोदी का संयुक्त संबोधन

- समझौते के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस की मैत्री अद्वितीय रही है।
- पुतिन ने कहा कि पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और इस वर्ष अब तक 20% वृद्धि देखी गई है।
- पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस की रेलवे कंपनी भारत में अत्याधुनिक रेलवे ट्रैक का निर्माण करेगी।
- रूस भारत को पहले मानव अंतरिक्ष अभियान में सहायता प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त, पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस अगले 20 वर्षों में भारत में 12 परमाणु संयंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा।
- पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में होने वाले व्लादिवोस्तक आर्थिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत के लिए एस-400 प्रणाली का महत्व

☞ भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीदना चाहता है। भारत-चीन की लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा के लिए यह महत्वपूर्ण है। चीन के पास पहले से ही एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसकी आपूर्ति उसे आरंभ भी हो चुकी है। हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौतों से रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, ऊर्जा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोतः द हिंदू

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का चुनाव जीता

चर्चा में क्यों?

☞ भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का चुनाव जीत लिया है। एशिया-प्रशांत श्रेणी में भारत को 188 देशों का समर्थन मिला।

मुख्य तथ्य

- इस जीत के साथ भारत को 12 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार परिषद का तीन साल के लिए सदस्य चुन लिया गया है। भारत का कार्यकाल 01 जनवरी 2019 से शुरू होगा।
- भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र श्रेणी में था। 18 नए सदस्यों में भारत को सबसे ज्यादा 188 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा में मानवाधिकार परिषद के नए सदस्यों को चुना गया।
- 18 नए सदस्यों को गुप्त मतदान द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर चुना गया। परिषद में चुने जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र से मानवाधिकार परिषद में कुल पांच सीटें हैं जिनके लिए भारत के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपीन ने अपना नामांकन भरा था।
- भारत पहले भी 2011-2014 और 2014 से 2017 दो बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है। भारत का अंतिम कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुआ था। यूएन के नियमानुसार, लगातार दो कार्यकाल के तुरंत बाद कोई देश तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता।

यूएनएचआरसी में कुल सदस्य देशः

- यूएनएचआरसी में कुल 47 निर्वाचित सदस्य देश हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सदस्यों को पांच क्षेत्रीय समूहों में बांटा गया है।
- अफ्रीकन स्टेट्स में 13 सदस्य, एशिया-पसिफिक में 13 सदस्य, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में 6 सदस्य, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स में 8-8 सदस्य, जबकि वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य स्टेट्स के लिए 7 सीटें निर्धारित हैं।
- चुनाव के बाद अफ्रीका क्षेत्र के नए सदस्य बुर्किना फासो, कैमरून, इरिट्रिया, सोमालिया और टोगो बने हैं।
- ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक ने जीत दर्ज की। लैटिन अमेरिका और कैरेबिया क्षेत्र में अर्जेंटीना, बहामास और उरुग्वे शामिल हैं। वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य राज्यों की कैटेगिरी में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली नए सदस्य बने है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है एवं उनको बढ़ावा देता है। यह मानवीय गरिमा के सार्वभौमिक आदर्शों के लिए दुनिया की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च 2006 को एक नई मानवाधिकार परिषद् के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है।
- यूएनएचआरसी, महासभा परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के योगदान और प्रतिबद्धता को देखता हैं। इसके प्रत्येक सीट की अवधि तीन वर्ष होती है। मानवाधिकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानव अधिकार अधिकारी होते हैं। यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित हैं।

स्रोत: द हिंदू

भारत और चीन ने पहली बार सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- भारत और चीन ने 22 अक्टूबर 2018 को आतंकवाद से मिलकर निपटने पर सहमति जताते हुए एक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत और चीन के बीच पहली बार सुरक्षा सहयोग पर समझौता हुआ।
- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीन के स्टेट काउंसिलर एवं सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ केझी के साथ भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चीनी मंत्री 21 से 25 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं।

समझौता का उद्देश्य:

☞ इस समझौता का मकसद आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीली पदार्थों पर लगाम और ऐसे अन्य क्षेत्रों पर चर्चा, सहयोग करना और इन पर लगाम लगाना है।

मुख्य तथ्य

- बैठक के दौरान भारत और चीन ने आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें सबसे पहले द्विपक्षीय आतंकवाद मुद्दे पर वार्ता हुई। दोनों ही देशों ने भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में हुए समझौते का स्वागत किया।
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का मुद्दा भी उठाया। भारत ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियो की सूची में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव किया है लेकिन चीन बार बार इसका विरोध करता रहा है।
- दोनों मंत्रियों ने सुरक्षा सहयोग को और बढाने के समझौते पर हस्ताक्षर किये। इससे आतंकवाद से निपटने , संगठित अपराधों , मादक पदार्थ नियंत्रण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढेगा। कुछ साल पहले सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कुछ साल पहले उसकी वैधता खत्म हो गई थी।
- वार्ता के दौरान भारत ने चीन से कहा कि वह पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने में सहयोग करे. चीन हर बार इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में भारत के आवेदन पर वीटो कर देता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और चीन के बीच सहमति:

- भारत और चीन के बीच मानव और ड्रग्स तस्करी, साइबर क्राइम, वित्तीय अपराध पर चर्चा हुई, जबकि अलग-अलग एजेंसियों से सहयोग पर भी समझौते हुए हैं।
- भारत और चीन ने आतंक को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इस पर काम करने को लेकर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर काबू पाने सहित सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
- भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लीबरेशन आर्मी के बीच दो महीने तक भारत-भूटान और चीन के तिहरे जंक्शन डोकलाम में चले गतिरोध के एक साल बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू, पीआईबी

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018: भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट-2018 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफी भुखमरी मौजूद है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018 में कुल 119 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 103वें पायदान पर है।
- भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 106वें स्थान पर मौजूद है जबकि भारत पिछले वर्ष 100वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 68 मिलियन लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018 के प्रमुख तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है।
- वर्ष 1999-2001 में कुपोषित बच्चों की संख्या 17.6% थी, जबकि वर्ष 2015-17 में यह कम होकर 12.3% पर पहुँच गयी है।
- 1999-2001 में बच्चों की ग्रोथ का आंकड़ा 37.1% था, जबकि 2013-17 में यह कम होकर 27.9% पर पहुँच गया।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस टॉप पर है जबकि चीन 25वें, बांग्लादेश 86वें, नेपाल को 72वें, श्रीलंका को 67वें और म्यांमार को 68वें स्थान पर है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक के अनुसार जिम्बाब्वे तथा सोमालिया में कुपोषण दर सबसे अधिक 46.6 से 61.8% है।
- बच्चों की वृद्धि दर सबसे कम तिमोर-लेस्ते,इरीट्रिया तथा बुरुंडी में दर्ज की गई है।
- भूख के कारण चाड, हैती, मेडागास्कर, सिएरा लिओन, यमन तथा जाम्बिया में हिंसक हालात बताए गये हैं।

पिछले वर्षों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत

- वर्ष 2014 के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2014 में भारत जहां 55वें पायदान पर था, तो वहीं 2015 में 80वें, 2016 में 97वें और पिछले साल 100वें पायदान पर आ गया। वर्ष 2018 की रैंकिंग में भारत पिछले वर्ष की तुलना में तीन पायदान और गिरकर 103वें स्थान पर आ गया है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व के विभिन्न देशों में खानपान की स्थिति का विस्तृत ब्योरा दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें कमियां क्या हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में यह रिपोर्ट जारी की जाती है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी, वेल्ट हंगरलाइफ नाम के एक जर्मन संस्था ने 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था, 2018 में उसकी रिपोर्ट 13वां एडिशन है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर पहली त्रिपक्षीय बैठक की

चर्चा में क्यों?

☞ भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने 23 अक्टूबर 2018 को चाबहार बंदरगाह परियोजना पर पहली त्रिपक्षीय बैठक की। इसमें परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

☞ इस बैठक की महत्ता इस वजह से अधिक है क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह बंदरगाह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ रहा है।

पहली त्रिपक्षीय बैठक से संबंधित मुख्य तथ्य:

❑ चाबहार बंदरगाह के जरिये अंतरराष्ट्रीय पारगमन और परिवहन के लिए त्रिपक्षीय समझौते के पूर्ण संचालन के लिए तीनों पक्षों ने विस्तृत विचार-विमर्श किया।

❑ भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने मई 2016 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल से तीनों देशों के बीच पारगमन और परिवहन कॉरीडोर बनाने की बात कही गई थी।

❑ बैठक में एक फॉलोअप कमेटी गठित करने का भी फैसला किया गया जिसकी पहली बैठक चाबहार बंदरगाह में दो महीने के भीतर होगी।

❑ त्रिपक्षीय चाबहार पहल का पूरी तरह परिचालन शुरू होने से अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा।

50 करोड़ डॉलर का निवेश:

❑ भारत चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए 50 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है, जिससे देश को अफगानिस्तान तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी. अभी अफगानिस्तान जाने के लिए सड़क मार्ग से रास्ता पाकिस्तान होकर गुजरता है।

❑ भारत ने पिछले साल चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को सहायता के रूप में 11 लाख टन गेहूं भेजा था. भारत ने चाबहार से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग के निर्माण के लिए सहायता दी थी।

चाबहार बंदरगाह का विकास:

☞ अमेरिका-ईरान सबंधों में अनिश्चितता के मद्देनजर भारत ने चाबहार में विकास कार्यों की गति धीमी कर रखी है। भारत के लिये यह एक अच्छी बात है कि ईरान रणनीतिक कारणों से यह चाहता था कि चाबहार बंदरगाह का विकास भारत ही करे। इसीलिये पहले उसने यह परियोजना भारत को देते समय चीन का दबाव पूरी तरह दरकिनार कर दिया था। हालाँकि अब तक भारत की इस परियोजना को विकसित करने की धीमी गति उसके लिये परेशानी और चिंता का सबब बनती दिख रही है।

भारत हेतु चाबहार का महत्त्व:

❑ भारत और ईरान दोनों ही देशों के लिए चाबहार परियोजना का बहुत महत्व है। यह ओमान सागर में अवस्थित यह बंदरगाह प्रांत की राजधानी जाहेदान से 645 किलोमीटर दूर है और मध्य एशिया व अफगानिस्तान को सिस्तान-बलूचिस्तान से जोड़ने वाला एक मात्र बंदरगाह है।

❑ चाबहार भारत के लिये अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है। यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ जगह है। भारत वर्ष 2003 से इस बंदरगाह के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है।

❑ चाबहार गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है और यह जमीन के साथ मुख्य भू-भाग से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ सामान उतारने-चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता। चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिये एक और रास्ता मिल जाएगा। विदित हो कि अभी तक पाकिस्तान के रास्ते भारत-अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चाबहार के बारे में:

- चाबहार ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह एक मुक्त बन्दरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। इस नगर के अधिकांश लोग बलूच हैं और बलूची भाषा बोलते हैं। यहाँ मौसम सामान्य रहता है और हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री रास्तों तक भी यहाँ से पहुँच बहुत आसान है।
- भारत ने मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा और इस स्थान तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी।

स्रोत: द हिंदू , इंडियन एक्सप्रेस

भारत और बांग्लादेश के बीच जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

☞ भारत और बांग्लादेश ने 25 अक्टूबर 2018 को व्यापार और जहाजों के आवागमन के लिए दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।

समझौतों के मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोन्गला गोदियों को भारत से आने वाले और भारत को भेजे जाने वाले सामान के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसके अलावा यात्रियों के आने-जाने और नौवहन सेवाओं के लिए भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- इस प्रक्रिया के लिए तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- नदी रास्ते नौवहन सेवाएं कोलकाता-ढाका-गुवाहाटी-जोरहट के बीच शुरू की जाएगी।
- इस बात पर भी सहमति हुई कि एक संयुक्त तकनीकी समिति अरिचा तक ढुलियान-राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी।

अन्य प्रमुख तथ्य

☞ इसके अलावा भगीरथी नदी पर जांगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने संबंधी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा. दोनों पक्षों ने जोगीघोपा के विकास के प्रति भी सहमति व्यक्त की. इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और भूटान के लिए सामान के आवागमन के संबंध में टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है.

भारत-बांग्लादेश संबंध

☞ भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं। बांग्लादेश का उदय 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। इससे पूर्व इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था तथा 1947 में भारत विभाजन के दौरान यह अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत एवं जापान ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

☞ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की 29 अक्टूबर 2018 को हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों के बीच टू प्लस टू वार्ता करने पर सहमति जताई गई।

☞ शिखर वार्ता में दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के हालात सहित विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के बाद कहा, हम दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि डिजिटल साझेदारी से लेकर साइबर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्र से अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में हम अपनी भागीदारी को मजबूत करेंगे।

भारत-जापान शिखर वार्ता के मुख्य बिंदु

- भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था का समझौता किया।
- भारत और जापान के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ओडीए ऋण की दूसरी किश्त पर समझौता हुआ।
- इसके अलावा आयुष्मान भारत से सम्बंधित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंकरण तथा नौसेनिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते किये गये।
- भारत के आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी) मंत्रालय और कनागावा प्रीफैक्चरल गवर्नमैंट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे दौरान सहयोग पत्र (एम.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर हुए।
- जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति प्रदान की।
- दोनों नेताओं ने अपने औपचारिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते खतरों और उसकी वैश्विक पहुंच पर गहरी चिंता भी प्रकट की।
- जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिश का समर्थन किया।

समझौते का लाभ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जापानी समकक्ष शिंजो आबे के मध्य हुए 75 अरब डालर के करंसी स्वैप समझौते से देश के फॉरेन एक्सचेंज और कैपीटल मार्किट में स्थिरता आएगी। इस समझौते के बाद भारत जरूरत पडने पर विदेशी पूंजी के इस्तेमाल में सक्षम हो जाएगा और बाजार पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
- शिखर वार्ता के बाद जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि तीन अंतरराष्ट्रीय निर्यात तंत्रों में भारत की पूर्ण सदस्यता के बाद दोनों नेताओं ने वैश्विक अप्रसार परमाणु प्रयासों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। भारत पहले से ही आस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार व्यवस्था और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है।

स्रोतः द हिंदू, पीआईबी

भारत और ताजिकिस्तान के मध्य नौ समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान के साथ 08 अक्टूबर 2018 को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने नौ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- राष्ट्रपति कोविंद ने वार्ता के दौरान ताजिकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने की प्रशंसा की और सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद से लड़ने में मजबूत समन्वय की जरूरत पर जोर दिया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत-ताजिकिस्तान द्विपक्षीय समझौते

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों देशों की जनता के लाभ के लिए भारत-ताजिकी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा और संयोजक परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया।
- दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने आतंकवाद की बुनियादी चुनौतियों, विशेषरूप से अफगानिस्तान के संदर्भ में चर्चा की। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने कहा कि उन्हें द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और पुरानी दोस्ती पर गर्व है।
- इस अवसर पर, भारत ने ताजिकिस्तान को विकास सहायता परियोजनाओं के लिए दो करोड़ अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की।
- राष्ट्रपति कोविंद ने दुशान्बे स्थित ताजिकिस्तान विश्वविद्यालय में 'काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन: चौलेंजेस इन मॉडर्न सोसायटीज' विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया।
- इसके उपरांत राष्ट्रपति कोविंद ने मजलिसी ओली (ताजिकिस्तान की संसद के निचले सदन) के मजलिसी नामॉयन्दगोन के अध्यक्ष और ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसूलोजाडा के साथ अलग द्विपक्षीय बैठक की।

भारत-ताजिकिस्तान संबंध

- भारत और ताजिकिस्तानन के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मधुर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य उच्चत स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं।
- पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने सितंबर 2009 में ताजिकिस्तान की राजकीय यात्रा की थी।
- पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 14 से 17 अप्रैल 2013 के दौरान ताजिकिस्तान का दौरा किया था।
- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 10 से 12 सितंबर 2014 को दुशाम्बे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के लिए ताजिकिस्तान का दौरा किया।
- ताजिकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति रहमोन ने पांचवीं बार 01 से 04 सितंबर 2012 के दौरान भारत का दौरा किया।
- इससे पूर्व उन्होंने 1995, 1999, 2001 और 2006 में भारत का दौरा किया था।

स्रोत: पीआईबी

अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु संधि समाप्त करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की है कि अमेरिका रूस के साथ दशकों पुरानी इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (आईएनएफ) संधि से अलग हो जायेगा।
- डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से यह बात नेवादा में होने वाली एक रैली के लिए निकलने से पहले की. उन्होंने आरोप लगाया कि रूस संधि का उल्लंघन कर रहा है। इस संधि के तहत एक खास श्रेणी के परमाणु हथियारों को समाप्त करने की व्यवस्था है।

प्रमुख तथ्य

- यह संधि अमेरिका और यूरोप और सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका और रूस को 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है।
- इसमें सभी जमीन आधारित मिसाइलें शामिल हैं।
- मध्यम दूरी परमाणु शक्ति (आईएनएफ) संधि की अवधि अगले दो साल में खत्म होनी है।
- रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के साथ ऐतिहासिक परमाणु संधि से अलग होने का अमेरिका का कदम अकेले वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संधि का महत्व

- तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोबार्चेव और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन द्वारा 1987 में हस्ताक्षरित यह संधि 483 किलोमीटर और 5,472 किलोमीटर के बीच की दूरी और जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों के निर्माण, तैनाती और परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है।
- नाटो मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि आईएनएफ समझौता ''यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए अहम है और हम इस ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण संधि की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'' साथ ही उन्होंने रूस से अपनी नई मिसाइलों की क्षमताओं को लेकर स्पष्ट करने का आग्रह किया।

संधि से अलग होने का कारण

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जब तक दूसरे देश इसका उल्लंघन करते रहेंगे तब तक अमेरिका इस समझौते का पालन नहीं करेगा।
- इस बीच, रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के साथ ऐतिहासिक परमाणु संधि से अलग होने का अमेरिका का कदम अकेले वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है।
- ट्रंप ने कहा कि जब तक रूस और चीन हमारे पास नहीं आते और यह नहीं कहते कि उन हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमें उन हथियारों को बनाना होगा।
- अगर रूस और चीन यह कर रहे हैं, और हम समझौते का पालन कर रहे हैं तो यह अस्वीकार्य है।

आईएनएफ संधि

- इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि (आईएनएफ संधि) संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरमीडिएट-रेंज और शॉर्ट-रेंज मिसाइलों के उन्मूलन पर संधि का संक्षिप्त नाम है जो 1987 में हस्ताक्षरित की गई।
- 8 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूस के गुष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने वाशिंगटन, डीसी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए।
- इस संधि को 27 मई 1988 को संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया और 1 जून 1988 को लागू किया गया।

स्रोतः द हिंदू

अमेरिका और कनाडा के बीच नाफ्टा समझौते को लेकर सहमति बनी

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका और कनाडा के बीच नाफ्टा समझौते (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते) को लेकर सहमति बन गई। इस समझौते में मैक्सिको भी शामिल है।
- नया समझौता 'यूनाइटेड स्टेट्स-मैक्सिको-कनाडा संधि' (यूएसएमसीए) करीब 25 साल पुरानी 'उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संधि' (नाफ्टा) की जगह लेगा। अमेरिका नवंबर 2018 के अंत में कनाडा और मैक्सिको के साथ नाफ्टा समझौता की जगह नई डील पर हस्ताक्षर करेगा जिसके बाद उसे स्वीकृति के लिए अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जाएगा।

समझौता से संबंधित मुख्य तथ्यः

- यह समझौता अमेरिका कनाडा और मेक्सिको तीनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील के कारण तीनों देशों के बीच व्यापार और कर नियमों में बड़ी छूट मिलती है।
- मेक्सिको और अमेरिका के बीच अगस्त में नाफ्टा डील पर बात बन गई थी, लेकिन कनाडा इससे बाहर था।
- मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ नाफ्टा व्यापार समझौता पूरी दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक माना जाता है।
- इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समझौते में कई तरह की छूट दी गई हैं।
- समझौते के अनुसार, कनाडा अपना डेयरी बाजार अमेरिका के उत्पादकों के लिए खोलेगा जबकि अमेरिका ने ओटावा प्रांत की विवाद निपटान के प्रावधान संबंधी मांगों को छोड़ दिया।
- इस सहमति से मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नितो का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सभी पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। राष्ट्रपति एनरिक पेना नितो का कार्यकाल 01 दिसंबर 2018 को समाप्त हो रहा है।

नाफ्टा समझौता क्या है?

- उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापार समझौता है। यह समझौता वर्ष 1994 से प्रभाव में आया। इसे विश्व के सबसे बड़े और मुक्त व्यापार समझौता माना जाता है।
- ट्रेडमार्क, पेटेंट और करंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार को लेकर काफी सुगम नियम बनाए गए। इस कारण से इस व्यापार समझौते को अमेरिका के साथ कनाडा और मेक्सिको के लिए बहुत अहम माना जाता है।
- इसे उत्तर अमेरिकी आर्थिक सहयोग समझौते के द्वारा अद्यतित किया गया, जिसने प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण विनियामकों की स्थापना में सहायता की।
- इसका और अधिक अद्यतन उत्तर अमेरिकी श्रम सहयोग समझौते के रूप में किया गया, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी बेहतर कार्य स्थितियों के लिए लड़ सकते थे। नाफ्टा के कारण अमेरिका और मेक्सिको के बीच अप्रवासन में भी वृद्दि हुई है।

स्रोतः द हिंदू

ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट: पाकिस्तान सीरिया से तीन गुना ज्यादा खतरनाक

चर्चा में क्यों?

- एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार पकिस्तान विश्व में आतंकवाद फैलाने वाला सबसे खतरनाक देश है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन या तो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से उन्हें मदद मिल रही है।
- रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और अफगान तालिबान को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रटीजिक फोरसाइट ग्रुप (SFG) की साझा स्टडी में ये दावे किए गए हैं। यह रिपोर्ट अगले दशक में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए तैयार की गई है। यह आतंकवाद से निपटने के लिए नीति निर्माताओं के लिए एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

मुख्य तथ्य

- ह्यूमनिटी एट रिस्क: ग्लोबल टेरर थ्रेट इंडिकेंट नाम की स्टडी में दुनियाभर में सक्रिय 200 आतंकी समूहों का विश्लेषण किया गया।
- इससे पता चला कि आतंकी कैंपों और उनके सुरक्षित पनाहगाह वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पर है।
- पाकिस्तान के फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा और कलात (बलूचिस्तान) के अलावा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ये आतंकी पनाहगाहें हैं।
- दुनिया में आतंकवाद को पैदा करने और उसका समर्थन करने वालों में पाकिस्तान सबसे आगे है।
- अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को भी पाक से मदद मिल रही है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस लिहाज से पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां इस्लामिक स्टेट से जूझ रहे सीरिया की तुलना में ज्यादा खतरनाक पाई गई हैं।
- इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और यमन जैसे देशों से ऑपरेट हो रहे वैश्विक आतंकी समूहों की सूचना जुटाई गई है।
- यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड अथवा ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, में स्थित है। यह इंग्लैंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके साथ 39 कॉलेज संबद्ध हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में स्नातक और परास्नातक विषयों की पढाई कराई जाती हैं। इसमें 18000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से एक चौथाई विदेशी छात्र हैं।

स्रोतः द हिंदू

बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का नया कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात राहत कोष परिषद (यूनिसेफ) ने विश्व में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम (सेवन स्ट्रेटिजीज फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन) इंस्पायर (प्छैच्प्त्म्) की शुरूआत पर सहमति जताई है।

☞ एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के प्रतिनिधि इन दिनों यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाना है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक है।

मुख्य तथ्य

- एक अनुमान के मुताबिक विश्व में कम से कम एक अरब बच्चे हर साल किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना कर रहे हैं और एशिया में पिछले वर्ष 50 फीसदी बच्चों को हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ा था।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2030 तक बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है।
- यह सतत विकास के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में एक प्राथमिकता तय की गई है।
- इसे हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की दस एजेंसियों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, 15 से 19 (84 मिलियन) आयु वर्ग की प्रत्येक तीसरी लड़की को अपने पति या साथी द्वारा भावनात्मक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

INSPIRE

- यह (INSPIRE) एक सात सूत्रीय कार्यक्रम है जिसमें निम्नलिखित सूत्र शामिल किए गये हैं:
- Implementation and enforcement of laws% कानूनों का नियमित कार्यान्वयन और प्रवर्तन
- Norms and Values% मानदंड और मूल्य
- Safe environments% सुरक्षित वातावरण
- Parent and caregiver support% अभिभावक और देखभाल करने वाले का समर्थन
- Income and economic strengthening% आय और आर्थिक मजबूती
- Response and support services% प्रतिक्रिया और देखभाल करने वाली सेवाएं
- Education and life skills% शिक्षा और जीवन कौशल

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

यूनिसेफ

- यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसम्बर साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्यूयार्क में की गई थी। यूनीसेफ विश्वभर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों विशेषकरविश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, बीमारियों आदि से बचने के लिए कार्यक्रम चलाती है।
- यूनिसेफ पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करने के दौरान किसी भी तरह के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतक विचारधारा आदि आधारों पर भेदभाव नहीं करता।
- यूनिसेफ प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध कराता है।

स्रोतः द हिंदू

चीन द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- चीन द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई कि वह दक्षिणी ध्रुव में देश के पहले स्थाई हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। चीन का कहना है कि वह दक्षिणी ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेश में एयरपोर्ट बनाने में सक्षम है।
- यह हवाई अड्डा वैज्ञानिकों को साजो सामान उपलब्ध करायेगा और इससे संसाधन-संपन्न अंटार्कटिका में हवाईक्षेत्र प्रबंधन में सुधार होगा। आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

मुख्य तथ्य

- चीन की सरकारी अखबार श्साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेलीश की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य के लिये चीन का 35वां अंटार्कटिक अभियान रवाना होगा, जिसका प्रमुख कार्य हवाईअड्डे का निर्माण करना होगा।
- अंटार्कटिक में चीन निर्मित झोंगशान स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर बर्फीले क्षेत्र के पास इस हवाईअड्डा के बनने की संभावना है।
- चीनी वैज्ञानिकों ने 2009 में अंटार्कटिक में 25वें अभियान के दौरान फिक्स्ड विंग विमान के लिये चार किलोमीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी हवाईपट्टी का निर्माण किया था।
- इस अभियान से चीन अब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उन देशों की जमात में शामिल हो रहा है जिनके अंटार्कटिक में हवाईअड्डे हैं।
- यह स्थान सोना, चांदी, प्लेटिनम और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इससे पहले की आधिकारिक चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2010 में बर्फीली परत पर चीन ने फीयिंग नामक हवाईअड्डे का निर्माण किया था।

लाभ

- इस एयरपोर्ट पर मध्यम और बड़े विमान उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होंगे। इससे परिवहन समय के साथ क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का हालांकि कहना है कि अंटार्कटिक में एयरपोर्ट बनाना आसान नहीं है क्योंकि वहां की 99.5 फीसद जमीन बर्फ से ढकी है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और अजरबैजान ने व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

- भारत और अजरबैजान ने 12 अक्टूबर 2018 को व्यापार, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और अजरबैजान के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री मुख्तार बाबायेव ने 'भारत- अजरबैजान अंतर सरकारी व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियां तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग आयोग' की दो दिन तक चली पांचवीं बैठक के बाद इस समझौते के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।
- व्यापार और आर्थिक, विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी सहयोग पर भारत-अजरबैजान अंतर-सरकारी आयोग की पांचवी बैठक नई दिल्ली में 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2018 को हुई। भारत और अजरबैजान आपसी व्यापार क्षमता से काफी कम होने की बात स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं।

मुख्य तथ्य:

- दोनों देशों ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक, विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।
- दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, परिवहन, ऊर्जा तथा हाइड्रोकार्बन, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, कृषि खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य और फॉर्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध, रसायन तथा पेट्रो-रसायन और खनन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने तथा बढ़ाने पर बल दिया।

भारत और अजरबैजान के बीच कारोबार:

- भारत और अजरबैजान के बीच जनवरी-अगस्त, 2018 में 657.9 मिलियन डॉलर का कारोबार हुआ।
- दोनों देशों ने महसूस किया कि द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से काफी कम है और व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग में तेजी लाने तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ व्यापार संबंधों तथा व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने के उपाय करने पर सहमति व्यक्त की।

आर्थिक विकास:

- यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों में हो रहे आर्थिक विकास और सुधारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापार शिष्टमंडल भेजा जाएगा और व्यापार प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक आयोजनों के बारे में सूचना का नियमित आदान-प्रदान होगा।
- दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी सहयोग पर भारत-अजरबैजान अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक बाकू में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

स्रोत: पीआईबी

मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला किया

चर्चा में क्यों?

- मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है. मलेशिया के संचार और मल्टी मीडिया मंत्री गोबिंद सिंह देव ने कहा कि इस सजा के प्रति देश में भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला किया है।
- मृत्युदंड समाप्त हो जाने के बाद मलेशिया को, दूसरे देशों में मौत की सजा का सामना कर रहे मलेशियाई लोगों के जीवन के लिए संघर्ष करने का नैतिक अधिकार मिल सकेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मलेशिया में मृत्युदंड समाप्त करने की मांग:

- दरअसल दुनिया के अन्य कई देशों की तरह मलेशिया में भी मानवाधिकार समूहों और आम जनता का एक बड़ा वर्ग काफी समय से मृत्युदंड समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इस मामले में मलेशिया के मंत्रिमंडल ने हाल ही में के बैठक आयोजित की थी जिसके बाद सरकार ने देश में मृत्यु दंड की सजा को खत्म करने पर सहमति जता दी है।
- सरकार के इस फैसले के बाद से देश के मानवाधिकार समूहों और आम जनता ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद कहा है।
- लॉयर्स फॉर लिबर्टी अधिकार समूह के एक सलाहकार एन सुरेंद्रन ने एक बयान में कहा की मौत की सजा बर्बरतापूर्ण है और अकल्पनीय रूप से क्रूरतापूर्ण है।

मलेशिया में मौत की सजा:

- मलेशिया में फिलहाल हत्या, अपहरण, आग्नेयास्त्रों समेत अन्य अपराधों के लिये मौत की सजा अनिवार्य है। मलेशिया में फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत माना जा रहा था। मौत की सजा देने का यह नियम यहाँ भी ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है।

मृत्युदंड अन्य देशों में:

- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और अरब देशों के साथ दुनिया के उन चुनिंदा 52 देशों में शामिल है, जिसने अभी तक मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त नहीं किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 192 देशों में से 140 ने अपने यहां से मृत्युदंड का प्रावधान हटा दिया है। यूरोपीय संघ ने तो अपनी सदस्यता के लिए मृत्युदंड का न होना एक अनिवार्य शर्त बना दी है।

विभिन्न देशों में मृत्युदंड के तरीके

- फायरिंग, फांसी, पथराव: अफगानिस्तान, सूडान
- फायरिंग, फांसी: बांग्लादेश, केमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान, मिस्र
- केवल फांसी: भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिंबाब्वे, दक्षिण कोरिया
- फायरिंग: यमन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, थाइलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया, घाना, अर्मीनिय
- इंजेक्शन और फायरिंग: चीन

इंजेक्शन: फिलीपींस

- इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस, फांसी, फायरिंग: अमेरिका

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

भारत में 2014 से करोड़पति करदाताओं की संख्या 60 प्रतिशत बढ़ी: सीबीडीटी

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 22 अक्टूबर 2018 को बताया कि पिछले 4 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी दिखाने वालों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हुई है। बतौर सीबीडीटी, निर्धारण वर्ष 2014-15 में 1 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी दिखाने वालों की संख्या 88,649 थी जो निर्धारण वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1.4 लाख रुपये से अधिक हो गई।

मुख्य तथ्य

- आयकर विभाग की पॉलिसी मैकिंग बॉडी के अनुसार करोड़पतियों में पिछले चार साल में 68 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। उनके अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. जहां वर्ष 2014-15 में 88,649 आयकर दाताओं ने 1 करोड़ से ज्यादा की आय घोषित की वहीं वर्ष 2017-18 में यह बढ़कर 1,40,139 लाख हो गई।
- सीबीडीटी के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 68 प्रतिशत बढ़कर 48,416 से 81,344 पर पहुंच गई।
- आंकड़ों के अनुसार पिछले चार वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों का आंकड़ा भी 80 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 में यह 3.79 करोड़ था, जो 2017-18 में 6.85 करोड़ हो गया।

आईटीआर रिटर्न्स में 80 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि:

- सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि पिछले चार सालों के दौरान फाइल किए गए आईटीआर रिटर्न्स में 80 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है और यह वर्ष 2013-14 के 3.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 6.85 करोड़ हो गया है।

रिटर्न फाइल करने की समयसीमा:

- वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी):

- भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है।
- सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है. सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है।
- सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 77वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है।

मुख्य तथ्य

- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की। भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी। पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है।
- वहीं, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है. इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।
- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।
- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है. विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंगः

वर्ष	रैंकिंग
साल 2018	77वां रैंक
साल 2017	100वां रैंक
साल 2016	130वां रैंक
साल 2015	130वां रैंक
साल 2014	142वां रैंक

यह रैंकिंग कैसे तय होती है?

- भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इन छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन से भारत की रैंकिंग सुधरी:

छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन	2018-19 में रैंक	2017-18 में रैंक
बिजनेस की शुरुआत	137	156
कंस्ट्रक्शन परमिट	52	181
बिजली की उपलब्धता	24	29
कर्ज की उपलब्धता	22	29
सीमा पार कारोबार	80	146
कॉन्ट्रैक्ट में आसानी	163	164

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस :

- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।
- कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है।
- डूईंग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय किया जाता है और ये स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

स्रोत: द हिंदू , बिजनेस स्टैंडर्ड

गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 अक्टूबर 2018 को सूरत में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ऐसा ही दूसरा मेगा फूड पार्क मेहसाणा में बनाए जाने को मंजूरी दे दी है।

मुख्य तथ्य

- सूरत जिले के मंगलौर तालुका के तहत शाह और वसरावी गांव में स्थित यह पार्क मेसर्स गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
- यह मेगा फूड पार्क 70.15 एकड़ भूमि पर 117.87 करोड़ रूपए की लागत से बनाया गया है. इसमें डेवलपर द्वारा बनाए गए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में 3,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता से युक्त कई चौंबरों वाला कोल्ड स्टोर, 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयर हाउस, सब्जियों और फलों कु गूदे निकालने के लिए बड़ी पाइपलाइन, क्यूसी प्रयोगशाला और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ऐसी ही कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

उद्देश्य:

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है।
- इस पार्क के बनने से सूरत के साथ ही नवसारी, तापी, नर्मदा और भरूच के पड़ोसी जिले के लोग भी लाभान्वित होंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इसका महत्व क्या है?

- मेगा फूड पार्क की 25 से 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होने की संभावना है। इस पार्क में करीब 450 से 500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होगा। इससे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- फूड पार्क के आस-पास के इलाकों के करीब 25,000 किसान लाभन्वित होंगे. फूड पार्क की आधुनिक बुनियादी संरचना से किसान, उत्पादक और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोग तथा उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। इससे गुजरात के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
- मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएं और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) और संग्रह केंद्रों (सीसी) के रूप में कृषि के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा दी जाती है।
- सरकार भारत में उद्यम लगाने के इच्छुक निवेशकों को सहज, पारदर्शी और सुलभ कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को खाद्य क्षेत्र में एक मजबूत अर्थव्यवस्था तथा विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर खास जोर दिया है।

स्रोतः पीआईबी

एमएसएमई सेक्टर हेतु सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे देश भर में एमएसएमई के विकास और विस्तार के साथ-साथ उन्हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं:

- प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट के लोन पोर्टल का शुभारंभ करने का घोषणा किया। इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है। जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का घोषणा किया। शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की।
- पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जायेगा। इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएं हल हो जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है।
- पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित हैं। एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेढ़ लाख से अधिक आपूर्तिकर्ता अब जीईएम के साथ पंजीकृत हैं इनमें से 40 हजार एमएसएमई हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए। सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए।
- पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे।
- फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्लस्टर बनाये जायेंगे। इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।
- आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।
- अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा।
- वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। रिटर्न, स्व, प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा।
- 12वीं घोषणा के रूप में एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा:

- प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया जायेगा कि उन्हें जन-धन खाता, भविष्य निधि और बीमा उपलब्ध हो। अगले 100 दिनों के दौरान इस आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जायेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई):

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

स्रोतः द हिंदू

सरकार द्वारा स्वर्ण बॉन्ड योजना जारी

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि तय कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक हर महीने जारी की जाएगी।
- गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मनोनीत डाकघरों एवं मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई लिमिटेड के जरिए की जाएगी। योजना का पहला चरण निवेश के लिए 15 अक्टूबर को खुलेगा और 19 अक्टूबर को बंद हो जाएगा. तो वहीं बॉन्ड 23 अक्टूबर को जारी किया जाएगा।

स्वर्ण बॉन्ड योजना

- इस योजना के तहत कम से कम एक ग्राम सोना और अधिक से अधिक पाँच सौ ग्राम सोने के वजन के मूल्य के बराबर बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
- इसकी अवधि आठ वर्ष है। इसमें ब्याज की दर 2.5 प्रतिशत है।
- एक वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों और एचयूएफ के मामले में एक ग्राहक को अधिकतम चार किलोग्राम निवेश की अनुमति दी जाती है।
- ट्रस्ट और वित्तीय वर्ष के समान इकाइयों के मामले में निवेश की ऊपरी सीमा 20 किलोग्राम है।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर योग्य है। हालांकि, किसी व्यक्ति को एसजीबी (SGB) के रिडेम्पशन पर उत्पन्न पूंजीगत लाभ कर छूट दी गई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

- इस योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य भौतिक रुप से सोने की मांग में कमी लाना एवं सोने की खरीद में उपयोग होने घरेलू बचत का इस्तेमाल वित्तीय बचत में करना है।
- घर में सोना खरीद कर रखने की बजाय अगर आप सॉवरेन गोल्डल बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

भारत छह साल में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा: IATA रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

☞ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जायेगा। वर्तमान में भारत वैश्विक विमानन बाजार में सातवें स्थान पर हैं। IATA की 24 अक्टूबर 2018 को जारी अगले 20 वर्ष के पूर्वानुमान रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।

मुख्य तथ्यः

- भारत 2020 तक जर्मनी और जापान को तथा 2023 तक स्पेन को पीछे छोड़ देगा. इसके बाद वर्ष 2024 के अंत तक वह ब्रटेन को पछाड़ कर तीसरे स्थान पर पहुँच जायेगा।
- भारत में वर्तमान में घरेलु हवाई यात्रियों की संख्या में 18.28% की दर से वृद्धि हो रही है, यह संख्या वर्ष 2018-19 में 243 मिलियन तथा वर्ष 2020 में 293 मिलियन तक पहुँच जाएगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष दो स्थानों पर अमेरिका और चीन कायम रहेंगे लेकिन अगले दशक के मध्य तक अमेरिका को पछाड़कर चीन पहले स्थान पर होगा। इसमें वर्ष 2037 तक पहले तीन स्थान पर क्रमशः चीन, अमेरिका और भारत के बने रहने की बात कही गयी है, बशर्ते सरकारों की विमानन नीतियों में कोई खास बदलाव न हो।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई ट्रैफिक में वर्ष 2018 में 10.43% की वृद्धि हुई और यात्रियों की संख्या 65 मिलियन पहुँच गयी, वर्ष 2020 तक यह आंकड़ा 76 मिलियन तक पहुँच जायेगा।
- हवाई ट्रैफिक में अगले 20 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में होगी। हवाई यात्रियों की संख्या अगले 20 वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

वैश्विक विमानन बाजार

- वैश्विक विमानन बाजार में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे स्थान पर, स्पेन चौथे स्थान पर जापान पांचवे स्थान पर और जर्मनी छठे स्थान पर है।
- नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या सितम्बर 2014 से सितम्बर 2018 तक लगातार बढ़ी है।
- वर्ष 2014 में जहां कुल छह करोड़ 73 लाख 83 हजार यात्रियों ने उड़ान भरी थी, वहीं इस साल जनवरी से सितम्बर के बीच ही उनकी संख्या 10 करोड़ 27 लाख 93 हजार पर पहुंच गयी है। इस वर्ष सालाना वृद्धि दर 20.94 प्रतिशत रही है।
- आईएटीए के अनुसार वर्ष 2017 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2037 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या सालाना संख्या 57 करोड़ 20 लाख पर पहुंच जाएगी। इनमें 41 करोड़ 40 लाख नए यात्री शामिल होंगे।
- वर्ष 2037 तक दुनिया भर में हवाई यात्रियों की संख्या 10 अरब 30 करोड़ पर पहुंच जाएगी। वैश्विक विमानन बाजार 76 खरब डॉलर का होगा और इस क्षेत्र में 11 करोड़ 90 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) :

- यह अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के लिए एक व्यापार संघ है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 120 देशों के 280 अनसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स का एक समूह है।
- आईएटीए की स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। IATA का मुख्यालय कनाडा के मोंट्रियल में स्थित है।
- यह संगठन हवाई यात्रा क्षेत्र से सम्बंधित नीति तथा मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह संगठन कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्य कार्य अन्तर-वायु कंपनी मामलों में सहयोग स्थापित करना है। इसके अलावा इसका काम लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित, निश्चित, विश्वसनीय तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य वायु सेवाएं सुनिश्चित करना है।
- यह एयर-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही एयर-कॉमर्स की सभी समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी करती है।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

बिहार में तय समय से पहले ही पूरे राज्य में शत प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा

चर्चा में क्यों?

- बिहार ने अपने तय समय से दो महीने पहले ही पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम के तहत बिहार ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है।
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के सभी एक करोड़ उनचालीस लाख तिरेसट हजार नौ सो नौ घरों में बिजली पहुंच गई है।

मुख्य तथ्य

- केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके साथ ही बिहार देश के आठ राज्यों में शामिल हो गया जहां शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंची है। ये हैं आठ राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी में शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच चुकी है।
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिहार में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर 2018 तक रखा था। बिजली विभाग ने तय समय से दो महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। सौभाग्य योजना के तहत बिहार में करीब 32 लाख ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था जिसे पूरा कर लिया गया है।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 सितंबर 2017 को 'हर घर बिजली योजना' की शुरुआत की थी। इसके तहत सौभाग्य योजना लागू हुई। केन्द्र सरकार ने बाद में बिहार मॉडल अपनाया।
- पिछले दिनों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और रोहतास जिले के ही कुछ हिस्से शेष बचे थे। प्रधान सचिव और बिजली कंपनी ने खुद इसकी मानिटरिंग शुरू की और तीन दिनों में ही यहां बिजली पहुंची।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य राज्य:

☞ उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन अभी भी लगभग 88 लाख घरों में बिजली नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र में ऐसे घरों की संख्या लगभग 30 हजार से अधिक है और राजस्थान में सात लाख से भी अधिक हैं।

सौभाग्य योजना:

- केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था। इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है।
- यह योजना केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का एक हिस्सा है. सौभाग्य एक ऐसी योजना है जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा और इसमें से 25 प्रतिशत को इस परियोजना के लिए तैनात किए जाने वाले मानव संसाधन एवं उनके पारिश्रमिक पर खर्च किए जाने का अनुमान है।

स्रोत: द हिंदू

WEF इंडेक्स में भारत बना 58वां सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाला देश

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने 16 अक्टूबर 2018 को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं वाली 2018 की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूचि में भारत 58वें नंबर पर है। सूची में अमेरिका इस साल शीर्ष पर रहा वर्ष 2008 के बाद अमेरिका पहली बार नंबर-1 पर रहा है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि वर्ष 2017 के मुकाबले भारत के स्थान या रैंकिंग में पांच अंकों का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में भारत 62 अंकों के साथ 58वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में 140 देश शामिल हैं।

मुख्य तथ्य:

- विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी 140 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में अमेरिका के बाद सिंगापुर दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। वहीं, सूची में पड़ोसी देश चीन को 28वां स्थान मिला है।
- इस सूची में पहला स्थान यानी सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की जगह अमेरिका को मिली है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे है। इन क्षेत्रों में श्रीलंका भारत के मुकाबले आगे है। द्वीपीय देश में सेहतमंद जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष है और वहां के कामगारों में शिक्षा भी बेहतर है।
- विश्व आर्थिक मंच की इस सूची में शीर्ष-10 देशों में अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, हांगकांग, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं।
- इस सूची में रूस 65.6 अंकों के साथ 43वें, दक्षिण अफ्रीका 60.8 अंकों के साथ 67वें और ब्राजील 59.5 अंकों के साथ 72वें स्थान पर हैं।

इन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत:

☞ विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी लाभों में उसके बाजार का आकार, नवोन्मेष (इनोवेशन) आदि शामिल हैं। हालांकि, देश को अपने श्रम बाजार (विशेष रूप से कामगारों के अधिकारों), उत्पाद बाजार (व्यापार शुल्क) तथा कौशल खासकर छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने की जरूरत है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चीन और भारत उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के करीब:

☞ रिपोर्ट के अनुसार ऊपरी और निम्न मध्य आय वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले चीन और भारत जैसे देश उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के करीब पहुंच रहे हैं और उनमें से कई देश को पीछे भी छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश के मामले में चीन औसत उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं से काफी आगे है, जबकि भारत भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है।

विश्व आर्थिक मंच का वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक 4.0:

☞ विश्व आर्थिक मंच का वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक 4.0 किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और अन्य चीजें तय करने के लिए 12 मानदंडों को ध्यान में रखता है, जिनमें - संस्थाएं, आधारभूत संरचना, तकनीक, मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्तीय प्रणाली, बाजार का आकार, बिजनेस डायनेमिक्स और नवोन्मेष शामिल हैं।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) :

☞ विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारीयों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तर पर होती है और ये स्तर उनकी संस्था के कार्य कलापों में सहभागिता पर निर्भर करती है। सदस्यता के लिए वह कंपनी चुने जाते हैं जो विश्व भर में अपने उद्योग में अग्रणी होते हैं। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे होते हैं।

स्रोत: द हिंदू , इकोनॉमिक टाइम्स

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर

चर्चा में क्यों?

☞ विश्वभर में 17 अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्य तथ्य:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस ने 15 अक्टूबर को आयोजित वर्ष 2018 अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर वक्तव्य जारी कर सभी को गरीबी उन्मूलन के लिए विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाने की अपील की। ताकि वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में यह बताया गया है कि किसी एक विशेष कारण के चलते नहीं बल्कि विभिन्न कारणों की वजह से लोगों को गरीबी में जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- इसलिए यह आवश्यक है कि केवल आय का स्रोत एवं आमदनी ही गरीबी का कारण नहीं है बल्कि भोजन, घर, भूमि, स्वास्थ्य आदि भी गरीबी के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं।

भारत में गरीबी का मुख्य कारण

- भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर गरीब में ऊंच-नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी आदि है।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, आज देश के यही किसान गरीबी की मार झेल रही है। खराब कृषि और बेरोजगारी की वजह से लोगों को भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। यही कारण है कि महंगाई ने भी पंख फैला रखे हैं। वहीं भारत में बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में गरीबी-दर:

☞ केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में बताया कि भारत में 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। विश्व बैंक की वर्ष 2011 रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की 23.6 प्रतिशत जनसंख्या (लगभग 276 मिलियन) की प्रतिदिन क्रय शक्ति 1.25 डॉलर प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 2016 में जारी अंतरराष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक में भारत को 97वां स्थान मिला है। इसमें विकासशील देशों के लिए औसत दर 21.3 रखी गयी थी जबकि भारत की यह दर 28.5 प्रतिशत थी।

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 दिसम्बर 1992 को प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी।
- इस दिवस पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास, विकास एवं विभिन्न कार्यों व योजनाओं को जारी किया जाता है।
- यह दिवस पहली बार वर्ष 1987 में फ्रांस में मनाया गया जिसमें लगभग एक लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन एटीडी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसफ व्रेंसिकी द्वारा आरंभ किया गया।

स्रोत: द हिंदू , बिजनेस स्टैंडर्ड

विश्व आर्थिक मंच द्वारा श्फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडियाश रिपोर्ट जारी की गई

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में "फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया" रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कम्पनियां तेजी से विकास कर रही हैं वे पुरुषों को बतौर कर्मचारी रखना अधिक पसंद करती हैं।

☞ यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की ओर से आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा पर्याप्त नये अवसर तथा संभावनाएं मौजूद हैं।

फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट

- रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तिहाई कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।
- भारत में रोजगार सृजन काफी तीव्र गति से हो रहा है लेकिन देश की केवल 26 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, यह वैश्विक स्तर से काफी नीचे है।
- रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक तीन में से एक कंपनी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की काम पर रखने में प्राथमिकता देती है जबकि दस में से एक कंपनी ही महिलाओं को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता देती है।
- रिटेल सेक्टर में 45 प्रतिशत कंपनियों में कोई महिला कर्मचारी नहीं है, जबकि परिवहन और लॉजिस्टिक में 36 प्रतिशत कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी कार्यरत्त नहीं है।
- फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रीलान्स क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत पुरुष ही कार्यरत हैं।
- इस क्षेत्र में पाया गया है कि फ्रीलान्स पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक सैलरी दी जाती है. इस सर्वेक्षण यह भी पाया गया कि केवल एक चौथाई कंपनियां ही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान करती हैं।

रिपोर्ट का कार्यक्षेत्र

☞ आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस रिपोर्ट के लिए 700 सूक्ष्म आकार की कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया। इन कंपनियों में 25,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इस रिपोर्ट के लिए वस्त्र उद्योग, लोजिस्टिक्स, परिवहन तथा बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र व रिटेल कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया। इस रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी का कार्यबल पर प्रभाव का अध्ययन में किया गया, इस रिपोर्ट में सामने आया की मशीने मानव कार्यबल का स्थान ले रही हैं, इससे जॉबलेस ग्रोथ होने के आसार हैं।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

❍ भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास 'जेआईएमईएक्स 18' विशाखापत्तनम में शुरू

- भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास (जेआईएमईएक्स) 07 अक्टूबर 2018 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ।
- इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज कागा और इनाजुमा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहुंचे हैं। यह भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाजों के साथ जापान-भारत सामुद्रिक अभ्यास (जेआईएमईएक्स) के तीसरा संस्करण है।
- भारतीय युद्धपोत पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के अधीन युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।

उद्देश्य:

☞ यह युद्धाभ्यास का लक्ष्य दोनों बलों की अंतरसंचालन क्षमता बढ़ाना, सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को समझना है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास:

- कागा इजुमो श्रेणी का हेलीकॉप्टर विध्वंसक है, जबकि इनाजुमा एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ये दोनों एस्कॉर्ट फ्लौटिला-4 के कमांडर, रियर एडमिरल तातसुया फुकादा के अधीन युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।
- इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना घरेलू स्तर पर निर्मित तीन युद्धपोतों और एक बेड़ा टैंकर के साथ हिस्सा ले रही है।
- इन युद्धपोतों में बहुउद्देश्यीय टोही जहाज आईएनएस सतपुड़ा, पनडुब्बीरोधी युद्धपोत आईएनएस कदमत, मिसाइल युक्त लड़ाकू पोत और बेड़ा टैंकर आईएनएस शक्ति शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त एक पनडुब्बी, एक पी8आई लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान और कई हेलीकॉप्टर भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है।
- भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित जंगी जहाजों एवं एक फ्लीट टैंकर द्वारा किया जा रहा है।

जेआईएमईएक्स18:

- जेआईएमईएक्स18 का लक्ष्य अंत: सक्रियता बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना तथा एक-दूसरे के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को अपनाना है।
- जेआईएमईएक्स18 आठ दिनों तक चलेगा जिसमें चार-चार दिनों के हार्बर एवं समुद्री चरण शामिल होंगे।

पृष्ठभूमि:

☞ जेआईएमईएक्स का पिछला संस्करण चेन्नई में दिसंबर 2013 में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच यह दूसरा और भारतीय समुद्री सीमा में पहला अभ्यास था। दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जापान में जनवरी 2012 में हुआ था। विदित हो कि रक्षा मंत्री एके एंटनी की नवंबर, 2011 में की गई जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित करने पर सहमति हुई थी।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

☞ भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया।

☞ सामरिक बल कमान ने अभियान तैयारियों को मजबूत करने के लिए डॉ अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया। सूत्रों ने परीक्षण को सफल बताते हुए कहा कि परीक्षण के दौरान सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है।

अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल :

❑ अग्नि-1 मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। मिसाइल को रेल व सड़क दोनों प्रकार के मोबाइल लांचरों से छोड़ा जा सकता है।

❑ यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी मारक क्षमता काफी अधिक है और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मनों को तबाह कर सकती है।

❑ यह परमाणु बमों को भी गिराने में सक्षम है। अग्नि-1 में विशेष नौवहन प्रणाली लगी है जो सुनिश्चत करती है कि मिसाइल अत्यंत सटीक निशाने के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचे।

❑ 15 मीटर लंबी और 12 टन वजनी यह मिसाइल एक क्विंटल भार के पारंपरिक और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था।

❑ यह एक ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली निर्देशित मिसाइल है और यह विशेष नेविगेशन प्रणाली से युक्त है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि मिसाइल अत्यधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचे।

❑ पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल की जा चुकी इस मिसाइल ने मारक दूरी, सटीकता और घातकता के मामले में खुद को साबित किया है।

❑ अग्नि-1 को एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी (एएसएल) ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) और अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) के सहयोग से विकसित किया है।

❑ मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने समेकित किया है। एएसएल मिसाइल विकसित करने वाली डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला है।

अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल

❑ भारत ने अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का भी सफल परीक्षण कर चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा निर्मित अग्नि-5, अग्नि मिसाइल श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है।

❑ तकनीकी दृष्टि से बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या बैलिस्टिक मिसाइल (इंससपेजपब उपेपसम) उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब-आर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है।

❑ इसका उपयोग किसी हथियार (प्राय: नाभिकीय अस्त्र) को किसी पूर्वनिर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिये किया जाता है। यह मिसाइल अपने प्रक्षेपण के प्रारम्भिक चरण में ही केवल गाइड की जाती है;

❑ उसके बाद का पथ कक्षीय यांत्रिकी (या आर्बिटल मेकैनिक्स) के सिद्धान्तों एवं बैलिस्टिक्स के सिद्धान्तों से निर्धारित होता है। अभी तक इन्हें रासायनिक रॉकेट इंजनों के द्वारा प्रणोदित (प्रोपेल) किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कोचीन में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ भारत के सबसे बड़े ड्राई डॉक का निर्माण किये जाने हेतु केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में परियोजना का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया जायेगा।

☞ कोचीन शिपयार्ड में पहले से ही दो ड्राइ डॉक मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों ही इस नए बनने वाले ड्राइ डॉक से छोटे हैं। इस निर्माण के साथ ही भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में जहाज मरम्मत का हब बन कर उभरेगा।

परियोजना के मुख्य बिंदु

- ड्राइ डॉक कोची का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया जाएगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत 1799 करोड़ रुपये है।
- यह नया ड्राइ डॉक 310 मीटर लंबा व 75 मीटर चौड़ा होने के साथ ही 13 मीटर गहरा भी होगा।
- इस डॉक का उपयोग समुद्री जहाज के निर्माण व उसकी मरम्मत के लिए किया जाएगा।
- इस डॉक में एलएनजी कैरिज, ड्रिल शिप व इंडियन नैवी के विमानवाहक पोत को भी खड़ा किया किया जा सकेगा।
- इस ड्राइ डॉक के निर्माण के साथ ही वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
- वर्तमान समय में वैश्विक जहाज निर्माण कार्य में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.66 प्रतिशत की है, ऐसे में यह परियोजना देश में जहाज निर्माण व्यवसाय को नयी दिशा देगी।
- इस परियोजना के मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का मानना है कि इसके बनने से देश के जहाज निर्माण व्यवसाय में एक नया आयाम देखने को मिलेगा, साथ ही इसके तहत करीब 2 हजार लोगों को नौकरी भी मिलेंगी।

ड्राई डॉक (शुष्क गोदी)

- ड्राई डॉक (शुष्क गोदी) एक ऐसा संरचित क्षेत्र होता है जिसमें व्यापारिक जहाजों और नौकाओं के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्य किए जाते हैं।
- इसके विशेष प्रकार के निर्माण में पानी भरा जा सकता है जिसे लॉक एरिया कहा जाता है, इससे जहाज इस क्षेत्र में आ-जा सकते हैं।
- एक बार जहाज के अंदर आ जाने पर मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं तथा समुद्र के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा करने पर जहाज को लंबे समय तक यहां रखा जा सकता है तथा मरम्मत का काम किया जा सकता है।

स्रोतः द हिंदू

एमआईटी वैज्ञानिकों ने बेहद सूक्ष्म रोबोट विकसित किया

चर्चा में क्यों?

- मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अतिसूक्ष्म रोबोट विकसित किया है जिसका उपयोग आयल या गैस पाइपलाइन की निगरानी अथवा मानव शरीर में रोग के निदान में किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि इस रोबोट का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने उस तरीके की भी खोज कर ली है जिसकी सहायता से ऐसे रोबोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- इन बेहद छोटे रोबोटों का नाम 'सेनसेल्स' रखा गया है (Synthetic Cells) रखा गया है।
- वैज्ञानिकों ने इस अतिसूक्ष्म रोबोट की बाहरी संरचना के निर्माण में कार्बन तथा ग्राफीन के द्वि-विमीय प्रारूप का उपयोग किया है।
- मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक प्रोफेसर के अनुसार, यह रोबोट किसी जीवित जैविक कोशिका की तरह ही व्यवहार करता है।
- बड़ी मात्रा में ऐसे छोटे रोबोटों को बनाने का आधार परमाणु की तरह पतले, भंगुर सामग्री का प्राकृतिक रूप से टूटने (natural fracturing) की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निहित है।
- वैज्ञानिक 'स्वत: छिद्रण' के माध्यम से 'फ्रैक्चर लाइनों' को सीधे निर्देशित करते हैं ताकि वे अनुमानित आकार और आकृति के कम-से-कम पॉकेट उत्पन्न कर सकें।
- इन पॉकेट्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सामग्रियों के साथ रोबोट जुड़े होते हैं जो आँकड़ों को एकत्रित तथा संगृहीत कर सकते हैं।

खोज के लाभ

- यह रोबोट तेल और गैस पाइपलाइन के अंदर की स्थिति की निगरानी करने तथा रक्त के साथ प्रवाहित होते हुए मानव शरीर में रोगों का निदान करने में सक्षम हैं।
- इन रोबोटों के उत्पादन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कई अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है।
- यह बिना किसी बाहरी सहायता के आँकड़ों को जुटाने में सक्षम है।

स्रोत: द हिंदू

भारत ने इजराइल के साथ 77.7 करोड़ रुपये की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- भारत ने रूस के बाद इजराइल के साथ रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इसके तहत इजराइल की प्रमुख सरकारी रक्षा कंपनी ने 24 अक्टूबर 2018 को भारतीय नौसेना के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।
- इस समझौते के तहत इजरायल भारत को सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक-8 मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करेगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच करीब 77.7 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदों पर समझौता हस्ताक्षर किये गये हैं।

भारत-इजराइल रक्षा प्रणाली आपूर्ति समझौता

- इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के अनुसार नई दिल्ली की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) इस परियोजना के लिए मुख्य विनिर्माता कपंनी होगी।
- आईएआई भारतीय नौसेना के सात पोतों के लिए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल (एलआर-एसएएम) और हवाई मिसाइल रक्षा प्रणाली (एएमडी), एएमडी प्रणाली बराक-8 के समुद्री संस्करण की आपूर्ति करेगी।
- बराक-8 एक भारतीय-इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी के साथ-साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- बराक-8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किमी है। यह साढ़े चार मीटर लंबी मिसाइल है जिसका वजन लगभग तीन टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है।
- हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम्स और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) मिसाइलों का उत्पादन करेगी।
- आईएआई इजरायल की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यह मिसाइल भेदी, हवाई प्रणालियों और खुफिया और साइबर सुरक्षा प्रणालियों सहित रक्षा प्रणालियों का विकास, विनिर्माण और आपूर्ति करती है।

इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई)

- इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) इजराइल की प्रमुख एयरोस्पेस और विमानन निर्माता कंपनी है।
- यह सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए कार्य करती है यह कंपनी पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में कार्यरत है।
- लड़ाकू विमान के निर्माण के अलावा, आईएआई नागरिक विमान मध्यम आकार के व्यापार जेट विमानों को भी बनाता है।
- इन उत्पादों के विशेष रूप से इजराइल के रक्षा बलों की जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है जबकि अन्य देशों के लिए आईएआई सैन्य विनिर्माण करता है।

स्रोतः द हिंदू

वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा को शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है। यह एक बायोडिग्रेडेबल वायरलेस डिवाइस है जो तंत्रिकाओं के रीजनरेशन तथा क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में सहायक है। माना जा रहा है कि यह खोज भविष्य में तंत्रिका कोशिकाओं के उपचार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

मुख्य तथ्य

- बायोइलेक्ट्रॉनिक दवा एक किस्म की वायरलेस डिवाइस होती है, इसे शरीर के बाहर एक ट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- माना जा रहा है कि एक बार इम्प्लांट करने के बाद यह अगले दो सप्ताह तक शरीर में कार्य कर सकती है।
- इस अवधि के उपरांत यह दवा स्वतः ही शरीर में अवशोषित हो जाती है।
- इसका आकार एक छोटे सिक्के जितना होता है तथा मोटाई कागज के समाज होती है।
- वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका प्रयोग चूहों पर किया गया जिसके बाद सकरात्मक परिणाम पाए गये।
- प्रयोग के बाद पाया गया कि चूहों में बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्जिकल रिपेयर प्रक्रिया के बाद नियमित रूप से तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्से को इलेक्ट्रिक इम्पल्स देती है।
- इससे उन चूहों की टांगों में तंत्रिका कोशिकाओं में पुनः वृद्धि हुई और बाद में उनकी मांसपेशी की मजबूत व नियंत्रण में भी वृद्धि हुई।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इसके फायदे क्या हैं?

- इस प्रकार की दवा से सीधे ही शरीर के क्षतिग्रस्त भाग अथवा उपचार की आवश्यकता वाले भाग पर कार्य किया जा सकता है।
- पारंपरिक दवा से होने वाले साइड इफेक्ट की तरह इसमें यह खतरा कम होगा।
- इस इम्प्लांट को शरीर में स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख करने की अधिक चिंता नहीं होगी क्योंकि यह स्वत: ही अवशोषित हो जाती है।
- भविष्य में इस प्रकार की दवा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति का कारण बन सकती है।

स्रोत: द हिंदू

चीन ने विश्व के सबसे बड़े परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- चीन ने 16 अक्टूबर 2018 को विश्व के सबसे बड़े मानवरहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया. चीन के आधिकारिक मीडिया ने 17 अक्टूबर 2018 को इसकी जानकारी दी। यह परिवहन ड्रोन डेढ़ टन तक भार ढो सकता है।
- सरकारी समाचार पत्र 'चाइना डेली' की एक रिपोर्ट के अनुसार परिवहन ड्रोन फीहोंग-98 का विकास 'चाइना एकेडमी आफ एयरोस्पेस इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी' ने किया है।

मुख्य तथ्य:

- रिपोर्ट के अनुसार यह ड्रोन 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।
- इस ड्रोन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है।
- इसकी उड़ान की अधिकतम सीमा 1200 किलोमीटर है।
- अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह ड्रोन सामान्य रूप से उड़ान भर सकता है और इसकी लागत भी किफायती है।
- चीन मानवरहित विमानों के विकास में आगे रहा है।

ड्रोन:

- ड्रोन यह आधुनिक युग का एक नवीन प्रकार का विमान है, इसमे चालाक नही होता, इसके स्थान पर इसे सुदूर स्थान से नियंत्रित किया जाता है, इसका प्रयोग जासूसी करने, बिना आवाज किए मिसाइल हमला करने हेतु किया जाता है।

अन्य जानकारी

- चीन ने सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
- चीन की एक खनन कंपनी ने हाल ही में एक सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है। इसे भारत-रूस के संयुक्त मिसाइल ब्रह्मोस के संभावित प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मिसाइल को युद्धक विमानों और युद्धपोतों में तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल में चीनी कंपनी ने 18.8 करोड़ डॉलर का निवेश किया है।
- गोल्बल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान अब चीन की इस नई मिसाइल को खरीद सकता है। इस मिसाइल में लांच, कमांड, कंट्रोल, लक्ष्य को भेदने के संकेत और समग्र सपोर्ट सिस्टम भी है। यह हल्की मिसाइल अधिक तेजी से अधिक दूर तक जा सकती है। चीन के सैन्य विश्लेषक का दावा है कि सुपरसोनिक मिसाइल न केवल भारत और रूस की ओर से बनाई गई ब्रह्मोस से सस्ती है बल्कि उससे ज्यादा उपयोगी है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

हरियाणा सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक बल 'कवच' की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 08 अक्टूबर 2018 को घोषणा की कि हरियाणा सरकार आतंकवाद निरोधक बल (एटीएफ) का गठन करेगी। इस बल का नाम 'कवच' रखा जायेगा जिसमें राज्य पुलिस से विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान शामिल होंगे।

☞ कवच नामक यह बल राज्य की वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेगा। हरियाणा पुलिस के चुनिंदा जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) से प्रशिक्षण हासिल होगा।

मुख्य तथ्य

- गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों की आवश्यकता को देखते हुए इस बल के गठन का फैसला लिया गया है।
- 'कवच' नामक इस सुरक्षा बल का मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया जायेगा।
- इस बल में कुल 150 जवान होंगे तथा 50-50 के चरण में इनकी भर्ती होगी।
- नवनियुक्त सुरक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण मानेसर स्थित स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के कैंप में किया जायेगा। यहां इन जवानों को 14 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- इस बल का कार्य आतंकवाद एवं दूसरे बड़े खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
- इस बल की कमान एडीजी रैंक के अधिकारी द्वारा संभाली जाएगी।

पृष्ठभूमि

- पठानकोट और मुंबई पर हमले के बाद यह कहा जा रहा था कि यदि उस समय वहां त्वरित कार्यवाही बल होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। एटीएफ के गठन का उद्देश्य (भविष्य के लिए) बेहतर तैयारी है। इसलिए हरियाणा में एटीएफ के गठन के तौर-तरीके को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- यह बल उन सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा जिनका हरियाणा वर्तमान में सामना कर रहा है। इस बल का गठन राज्य के समक्ष आ रहे किसी विशिष्ट खतरे से निपटने के लिए नहीं किया जा रहा है।

स्रोतः द हिंदू

नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब जाने वाला अंतरिक्षयान बना

चर्चा में क्यों?

☞ नासा द्वारा सूर्य व उसके बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे करीब जाने वाला मानवनिर्मित अंतरिक्षयान बन गया है।

मुख्य तथ्य

- पार्कर सोलर प्रोब सात साल तक सूरज का चक्कर लगाते हुए सूर्य का अध्ययन करेगा। यह यान सूर्य की बाह्य परत कोरोना के पास रहेगा। कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। नासा के इस अभियान का उद्देश्य कोरोना के पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।
- डेढ़ अरब डॉलर की लागत से बना यह मानवरहित स्पेसक्राफ्ट 13 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे इसलिए छोड़ा गया ताकि पता लगाया जा सके कि सोलर सिस्टम में कौन-कौन सी चीजें धरती को प्रभावित करती हैं। स्पेसक्राफ्ट के परीक्षण के पीछे सौर तूफान उठने के कारणों का पता लगाना भी एक मकसद है। पार्कर प्रोब का मकसद पृथ्वी की सतह पर सूर्य के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पार्कर लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सूर्य के नजदीक पहुंचता रहेगा और वैज्ञानिकों के लिए दशकों से पहेली बने इस तारे के रहस्यों की जानकारी देता रहेगा। इस अभियान में सूर्य से इसकी निकटतम दूरी 61.63 लाख किलोमीटर होगी।
- वर्ष 2024 में पार्कर के यहां तक पहुंचने का अनुमान है। पूरे अभियान के दौरान यह सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा। अक्टूबर 2018 की शुरुआत में पार्कर शुक्र ग्रह से महज 2414 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा था।

सोलर प्रोब के बारे में:

- सोलर प्रोब नासा द्वारा सूर्य के कोरोना व सौर वायु का रहस्य जानने के लिए भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है। यह यान मूलत: वर्ष 2015 में भेजा जाना प्रस्तावित था, परन्तु कई देरियों के बाद अंतत: इसे 12 अगस्त 2018 को अंतरिक्ष में भेज दिया गया।
- इस यान का नाम फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने तारों द्वारा ऊर्जा संचारित करने के कई अवधारणाएं पेश की थीं। नासा के इस यान का नाम पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है।
- सोलर प्रोब सूर्य के काफी निकट तक पहुँचेगा और इसका डिजाइन व निर्माण कार्य अनुभवी एप्लाइड फिजिक्स लैब (एपीएल) द्वारा किया जाएगा। इस अभियान को भेजे जाने में सात वर्ष का समय लग जाएगा।
- सूर्य के कोरोना व सौर वायु के बारे में इससे काफी तथ्य उजागर होने की संभावनाएँ हैं। नासा का यह अभियान एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य पर किए जा रहे अध्ययन में भी लाभकारी सिद्ध होगा।

स्रोत: द हिंदू

'सौरा जलनिधि' योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 30 अक्टूबर 2018 को 'सौरा जलनिधि' योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा सिंचाई में सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक पंप सेट्स का प्रयोग बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जहां बिजली व्यवस्था बदहाल है, वहां सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

योजना से संबंधित मुख्य तथ्य:

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना का वेब पोर्टल भी लांच किया। इस इवेंट में 30 जिलों के किसानों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया।
- पहले चरण में यह योजना उन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी जहाँ पंप सेट को चलाने के लिए विद्युत् उपलब्ध नहीं है।
- सरकार ने इस योजना के लिए वित्तवर्ष 2017-18 में 27.18 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।
- इस योजना से सालाना 1.52 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, तथा 5,000 परिवारों की आजीविका में मदद मिलेगी, तथा कार्बन पदचिन्हों में भी कमी आएगी।
- इस योजना का लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होंगे तथा जिनके पास न्यूनतम 0.5 एकड़ कृषि भूमि होगी।

योजना की विशेषताएं:

- यह योजना हमारे किसानों के लागत के बोझ को कम करेगी और कृषि आय में भी वृद्धि करेगी।
- सौरा जलानिधि योजना के तहत किसानों की खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिले यह निश्चित करेगी।
- सौरा जलानिधि योजना हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी और प्रदूषण को कम करेगी।
- सौरा जलानिधि, अभिसरण मोड में एक अच्छी तरह से आधारित सौर पंप सिंचाई प्रणाली है।
- इसके अलावा, इस सरकारी योजना के अंतर्गत, बिजली आपूर्ति क्षेत्रों द्वारा संरक्षित या कम से कम सेवा के किसानों को सौर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। ताकि वह सभी किसान बिना किसी परेशानी के अपनी कृषि कर सके।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चीन द्वारा वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किये जाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ चीन द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 तक अपना 'कृत्रिम चंद्रमा' लॉन्च करने की घोषणा की गई। चीन का उद्देश्य शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को हटाने तथा शहरी क्षेत्रों से बिजली की खपत तथा लागत कम करने के लिए यह कदम उठाया जायेगा।

☞ चीन द्वारा यह कृत्रिम उपग्रह दक्षिण-पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर में विकसित किया जा रहा है। चेंगदू एयरोस्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन वू चुनफेड द्वारा इस बात की घोषणा की गई।

कृत्रिम चंद्रमा की विशेषताएं

- यह कृत्रिम चंद्रमा पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर के दायरे को रोशन करेगा।
- यह कृत्रिम चंद्रमा वास्तविक चंद्रमा की अपेक्षा आठ गुना अधिक चमकीला होगा।
- अभी तक प्रकाशक उपग्रह के रूप में प्रचारित किए जा रहे इस उपग्रह को चेंगदू शहर के दक्षिण पश्चिम इलाके के ऊपर 2020 तक स्थापित किया जाएगा।
- इस कृत्रिम चंद्रमा को परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- यह विचार एक फ्रांसीसी कलाकार से प्रेरित है जिसने पृथ्वी पर लटकते दर्पणों के हार का अनुमान लगाया था।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सेटेलाइट की रोशनी इतनी होगी कि इससे शहर में स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेटेलाइट एक परावर्तक कोटिंग का इस्तेमाल करेगा जिससे प्रतिबिंबित होने वाली रोशनी धरती के 50 वर्ग मील क्षेत्र को रोशनी प्रदान करेगा।

आलोचना

☞ कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किये जाने की घोषणा करने के बाद आलोचकों के स्वर भी प्रखर हो गये हैं। आलोचकों तथा पर्यावरणविदों का मानना है कि कृत्रिम चंद्रमा का प्रयोग रात न होने का आभास होगा जिससे शहर के पर्यावरण तथा पशु-पक्षियों पर दुष्प्रभाव हो सकता है।

स्रोतः द हिंदू

पाकिस्तान साल 2022 में भेजेगा पहला अंतरिक्ष यात्री

चर्चा में क्यों?

☞ पाकिस्तान चीन की मदद से वर्ष 2022 में पहली बार किसी पाकिस्तानी को अंतरिक्ष में भेजेगा। पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष मिशन की योजना 2022 के लिए बनाई गई है और प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गइ।

☞ यह समझौता पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन (सुपारको) और चीन की कंपनी के बीच हुआ है। पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच रक्षा संबंध पहले से ही काफी अच्छे है।

रक्षा संबंध:

- पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच रक्षा संबंध पहले से ही काफी अच्छे है. साथ ही पाकिस्तान, चीनी मिलिट्री उपकरणों का सबसे बड़ा खरीददार भी है।
- पाकिस्तान ने चीनी प्रक्षेपण यान की मदद से दो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा था। दोनों उपग्रहों का निर्माण पाकिस्तान में किया गया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पाकिस्तान ने चीनी लॉन्ग मार्च (एलएम-2सी) रॉकेट को जियूक्यूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया था। यह सेंटर चीन में गोबी के रेगिस्तान में स्थित है। इसके अलावा एक और सैटेलाइट जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पीआरएसएस1 था उसे भी लॉन्च किया गया था।
- चीन की मदद से लॉन्च हुए पाक के दूसरा टेस्ट पाक-टेस-1ए था। इस सैटेलाइट को सुपारको की ओर से डेवलप किया गया था। इस सैटेलाइट की वजह से पाकिस्तान के सैटेलाइट तैयार करने की क्षमताओं में इजाफ हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान को मौसम, पर्यावरण और कृषि आधारित जानकारियों के लिए दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन सैटेलाइट को चीन भेजा गया था क्योंकि पाकिस्तान के पास किसी भी तरह का कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं है।

पहला मानव अंतरिक्ष मिशन:

- चीन ने वर्ष 2003 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था। इस लॉन्च के साथ ही वह दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया था जिसने मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। चीन से पहले रूस और अमेरिका ऐसा कर चुके हैं।

अंतरिक्ष यात्री भारत की ओर से:

- भारत ने वर्ष 2022 में ही अपने अंतरिक्ष यान से पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2018 के मौके पर इस बात की घोषणा की थी वर्ष 2022 में भारत की ओर से मानव यान को भेजा जाएगा। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जो इंसान को अंतरिक्ष पर भेजेगा।

स्रोतः द हिंदू

पाकिस्तान और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू

चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान और रूस के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'द्रुझबा III' शुरू हो गया है। इस अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है। यह पाकिस्तान और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है।
- पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए रूसी सेना की एक टुकड़ी यहां पहुंच गई।

संयुक्त सैन्य अभ्यास:

- यह सैन्य अभ्यास 21 अक्टूबर से 04 नवम्बर तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का आरम्भ वर्ष 2016 में हुआ था। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान और रूस के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया था। इस साल के अभ्यास को अभी तक का सबसे आधुनिक माना जा रहा है। वर्ष 2017 में रूस में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था।
- रूसी और पाकिस्तानी रक्षा बलों की इकाइयां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पब्बी शहर में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध केन्द्र के प्रशिक्षण रेंज में संयुक्त अभ्यास कर रही है। रूस के दक्षिणी सैन्य जिले के 70 से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे है।
- दोनों देशों के सैनिक समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर अभ्यास करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि तीसरा अभ्यास पाक-रूस द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहयोग का हिस्सा है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग:

- दोनों देश ने रक्षा उद्योग और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। हथियारों और उपकरण का आयात बढ़ाने एवं सैन्य अभ्यास में संयुक्त भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए।

रूस और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध मजबूत:

- पिछले कुछ वर्षों में रूस और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। इसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सख्त रवैया भी है। इससे पाकिस्तान का झुकाव चीन और रूस की ओर अधिक हुआ है। पाकिस्तान भी रूस के साथ रक्षा सम्बन्ध मजबूत करने का इच्छुक है।
- शीतयुद्ध के दौरान के वैमनस्य के बाद रूस से पाकिस्तान के रक्षा रिश्तों में नई गति आई है और हाल-फिलहाल अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में बढ़ती तल्खी ने पाकिस्तान को रूस और चीन के और करीब ला दिया है।

सैन्य अभ्यास का मकसद:

- रूस के अनुसार पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ अनुभवों को साझा करना है। सितंबर 2018 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत रूस, चीन समेत अन्य सदस्य देशों की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास किया था।

स्रोत: द हिंदू

चीन ने दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का पहला सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- चीन में स्वदेश निर्मित तथा जल और थल दोनों सतहों पर कारगर विमान एजी600 (AG 600) ने 20 अक्टूबर 2018 को पहले परीक्षण के तहत सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लैंडिंग की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान कहा जा रहा है। इतना ही नहीं यह पूरी तरह से चीन में बनाया गया है।
- चीन की सरकारी विमानन कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कोरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा निर्मित इस विमान ने हूबेई प्रांत के जिंगमेन में उड़ान भरी और बाद में समुद्र में भी उतरा।

एजी 600

- एजी 600 नामक कोड, जिसे टीए-600 भी कहा जाता है, वर्तमान में उड़ने वाला सबसे बड़ा उभयचर विमान है। यह चीन विमानन उद्योग निगम (एविक) द्वारा डिजाइन किया गया है। इसकी ऑपरेशन रेंज लगभग 4,500 किलोमीटर है।
- हवाई जहाज ने 24 दिसंबर 2017 को झुहाई, गुआंग्डोंग में अपनी पहली उड़ान भरी। एजी 600 चीन की तीन राज्य-अनुमोदित "बड़ी विमान परियोजनाओं" में से एक है।
- 23 जुलाई 2016 को झुहाई एविक कारखाने में प्रोटोटाइप पर कार्य शुरू किया गया था। यह विमान अपने साथ 53.5 टन वजन अपने साथ ले जा सकता है। महज कुछ सेकंड में 12 टन पानी स्टोर करने की क्षमता रखता है।
- AG 600 चीन के बड़े विमानों के बेड़े का तीसरा सदस्य है। दो अन्य विशाल विमान Y-20 (मालवाहक विमान) तथा यात्री विमान C919 हैं।

विमान की खासियत:

- इस विमान की खासियत यह भी है कि इसका इंजन भी पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इसके अलावा यह 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है।
- यह विमान समुद्र में बचाव के दौरान अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यह विमान जंगलों की आग बुझाने, समुद्री सीमाओं की निगरानी में भी कारगर भूमिका निभा सकता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस विमान के परीक्षण की शुरुआत दिसंबर 2017 में हुई थी, इसके बाद से इसके कई चरण के परीक्षण हो चुका है। इस दौरान इसके आठ बार टेक्सिंग टेस्ट भी हुए जिसमें इससे 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तर से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ाकर पानी का छिड़काव किया गया था।
- इस विमान की लंबाई करीब 37 मीटर है जो लगभग बोइंग 737 के ही बराबर है। इस प्लेन को खासतौर से समुद्री बचाव कार्य, जंगल की आग बुझाने और समुद्र तट की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उपयोग सैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।
- यह विमान 39.6 मीटर लंबा है और एक बार में 4 हजार किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 50 यात्रियों को भी ले जाया जा सकता है।
- इस प्लेन को खासतौर से समुद्री बचाव कार्य, जंगल की आग बुझाने और समुद्र तट की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस विमान की रेंज चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में निर्मित कृत्रिम द्वीपों तक है।

स्रोत: द हिंदू

चीन ने पहली बार एक साथ तीन हाइपरसोनिक विमानों के मॉडल का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

चीन ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसॉनिक विमान के तीन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है।

परमाणु हथियार ढोने में सक्षम किसी भी विमान को रोकने के लिए इसकी स्पीड को जरूरत के मुताबिक घटाया और बढ़ाया जा सकेगा। चीन में जीउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से विमानों के तीन मॉडलों का परीक्षण किया गया।

हाइपरसोनिक विमान से संबंधित मुख्य तथ्य:

- विमान के तीनों मॉडल की अलग-अलग डिजाइन है। तीनों को डी 18-1एस, डी18-2एस और डी-18 3 एस कोड नाम दिया गया है। इसे गुब्बारे के सहारे छोड़ा गया था।
- हाइपरसोनिक विमान की रफ्तार को भी आवश्यकता अनुसार घटायी-बढ़ायी जा सकती है। इस तरह के हाइपरसोनिक विमानों का चीन ने पहली बार परीक्षण किया है।
- यह परमाणु हथियार ढोने में संपन्न विमानों पर सटीकता से हमला कर सकेगा।
- हाइपरसोनिक का अर्थ ध्वनि की गति से भी छह गुना अधिक होता है।
- यह हाइपरसोनिक विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है।
- ये परमाणु हथियार ले जाने के साथ किसी भी मौजूदा पीढ़ी की मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणालियों (ऐंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स) में प्रवेश कर सकता है।

हाइपरसॉनिक विमान

- हाइपरसॉनिक एयरक्राफ्ट उन विमानों को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से भी अधिक वेग से उड़ सकते हैं। ऐसे विमानों का विकास 21वीं सदी में हो रहा है।
- इनका उपयोग प्राय: अनुसंधान एवं सैनिक उपयोग के लिये तय किया गया है। यह लड़ाकू विमान ध्वनि के वेग के पाँच गुना से भी अधिक वेग (5 मैक से अधिक) से उड़ते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य जानकारी :

- चीनी वैज्ञानिकों ने पिछले महीने पहली बार स्टारी स्काय-दो नामक हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण किया था। इसे रॉकेट के जरिए छोड़ा गया और फिर यह अपने शॉक वेभ मैक छह (ध्वनि की रफ्तार से छह गुणा, या 7,344 किलोमीटर प्रति घंटे) पर चलता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी तरह विकसित होने के बाद इसकी रफ्तार इतनी होगी कि यह मौजूदा पीढ़ी की मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणालियों में प्रवेश कर सकता है।
- चीन का इस साल का रक्षा बजट 175 बिलियन यूएस डॉलर है। वह अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के देशों के साथ मिलकर डिफेंस और डिवेलपमेंट के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। गौरतलब है कि चीन वर्ष 2014 से ही हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण कर रहा है। चीन के अलावा अमेरिका और रूस भी इसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं।

स्रोतः द हिंदू

सस्ती जल कीटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर' विकसित

चर्चा में क्यों?

☞ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-आईआईटीआर), लखनऊ ने ट्रेडमार्क 'ओनीर' के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी 'पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली' विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन की उपस्थिति में मैसर्स ब्लूबर्ड वॉटर प्यूरिफायर, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया।

ओनीर की विशेषताएं

- पेयजल के जरिये संक्रमण के कारण विकृति एवं मृत्यु की घटनाएं विशेष रूप से बच्चों में बढ़ रही हैं।
- सीएसआईआर-आईआईटीआर द्वारा विकसित ओनीर केवल 2 पैसे प्रति लीटर की दर से सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा।
- सामुदायिक स्तर के मॉडल की क्षमता 450 एलपीएच है जिसे 5,000 से एक लाख लीटर प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
- साथ ही इसमें मेम्ब्रेन अथवा रखरखाव की लागत को भी वहन नहीं करना पड़ता है।
- यह प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी क्योंकि यह सौर ऊर्जा से संचालित हो सकती है और इसका विकास 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत किया गया है।

ओनीर का लाभ

☞ यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है और बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, सिस्ट आदि को नष्ट करती है ताकि घरेलू एवं सामुदायिक पेयजल के लिए (बीआईएस, डब्ल्यूएचओ आदि द्वारा) निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की स्थापना 1965 में हुई थी।
- यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संघटक प्रयोगशाला है।
- आईआईटीआर विषविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु, जल एवं मिट्टी में प्रदूषकों प्रभाव संबंधी शोध सम्मिलित हैं।

स्रोतः लाइव मिन्ट

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वयित गश्त का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वयित गश्त का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से भारत और इंडोनेशिया के बीच यह आयोजन चल रहा है।

मुख्य तथ्य

- इसका आयोजन इंडोनेशिया के बेलवन में 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2018 के बीच किया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच तीन दशक से चल रहे अभ्यास इंड-इंडो कारपैट-2018 का 32 वां संस्करण है।
- इस संयुक्त गश्त में दोनों देशों के पोत तथा एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के 236 नॉटिकल मील के क्षेत्र में गश्त करेंगे।

उद्देश्य:

- इस गश्त के आयोजन से इंडोनेशिया के साथ भारतीय नौसेना तथा इन्डोनेशियाई नौसेना के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। इस गश्त का उद्देश्य मित्र देशों के साथ भारत की शांतिप्रिय उपस्थिति तथा एकजुटता को व्यक्त करना है।
- इस साझा गश्त और नौसैनिक अधिकारियों का एक-दूसरे के यहां दौरा समुद्री इलाके में एकजुटता और शांतिपूर्ण मौजूदगी दिखाने के इरादे से आयोजित की जाती है।

इंड-इंडो कारपैट- 2018:

- इंडोनेशिया में साझा समुद्री गश्त के लिये भारतीय नौसेना का कोरा वर्ग का मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुलिश 11 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के बेलावन हार्बर पर पहुंचा।
- इस पोत के साथ भारतीय नौसेना का समुद्र टोही विमान डार्नियर भी अपने अंडमान स्थित नौसैनिक अड्डे से बेलावन पहुंचा जो पूरे समुद्री इलाके पर उड़ान भर कर समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले तत्वों पर निगाह रखेगा।
- इस गश्त का आयोजन तीन चरणों में किया जायेगा, इसका समापन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक समारोह में किया जायेगा।
- इस गश्त में आईएनएस कुलिश तथा डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान अंदमान व निकोबार कमांड से हिस्सा ले रहे हैं।
- इस साझा गश्त के दौरान दोनों नौसेनाएं अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के 236 किलोमीटर के दायरे में अपने युद्धपोत तैनात रखेंगी।

पृष्ठभूमि:

- हिंद महासागर के इलाके में समुद्री चिंताओं को दूर करने के लिये भारतीय नौसेना के पोत हाल के वर्षों में तैनात होते रहे हैं।
- भारतीय नौसैनिक पोत हिंद महासागर के तटीय देशों को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों की चौकसी, राहत व बचाव और अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियों में मदद करते रहे हैं।

दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के तहत भारतीय तथा इन्डोनेशियाई नौसेनाएं 2002 से साल में दो बार समन्वयित गश्त का अभ्यास करती हैं। इससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ भी बेहतर होती है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

बिहार की 'शाही लीची' को जी आई टैग प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों?

☞ बिहार के मुजफ्फरपुर में उगाई जाने वाली 'शाही लीची' को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। बौद्धिक संपदा कानून के तहत 'शाही लीची' को अब जीआई टैग (जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन) दे दिया गया है।

☞ बिहार लीची उत्पादक संघ ने जून 2016 को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में 'शाही लीची' के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। जीआई टैग मिलने से 'शाही लीची' की बिक्री में नकल या गड़बड़ी की आशंकाएं काफी कम हो जाएंगी।

विशेषताएं

- बिहार की लीची की प्रजातियों में चायना, लौगिया, कसैलिया, कलकतिया सहित कई प्रजातियां है लेकिन शाही लीची को श्रेष्ठ माना जाता है।
- यह काफी रसीली होती है। गोलाकार होने के साथ इसमें बीज छोटा होता है।
- यह स्वाद में काफी मीठी होती है। इसमें एक विशेष सुगंध भी होती है।
- बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण शाही लीची के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
- देश में कुल लीची उत्पादन का आधा से अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है।
- आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 32,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। यहां कुल 300 मैट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है।
- बिहार के कुल लीची उत्पादन में से 70 फीसदी उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है. मुजफ्फरपुर में 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती होती है।

जीआई टैग (जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग)

- जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।
- ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।
- दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
- जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों, शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

स्रोतः द हिंदू

भारतीय वायु सेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय वायु सेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर 'डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इन्द्रधनुष' के बारे में प्रधानमंत्री के सपने को ध्यान में रखते हुए 'मेडवाच' नामक एक मोबाइल हेल्थ ऐप की शुरूआत की है।

मुख्य तथ्य

- इस ऐप की कल्पना भारतीय वायुसेना के चिकित्सकों ने की है और इसे बहुत कम लागत पर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा अपने देश में विकसित किया गया है।
- वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने वायु सेना दिवस पर 08 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरूआत की।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मेडवाचः

- 'मेडवाच' से वायु सेना के जवान और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही-सही और वैज्ञानिक तथा विश्वस्त विवरण उपलब्ध होगा।
- यह ऐपू -apps-mgov-gov-in पर उपलब्ध है और इसमें मूलभूत प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे तथा पोषक आहार पर आधारित विवरण, समयानुसार स्वास्थ्य समीक्षा, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड, बीएमआई कैलकुलेटर, हेल्पलाइन नम्बरों और वेब लिंकों जैसे उपयोगी माध्यम शामिल हैं।
- 'मेडवाच' तीनों सशस्त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है।
- मेडवाच मोबाइल हेल्थ ऐप भारतीय वायु सेना की एक पहल होने के साथ ही हमारे नागरिकों के लिए एक छोटा योगदान है।

भारतीय वायु सेना दिवसः

- ☞ भारतीय वायुसेना की स्थापना 08 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मेघदूत जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात विमान और हेलीकाप्टर भी प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके साथ-साथ, विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किये गए नए विमान भी प्रदर्शित किए जाते हैं, साथ ही इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों को भी समझाया जाता है।
- ☞ भारतीय वायु सेना में लगभग 1,70,000 कर्मियों की ताकत है और 1,400 से अधिक विमान हैं और इसे दुनिया के अग्रणी वायु सेना में से एक माना जाता है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है।

स्रोतः द हिंदू

कोंकण के अल्फोंसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया

चर्चा में क्यों?

- महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में पैदा होने वाले अल्फोंसो आम को हाल ही में 'भौगोलिक चिन्ह' (जीआई) के तौर पर पंजीकृत किया गया है।
- हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह के लिए 'लोगो और टैगलाइन' को लॉन्च करते हुए कहा कि इससे कलाकारों उत्पादनकर्ताओं की बौद्धिक संपदा का उनका अधिकार तथा उस उत्पाद के उत्पत्ति को सही अधिकार मिल सकेगा।
- अल्फोंसो (हापुस) आम की पैदावार
- अल्फोंसो (हापुस) आमों की सबसे बेहतरीन किस्म महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में स्थित सिंधुदुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ में उगायी जाती है, साथ ही सबसे अच्छे आम सागर तट से 20 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित जमीन पर ही उगते हैं।
- इसके अलावा महाराष्ट्र का रत्नागिरि जिला, गुजरात के दक्षिणी जिले वलसाड और नवसारी भी अल्फोंसो की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ समय पूर्व से बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी अल्फोंसो की पैदावार शुरू की गयी है।

कोंकण अल्फोंसो के बारे में जानकारी

- अल्फोंसो को आमों का राजा कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे हापुस के नाम से जाना जाता है।
- इसके लजीज स्वाद, अनोखी खुशबू और चमकदार रंग के चलते इसकी भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग हैं।
- विश्व में यह काफी लंबे समय से मशहूर फल रहा है और इसे जापान, कोरिया तथा यूरोप को निर्यात किया जाता रहा है।
- हाल ही में अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने भी अपने बाजारों में इसके आयात को मंजूरी दी है।
- भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था और देश में इस टैग को हासिल करने वाले कुल उत्पादों की संख्या 325 हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भौगोलिक चिन्ह (जीआई टैग)

- भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।
- ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।
- दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
- जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

स्रोतः द हिंदू

ELITE IAS

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी की

चर्चा में क्यों?

☞ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने 08 अक्टूबर 2018 को अपनी रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य तथ्य

- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा उत्सर्जन स्तर को देखते हुए 2030 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसके भयानक परिणाम होंगे। आईपीसीसी की सह-अध्यक्षा डेब्रा रॉबर्ट्स के मुताबिक, आने वाले कुछ साल मानव इतिहास के लिए सबसे अहम साबित होने वाले हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जलवायु में बदलाव के असर समय से पहले दिखाई देने लगे हैं।
- रिपोर्ट के सह-लेखक और जलवायु परिवर्तन के जानकार आर्थर वाइन्स ने बयान जारी किया कि अब इस पर आम सहमति बन चुकी है कि ग्लोबल वॉर्मिंग इंसानों की सेहत पर असर डालती है और इसकी वजह से लाखों लोग जान गंवाते हैं।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- भारतीय उपमहाद्वीप में इसका सबसे ज्यादा असर कोलकाता और कराची पर पड़ने के आसार जताए गए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो भारत को 2015 से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
- विदित हो कि वर्ष 2015 में गर्म थपेड़ों से भारत में लगभग 2500 लोगों की जान चली गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 0.7 डिग्री, चेन्नई का 0.6 डिग्री और कोलकाता का 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है।
- इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, मानव सुरक्षा तथा आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है।

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

- आईपीसीसी द्वारा जारी 400 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ समय में धरती की सतह पर तापमान करीब 1 डिग्री तक बढ़ चुका है।
- इतना तापमान महासागर का स्तर बढ़ाने और खतरनाक तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति लाने के लिए काफी है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में धरती का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
- इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि तापमान में आधा डिग्री के कारण काफी बदलाव आ जाता है, इससे विश्व की जनसँख्या तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर हीट वेव, आर्कटिक की बर्फ पिघलने, समुद्री जल स्तर के बढ़ने, अनियमित वर्षा, कृषि उपज में कमी तथा कई जीव प्रजातियों के विलुप्त इत्यादि में वृद्धि हो रही है।

इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी)

- आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यकम तथा विश्व मौसमविज्ञान संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 195 देश इसके सदस्य हैं।
- इसमें विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के समूह कार्य करता हैं, वे जलवायु परिवर्तन का नियमित आकलन करते हैं। प्रत्येक 5-6 वर्ष उपरांत आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर

चर्चा में क्यों?

- विश्वभर में 13 अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना।
- वर्ष 2018 के अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का विषय 'आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना' (Reducing Disaster Economic Losse) रखा गया है।
- संयुक्त राष्ट्र डाटा के अनुसार, विश्वभर की आपदाओं में जान गंवाने वाले महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। हालांकि 60 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु बचाव योग्य स्थितियों में होती है जबकि पांच वर्ष से छोटे बच्चों में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत है। अन्य प्रभावित लोगों अथवा समूहों में दिव्यांग लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- खतरों की जोखिम को कम करना, भूमि और पर्यावरण संसाधनों का उचित प्रबंधन, आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय विशेष की तैयारी में सुधार करना और ऐसे सभी विनाशकारी घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी जारी करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयोजन का केन्द्र बिन्दु है।

अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस:

- अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपदाओं के जोखिम में कमी लाने की जागरूकता विकसित करने के लिए मनाया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है।
- इस दिवस का मनाने का उद्देश्य विश्व में जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरुकता बढ़ाई जा सके एवं आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
- यह दिन आपदा से उबरने की अधिक क्षमता वाले समुदायों और राष्ट्रों के निर्माण में भाग लेने के लिए हर नागरिक और सरकार को प्रोत्साहित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसम्बर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।

स्रोतः द हिंदू

भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 20 साल में गंवाए 79.5 अरब डॉलर: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले 20 साल में आई प्राकृतिक आपदाओं से भारत को 79.5 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदा से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है।
- "आर्थिक नुकसान, गरीबी और आपदा: 1998-2017" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव या मौसमी घटनाओं के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए काम करने वाले विभाग ने तैयार किया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य:

- संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से लेकर 2017 के बीच प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में 151 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- इन 20 वर्षों में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लगभग 215.6 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। इस तरह वर्ष 1978 से वर्ष 1997 के बीच इनसे 895 अरब डॉलर (करीब 66 हजार 350 अरब रुपए) का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ था।
- रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे होने वाली क्षति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल आर्थिक नुकसान में बड़ी मौसमी घटनाओं से होने वाली हानि की हिस्सेदारी 77 फीसदी है।

इस देश में इतना हुआ नुकसान:

देश	नुकसान
अमेरिका	944.8 अरब डॉलर (करीब 70 हजार 042 अरब रुपए)
चीन	492.2 अरब डॉलर (करीब 36 हजार 489 अरब रुपए)
जापान	376.3 अरब डॉलर (करीब 27 हजार 897 अरब रुपए)
भारत	79.5 अरब डॉलर (करीब 59 खरब रुपए)
प्यूर्तो रिको	71.7 अरब डॉलर (5,316 अरब रुपए)
फ्रांस	48.3 अरब डॉलर (करीब 3,581 अरब रुपए)
जर्मनी	57.9 अरब डॉलर (करीब 4,291 अरब रुपए)
इटली	56.6 अरब डॉलर (करीब 4,195 अरब रुपए)

- 20 सालों में मुख्य वैश्विक घटनाओं में से 91 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा थीं जिनमें 43.3 प्रतिशत बाढ़, 28.2 प्रतिशत तूफान की भागीदारी थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों आपदाएं जन-धन के नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। वहीं 563 भूकंप और सुनामी की घटनाओं से 7.5 लाख लोगों की मौत हुई जो कुल प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों का 56 प्रतिशत है।
- पिछले 20 सालों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित देशों को तकरीबन 2908 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है जो पिछले दशकों की तुलना में दोगुना है।
- रिपोर्ट में कहा गया है की जलवायु परिवर्तन का जोखिम बढ़ रहा है। कुल आर्थिक नुकसान में बड़ी मौसमी घटनाओं से होने वाली हानि की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत है, जो 2,245 अरब डॉलर के करीब है।
- पिछले 20 साल में जलवायु संबंधी आपदाओं से 13 लाख लोगों की मौत हुई और 440 करोड़ लोग बेघर हुए है।
- इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस (आईडीडी) के मुताबिक भारत ने पिछले 17 साल में 300 प्राकृतिक आपदाएं झेलीं। इनकी वजह से 76,031 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से 25,000 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई। आपदाओं की वजह से एक अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संयुक्त राष्ट्रः

- संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन के उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्वयुद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है।
- इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।

स्रोतः द हिंदू

भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि जनवरी 2019 से देश के 24 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (एनईएस) आयोजित किया जायेगा।
- सर्वेक्षण के संपूर्ण ग्रीन डेटा का पहला सेट 2020 से उपलब्ध होगा जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेने के लिये नीति निर्माताओं के हाथों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण

- सर्वेक्षण विभिन्न पर्यावरणीय मानकों जैसे- वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्सर्जन सूची, ठोस, खतरनाक तथा ई-अपशिष्ट, वन तथा वन्यजीव, जीव तथा वनस्पति, आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिये ग्रिड-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा।
- यह देश भर के सभी जिलों की कार्बन आच्छादन क्षमता का भी आकलन करेगा।
- राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण सभी जिलों को उनके पर्यावरण प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करेगा और वहां मौजूद सबसे हरित क्षेत्र आदि के बारे में बताएगा।
- सर्वेक्षण के बाद अगले वर्ष अर्थात 2020 से डेटा उपलब्ध होगा क्योंकि एकत्रित डेटा को संकलित करने में इतना समय लग जायेगा।
- देश के सभी 716 जिलों में तीन से चार साल की अवधि में सर्वेक्षण किये जाने की उम्मीद है. वर्तमान में, सभी 55 जिलों में आवश्यक प्रारंभिक कार्य और प्रशिक्षण किया जा रहा है जहाँ अगले वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा।
- इन 55 जिलों में दक्षिण दिल्ली, महाराष्ट्र में पुणे और पालघर, हरियाणा में गुरुग्राम और मेवाट (नुह) शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, बिहार में नालंदा, झारखंड में धनबाद, गुजरात में जामनगर एवं मेहसाना, राजस्थान में अलवर एवं बाड़मेर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै, कर्नाटक में शिमोगा तथा तेलंगाना में हैदराबाद शामिल हैं।

सर्वेक्षण के लाभ

- यह सर्वेक्षण नीति निर्माताओं को सटीक डेटा प्रदान करेगा जिससे वे पर्यावरण संबंधित उचित निर्णय ले सकेंगे। अभी तक देश में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था जिसके चलते किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजनाएं लागू करने से पूर्व इसकी आवश्यकता महसूस होती थी।
- वर्तमान में देश के अधिकांश मानकों पर द्वितीयक डेटा उपलब्ध है। हालाँकि, राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण पहली बार सभी हरित भागों पर प्राथमिक डेटा प्रदान करेगा।
- यह उसी प्रकार का होगा जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण समय-समय पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सूनामी प्रभावित इंडोनेशिया के लिए भारत ने 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री' आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

- भारत ने भूकंप और सूनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। भारत द्वारा इंडोनेशिया के लिए आरंभ किये गये इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री' रखा गया है।
- इसके तहत दो विमानों और तीन नौसैनिक पोतों से राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री' लॉन्च किया गया है।

भारत का 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री'

- भारतीय वायुसेना के दो विमानों सी-130 जे और सी-17 से राहत सामग्री के साथ चिकित्सा दल को रवाना किया गया है।
- इन विमानों में एक अस्पताल बनाने के उपकरण, दवाएं, जनरेटर, टेंट और पानी ले जाया गया है।
- सी-130 जे विमान से तंबुओं और उपकरणों के साथ एक मेडिकल टीम भेजी गई है। इन उपकरणों की मदद से अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा सकते हैं।
- भारतीय नौसेना के तीन पोतों आइएनएस तीर, आइएनएस सुजाता और आइएनएस शार्दुल से मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी गई है।

इंडोनेशिया में प्राकृतिक आपदा

- इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर भूकंप और सुनामी से मरने वालों की संख्या लगभग 1500 हो गई है।
- यहां आये 7.5 की तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी से समुद्र में छह मीटर ऊंची लहरें उठी थीं। इस प्राकृतिक आपदा में द्वीप पर भारी तबाही हुई।
- इस दोहरी आपदा से 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 141 स्थानों पर बनाए गए शिविरों में 70 हजार से ज्यादा लोगों ने शरण ली है जबकि प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन और पानी के लिए जूझना पड़ रहा है।
- समाचार पत्रों के अनुसार यहां पर खाद्य सामग्री की इतनी गंभीर किल्लत हो गई है कि लोग मलबों में भोजन तलाशने को मजबूर हैं।

स्रोतः द हिंदू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 02 अक्टूबर 2018 को विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही द्वितीय आईओआरए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रीस्तकरीय बैठक और द्वितीय विश्वा नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एवं प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एन्तोनियो गुटेरस भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम 05 अक्टूबर तक चलेगा।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 150 से 200 वर्षों के दौरान मानवजाति ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति अब सौर, वायु और जल जैसे अन्य विकल्पों की तरफ संकेत कर रही है, जो अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा

- इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य, में जब लोग 21वीं शताब्दी में मानवता के कल्याण के विषय में बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सूची में सर्वोच्च स्थान पर स्थित होगा।
- उन्होंने कहा कि जलवायु के साथ न्याय करने के संदर्भ में यह मंच महान कार्य करेगा।
- सौर और पवन ऊर्जा के अलावा भारत बायोमास, बायो-ईंधन और बायो-ऊर्जा की दिशा में भी काम कर रहा है। हा कि भविष्य में प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ओपेक का स्थान ले लेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक विश्व, एक सूर्य तथा एक ग्रिड' की पारिकल्पना का सन्देश भी दिया।

क्या है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन?

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी।
- इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान सीओपी-21 से पृथक भारत और फ्राँस द्वारा की गई थी।
- कुछ समय पूर्व नई दिल्ली में हुई आईएसए की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की पाँचवीं बैठक में 121 संभावित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं।
- इस सम्मेलन में आईएसए से जुड़े 61 देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जबकि कुछ अन्य देशों ने फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि कर दी है।

स्रोतः द हिंदू

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई। इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण जीव-जन्तुओं की कुल संख्या में 60 प्रतिशत तथा वनस्पतियों में 87 प्रतिशत की देखी गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की यह रिपोर्ट वन्यप्राणी जीवन, समुद्री जीवन, झीलों तथा पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रभाव को दर्शाती है।
- इस रिपोर्ट में एक नया खंड शामिल किया गया है जिसे मृदा जैव विविधता का नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वेटलैंड्स का समाप्त होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
- इस रिपोर्ट में वन्य जीव जन्तुओं के लिए उनके प्राकृतिक आवास का समाप्त होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, आदि से होने वाले खतरों को भी शामिल किया गया है।
- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से कृषि और वनों की कटाई द्वारा प्रकृति को होने वाले अत्यधिक नुकसान की ओर इशारा करती है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की भारतीय ईकाई के अनुसार विश्व भर में 4,000 से अधिक प्रजातियों पर शोध किया गया जिसमें 1970 से 2014 के बीच 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- इस रिपोर्ट में, विशेष रूप से कशेरुकी प्रजातियों की निगरानी के आँकड़े भी शामिल हैं। जिसे स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी वाले डेटाबेस से लिया गया था।

स्मरणीय तथ्य

- वर्तमान में दुनिया के कुल स्तनधारी जीवों के सिर्फ 4 प्रतिशत जंगली जानवर हैं। वहीं मानव 36 प्रतिशत हैं और पशुधन (पालतू जानवर) 60 प्रतिशत हैं। 80 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 59 शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मानव ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोककर रख पाते हैं तो भी कोरल मोर्टालिटी (समुद्री जीवों की मौत) 70 से 90 प्रतिशत रहने की संभावना है।

स्रोतः द हिंदू

वायु प्रदूषण से हर साल 6,00,000 बच्चों की मौत: डब्ल्यूएचओ

चर्चा में क्यों?

- वायु प्रदूषण से हर साल 6,00,000 बच्चों की मौत हो जाती है जो पांच साल से कम उम्र के होते हैं। यह दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 2016 में करीब एक लाख से अधिक बच्चों को जान गवांनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत का कारण भारत की जहरीली होती हवा है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य:

- रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है. देश में पीएम 2.5 कणों के कारण हवा प्रदूषित होती जा रही है।
- दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है जहां 47,674 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में 21,136 बच्चे और कांगो में 12,890 बच्चों की वायु प्रदूषण के कारण मौत हुई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक इस आयु वर्ग में मारे गए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। भारत में 2016 में 32,889 लड़कियों की मौत इसी कारण से हुई है। वहीं, पांच से 14 साल के 4,360 बच्चों को वायु प्रदूषण के कारण जान गवांनी पड़ी है। सभी उम्र के बच्चों को मिलाकर देखें तो वायु प्रदूषण से करीब एक लाख दस हजार बच्चों की मौत हो गई है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अब करीब 20 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई है जो पूरी दुनिया में इस कारण से हुई मौतों का 25 प्रतिशत है।

प्रदूषित इलाकों में रहने वाले बच्चों की संख्या:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई वायु गुणवता के मानकों से नीचे लगभग 62 करोड़ बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। उसके बाद 52 करोड़ बच्चे अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया एंव प्रशांत क्षेत्र के प्रदूषित इलाकों में रहने वाले बच्चों की संख्या लगभग 45 करोड़ है।
- दिल्ली में हवा की क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है। पीएम 2.5 का स्तर दो सौ सत्तरह तक पहुंच गया है।

पीएम 2.5 और पीएम 10 क्या होता है?

- पीएम का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण मापने के लिए इसकी संख्या में वृद्धि को मापा जाता है। वायु में पीएम 2.5 की मात्रा 60 और पीएम 10 की मात्रा 100 होने तक हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है।
- पिछले दिनों दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 600 के आसपास था जिससे शहर की हवा को सांस लेने के लिए बेहद हानिकारक माना जा रहा था। पीएम 2.5 हवा में घुलने वाला बेहद छोटा पदार्थ है जब हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ता है तो इससे धुंध जैसी स्थिति बन जाती है।
- इसी प्रकार, पीएम 10 को रेस्पायरेबल पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं जो कि बेहद छोटे कण होते हैं, इसमें धूल, गर्द और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्रशासन की रोक और चेतावनी के बावजूद हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ा है।
- बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल के 15 साल पुराने और डीजल के 10 साल पुराने वाहनों पर बैन लगा दिया।

नाइट्रोजन ऑक्साइड तीन सबसे बड़े 'हॉटस्पॉट':

- ग्रीनपीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत के प्रदूषण स्तर की बहुत ही भयावह तस्वीर जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन के विश्व के तीन सबसे बड़े 'हॉटस्पॉट' भारत में हैं और इनमें से एक दिल्ली-एनसीआर में है।
- पीएम 2.5 और ओजोन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार होता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सेटेलाइट डाटा के विश्लेषण के मुताबिक कोयला और परिवहन उत्सर्जन के दो प्रमुख स्त्रोत हैं।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्ट्रोक, फेफड़ों (लंग) के कैंसर और हृदय रोगों से होने वाली एक तिहाई मौतों का कारण वायु प्रदूषण है जो तंबाकू के सेवन से होने वाले प्रभावों के बराबर है। इसके अलावा, निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में 97% शहर (1,00,000 आबादी) डब्ल्यूएचओ के मानकों का पालन नहीं करते हैं।

स्रोतः द हिंदू

पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा जिसे इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है।
- लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माणकार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। पटना विश्वविद्यालय परिसर में दो एकड़ भूखंड पर इस केंद्र का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक श्ऑब्जरबेटरीश का निर्माण कराया जा रहा है, जहां से डॉल्फिनों को देखा जा सकेगा। गंगा नदी में जाकर डॉल्फिन देखने की व्यवस्था जल्द कराई जाएगी।

मुख्य तथ्य

- डॉल्फिनों की संख्या और उपलब्धता की जानकारी के लिए चौसा से साहेबगंज तक सर्वे का काम 42.728 लाख रुपये की लागत से तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा इसी साल 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच कराया जाएगा।
- बिहार में 10 लाख रुपये की लागत से डॉल्फिन पर फिल्म भी बनाई जा रही है तथा डॉल्फिनों को बचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिरक्षण सह प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- डॉल्फिन संरक्षण के प्रयासों में इस केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. डॉल्फिन की जनसँख्या लगातार कम होती जा रही है।
- भारत की लगभग आधी डॉल्फिन जनसँख्या बिहार में ही है, देश में डॉलफिन की अनुमानित जनसँख्या लगभग 3,000 है।

गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिका है। यह विश्व की ताजे पानी की चार डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है।
- भारत के अलावा यह यांगत्जी नदी, पाकिस्तान की सिन्धु तथा अमेजन नदी में भी पायी जाती हैं। केंद्र सरकार ने 05 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह अपने शिकार को अल्ट्रासोनिक ध्वनि से ढूंढती है। गंगा नदी डॉल्फिन मार्ग ढूँढने, भोजन, खतरे से बचने इत्यादि सभी गतिविधियों के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करती है।
- बिहार व उत्तर प्रदेश में इसे 'सोंस' जबकि आसामी भाषा में 'शिहू' के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1996 में ही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन डॉल्फिनों को विलुप्तप्राय जीव घोषित कर चुका था।
- गंगा में डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धि 'मिशन क्लीन गंगा' के प्रमुख आधार स्तम्भ होगा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार बाघ जंगल की सेहत का प्रतीक है उसी प्रकार डॉल्फिन गंगा नदी के स्वास्थ्य की निशानी है।

डॉल्फिन संरक्षण उपाय

☞ वर्ष 1997 में पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया था। इसके अंतर्गत डॉलफिन की संख्या के वैज्ञानिक डेटाबेस बनाने की योजना बनाई गई थी। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉलफिन अभ्यारण्य स्थित है, यह देश का एक मात्र डॉलफिन अभ्यारण्य है यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है।

स्रोतः द हिंदू

कोका-कोला और नेस्ले सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां: ग्रीनपीस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

☞ पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम चलाने वाली संस्था ग्रीनपीस द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक हालिया रिपोर्ट जारी की गई है। ग्रीनपीस के अनुसार सॉफ्टड्रिंक बनाने वाली कम्पनियां जैसे कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले विश्व भर में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा फैलाती हैं।

☞ रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियां हैं – कोको कोला, परफेट्टी तथा मोंड्लेज आदि। यह कम्पनियां पूरे एशियाई क्षेत्र में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण का 30 प्रतिशत प्रदूषण अकेले ही फैलाती हैं।

ग्रीनपीस का अभियान

- ग्रीनपीस द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि दुनिया के 42 देशों में उन्होंने प्लास्टिक खत्म करने के 239 अभियान चलाए हैं जिसे ब्रेकफ्री फ्रॉम प्लास्टिक नाम दिया गया है।
- इसीलिए इस सफाई अभियान से उनके पास प्लास्टिक के कचरे के 1,87,000 टुकड़े जमा हो गए हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना था कि बड़ी कंपनियां प्रदूषण फैलाने में किस हद तक योगदान कर रही हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला सबसे बड़ी कचरा उत्पादक कंपनी है।
- रिपोर्ट में डेनोन, मोंडेलेज, प्रॉक्टर एंड गैंबल और यूनिलीवर के भी नाम हैं।
- ब्रेकफ्री फ्रॉम प्लास्टिक अभियान के वैश्विक संयोजक वोन हरनांडेज ने बताया कि कोक ब्रांड का प्लास्टिक कचरा 42 में से 40 देशों में पाया गया है।
- इन ब्रांडों का लेखा-जोखा देखने के बाद पता चला कि कॉरपोरेट क्षेत्र प्लास्टिक का प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है।
- कचरे में सबसे ज्यादा पॉलीस्टाइरीन किस्म का प्लास्टिक मिला, इसका इस्तेमाल पैकेजिंग और कॉफी कप बनाने में होता है।
- दूसरे नंबर पर पीईटी बॉटल और कंटेनर थे। इसके बाद कोक कंपनी के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि महासागरों के कचरे को खत्म करने का ग्रीनपीस ने जो लक्ष्य तय कर रखा है, उसे पूरा करने में कोक कंपनी मददगार बनेगी।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल तथा 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों?

☞ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाहर से आने वाले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है।

☞ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को 10 वर्ष से अधिक डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की वेबसाइट सूची डालने का निर्देश दिया, जिनके पंजीकरण की समयसीमा खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार को इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रमुख तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिल्ली में प्रदूषण संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर नागरिक शिकायत दर्ज करा पाएंगे।
- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील से कहा कि आप इवनिंग वॉक करिए और देखिए बाहर की स्थिति कैसी है?
- सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अमिक्स ने कोर्ट में बताया कि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि आप बाहर घूम नहीं सकते हैं।
- मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति है और पुरानी दिल्ली में हालात बहुत खराब है।
- कोर्ट ने कहा कि सुबह उठने के साथ ही धुंध की स्थिति से ही अंदाज लगा सकते है कि दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है।

पृष्ठभूमि

- चार वर्ष पूर्व 26 अप्रैल 2014 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आदेश जारी किया था।
- इसके तहत एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया जबकि 07 अप्रैल 2015 को एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जानलेवा धुँआ फैलाने वाली 113 इंडस्ट्री बंद करने का नोटिस दिया है और साथ ही 1368 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्रोतः द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों?

☞ सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को निर्देश जारी करते हुए कहा कि देशभर में 01 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे न ही इनका पंजीकरण होगा।

☞ भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाए हैं। भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त तारीख से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी।
- पीठ ने कहा कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है।
- बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हैं। वर्ष 2016 में केंद्र ने घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जाएगा।

भारत स्टेज (बीएस) मानक क्या है?

- इस उत्सर्जन मानक द्वारा मोटर वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की व्याख्या की जाती है। भारत में इससे पहले भारत स्टेज (बीएस)-2, बीएस-3 और बीएस-4 के वाहन चलते रहे हैं लेकिन अब बीएस-5 प्रणाली अपनाए बिना बीएस-6 को अपनाया जायेगा।
- बीएस प्रणाली के साथ अंकों का अर्थ उसकी क्षमता से है. इसमें जितनी बड़ी संख्या होती है, उतना ही कम प्रदूषण होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक मानक पिछले मानक की तुलना में बेहतर परफॉर्म करे।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

पर्यावरण मंत्रालय ने 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

- वायु प्रदूषण सर्दियों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तरी हिस्सों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप धारण कर लेता है जिसके चलते पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया है।
- पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखे भी वायु प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। वायु प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जिसके चलते लोगों को जागरुक करना आवश्यक हो जाता है।

'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान

- दीपावली के दौरान चलाए जाने वाले पटाखों में कई ज्वलनशील रसायन होते हैं जिनमें पोटेशियम क्लोरेट पाउडर वाला अल्युमीनियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तांबा, सोडियम, लिथियम, स्ट्रोंटियम इत्यादि शामिल होते हैं।
- इन रसायनों के जलने पर तेज आवाज के साथ बहुत ज्यादा धुंआ भी निकलता है। इस धुंए और आवाज से बच्चों एवं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर हो जाती हैं।
- इन प्रतिकूल प्रभावों के साथ-साथ दीपों के त्योहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 'हरित-दिवाली' अभियान शुरू किया है।
- इस अभियान के तहत बच्चों को अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को मिठाइयों सहित पौधे उपहार स्वरूप देने और अपने घरों एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की सलाह दी जाती है।
- अभियान के दौरान बच्चों को पर्यावरण अनुकूल ढंग से दीपावली मनाने की सलाह दी जाती है।
- 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का विलय 'ग्रीन गुड डीड' अभियान में कर दिया गया है जिसका शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक एकजुटता के रूप में किया गया है।
- मंत्रालय ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

☞ इस अभियान का शुभारंभ वर्ष 2017-18 में हुआ था। उस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, विशेषकर इको-क्लब से जुड़े बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया था और कम से कम पटाखे चलाने की शपथ ली थी। यह अभियान अत्यंत सफल रहा था और वर्ष 2016 के विपरीत वर्ष 2017 में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ने विकराल रूप धारण नहीं किया था। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इसी तरह का अभियान शुरू किया है।

स्रोतः द हिंदू

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत

चर्चा में क्यों?

☞ केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 15 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत की. यह प्रणाली गंभीर वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगा सकती है और भारत सरकार के ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए अलर्ट जारी कर सकती है।

☞ दिल्ली में हवा की रफ्तार में गिरने के साथ वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली में हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक में और गिरावट देखी गई।

वायु प्रदूषण प्रणालीः

❑ वायु प्रदूषण प्रणाली भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे, भारतीय मौसम विभाग तथा मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) ने संयुक्त रूप से विकसित की है।

❑ पूर्व चेतावनी प्रणाली दिल्ली क्षेत्र में तीन-चार दिन पहले गंभीर वायु प्रदूषण की सूचना देने में मदद करेगी। केन्द्र सरकार ने वायु प्रदूषण कण कम करने के अनेक उपाये किए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 41 सदस्यों वाली टीम का गठन किया है, जो दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण स्तर की निगरानी करेगी और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देगी।

❑ इस अवसर पर अवलोकन और पूर्वानुमान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकसित नई वेबसाइट लांच की गई। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण (ईपीए) तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

❑ दिल्ली में फिलहाल, वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में है जिसके कारण मशीनों से सड़कें साफ करने, कूड़ा जलाने पर पाबंदी, ईट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण उपाय और वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसारः

❑ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण सूचकांक और नीचे आ सकता है। इसके तहत दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ाई जा सकती है और डीजल से चलने वाले जेनरेटर भी बैन किए जा सकते हैं।

❑ यह कदम तब उठाए जाएंगे जब प्रदूषण की स्थिति लगातार 48 घंटों तक आपातकालीन, बेहद खतरनाक या बहुत खराब स्तर पर होगी।

वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारणः

☞ हरियाणा और पंजाब में हर वर्ष अक्तूबर और नवंबर में धान तथा अप्रैल में गेहूं की पराली जलाना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। पराली का यह धुंआ दिल्ली में सर्दियों के मौसम में कोहरे के साथ मिलकर वायु प्रदूषण और बढ़ा देता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एक्यूआई:

- गौरतलब है कि एक्यूआई को 0-50 के बीच 'अच्छा' माना जाता है। 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101-200 के बीच 'मध्यम', 201-300 के बीच 'खराब', 301-400 के बीच 'बेहद खराब' और 401-500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
- केंद्र द्वारा संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) के मुताबिक दिल्ली में 14 अक्टूबर 2018 को सुबह 10 बजे दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 208 रहा जो ''खराब'' श्रेणी में आता है।

स्रोत: द हिंदू

"तितली" चक्रवातीय आँधी

चर्चा में क्यों?

☞ हाल ही में "तितली" नामक चक्रवातीय आँधी ने बंगाल की खाड़ी तथा "लुबान" नामक चक्रवातीय आँधी ने अरब सागर पर दस्तक दी है।

चक्रवातों का नाम कैसे पड़ता है?

- सितम्बर 2004 में ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सम्बंधित एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने निर्णय किया कि इस क्षेत्र के देश अपना-अपना नाम देंगे जिसके आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाली आँधियों का नाम रखा जाएगा।
- 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड - ने 64 नाम सुझाए।
- आँधी आने पर नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौसम वैज्ञानिक केंद्र (Regional Specialized Meteorological Centre) नामों की सूची में से एक नाम चुनता है।

चक्रवातों का नाम देना आवश्यक क्यों है?

- ज्ञातव्य है कि अटलांटिक आँधियों के लिए 1993 से ही नाम दिए जाते रहे हैं। परन्तु ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण पहले नहीं होता था क्योंकि यह भय था कि बहुल राष्ट्रीयता वाले इस क्षेत्र का कोई न कोई देश नाम के मामले में संवेदनशील हो सकता है।
- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी नामकरण होता है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग किसी चक्रवात के बारे में आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। ऐसा करने से आपदा के बारे में जागरूकता, तैयारी, प्रबंधन एवं उसके निवारण में सुविधा हो सके।

चक्रवातों के नामकरण विषयक मार्गनिर्देश

- किसी चक्रवात के नामकरण के लिए सामान्य नागरिक भी अपना सुझाव मौसम विज्ञान महानिदेशक को दे सकता है। किन्तु इस निदेशालय ने नाम चुनने के लिए कठोर नियम बना रखे हैं।
- उदाहरण के लिए नाम को छोटा और आसानी से समझ लेने लायक होना चाहिए।
- नाम ऐसा हो जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील न हो और उसका कोई ऐसा अर्थ न हो जो आक्रोश पैदा कर सके।
- व्यापक मृत्यु एवं विनाश लाने वाले चक्रवात का नाम दुबारा उपयोग में नहीं आता है। ज्ञातव्य है कि अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागरीय आँधियों के नाम की सूची के नामों का कुछ-कुछ वर्षों के बाद दुबारा प्रयोग होता है।

चक्रवातों की श्रेणियाँ

- श्रेणी 1 : 90 से 125 किमी. प्रति घंटे चलने वाली हवाएँ, घरों को नाममात्र की क्षति, पेड़ों और फसलों को कुछ क्षति।
- श्रेणी 2 : 125 से 164 किमी. प्रति घंटे की विध्वंसक हवाएँ, घरों को छोटी-मोटी क्षति, पेड़ों, फसलों और कारवाँओं को अच्छी-खासी क्षति, बिजली जाने का जोखिम।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- श्रेणी 3 : 165 से 224 किमी. प्रति घंटे की अति विध्वंसक हवाएँ, छतों और भवन-संरचना को कुछ क्षति, कुछ कारवाँओं का विनाश, बिजली जाने की संभावना।
- श्रेणी 4 : 225-279 किमी. प्रति घंटे की अति विध्वंसक हवाएँ, छतों और भवन संरचनाओं को अच्छी-खासी क्षति, कारवाँओं का विनाश, उनका हवाओं में उड़ जाना, चारों ओर बिजली का जाना।
- श्रेणी 5 : 280 किमी. प्रति घंटे से अधिक की गति की अत्यंत खतरनाक हवाएँ जो दूर-दूर तक विनाश लाती हैं।

छः छः वर्ष पर फिर से उपयोग किये गए नाम

- अटलांटिक और प्रशांत महासागर की आँधियों के नाम हर छठे वर्ष फिर से उपयोग में लाये जाते हैं। पर यदि कोई आँधी अत्यंत जानलेवा और क्षतिकारक सिद्ध होती है तो भविष्य में उस आँधी के नाम को दुहराया नहीं जाता है क्योंकि म्यामी-स्थित नेशनल हरीकेन सेंटर के पूर्वानुमानकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करना असंवेदनशील तथा भ्रमोत्पादक होता है।

चक्रवातीय मौसम

- देश में चक्रवात अप्रैल से दिसम्बर के बीच होते हैं। भीषण आँधियों से दर्जनों की मृत्यु हो जाती है और निचले क्षेत्रों से हजारों को खाली कराया जाता है। साथ ही फसल और सम्पत्ति को व्यापक क्षति पहुँचती है।

हरिकेन, चक्रवात और तूफान में अंतर

- हरिकेन, चक्रवात और तूफान ख्र ये सभी ऊष्णकटिबंधीय आँधियाँ हैं। ये सभी एक हैं, बस इनके नाम स्थान विशेष में बदल जाते हैं।
- उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी हरिकेन, हिन्द महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने आँधी चक्रवात तथा पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी तूफान कहलाती है।

स्रोतः द हिंदू

❍ पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिषेध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (Environment Pollution [Prevention and Control Authority – EPCA) का फिर से गठन

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिषेध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (Environment Pollution [1]Prevention and Control Authority – EPCA) का फिर से गठन किया है।

EPCA क्या है?

- EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित निकाय है जिस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region – NCR) में वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए विभिन्न उपाय करने का काम सौंपा गया है। इसके लिए 1998 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

प्राधिकरण का गठन

- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य होते हैं। इनमें कुछ मुख्य सदस्य इस प्रकार हैं – राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी (NCT) के पर्यावरण सचिव, नई दिल्ली नगर परिषद् के अध्यक्ष, NCT के परिवहन सचिव, दिल्ली के विभिन्न निगमों के आयुक्त तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-Delhi) एवं जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर।

प्राधिकरण के कार्य

- राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित करना और उसमें सुधार लाना, साथ ही पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को नियंत्रित करना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर के अनुसार ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan – GRAP) को लागू करना।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'स्टैट' पहल आरंभ

चर्चा में क्यों?

☞ स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतिम दिन 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक (स्टैट) पहल लॉन्च किया गया।

☞ कंपनियों के साथ पहल शुरू करने के साथ ही संभावित उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेंगे और मोटर वाहन ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में बायोगैस उपलब्ध कराएंगे।

लक्ष्य

❍ पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कुल 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस स्टेशनों से सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन गैस मिलेगी जो मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही सीएनजी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। देश में मौजूदा समय में सालाना लगभग 4.4 करोड़ टन सीएनजी का इस्तेमाल वाहन ईंधन के तौर पर होता है। इस योजना में सरकार लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी और इससे लगभग 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

योजना के लाभ

❑ यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कदम से किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी सहायता मिलेगी।

❑ इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

❑ इन प्लांट्स में तैयार होने वाली कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को सरकार खरीदेगी और उसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के तौर पर करेगी।

❑ इस योजना के जरिए सरकार सस्ता वाहन ईंधन तो मुहैया कराएगी ही साथ में कृषि अवषेशों का सही इस्तेमाल होगा और पशु मल तथा शहरी कचरे का इस्तेमाल भी हो सकेगा।

❑ इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और स्रोत मिलेगा।

❑ मौजूदा और आगामी बाजारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित जैव-गैस नेटवर्क को सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ओएमसी ईंधन स्टेशनों से खुदरा बिक्री के अलावा, संपीड़ित जैव-गैस को बाद में तारीख को सीजीडी पाइपलाइनों में कुशल वितरण और क्लीनर और अधिक किफायती ईंधन की अनुकूलित पहुंच के लिए इंजेक्शन दिया जा सकता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य खबरें

विश्व खाद्य दिवसः 16 अक्टूबर

- विश्वस्तर पर 16 अक्टूबर 2018 विश्व खाद्य दिवस मनाया गया।
- वर्ष 2018 के लिए इस दिवस का विषय 'हमारे कार्य हमारा भविष्य हैं' (Out actions are out future) है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भुखमरी की चुनौतियों के बारे में जनता में जागरूकता प्रसारित करने के साथ-साथ लोगों को भूख के खिलाफ संघर्षमय कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना हैं।
- प्रत्येक वर्ष अलग-अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व में भुखमरी खत्म करना। वर्तमान में यह विश्व के लगभग 150 देशों में निर्धनता व भूख के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अधिकतर पारिवारिक किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त भंडारण, अच्छा बीजों की, परिवहन तथा अच्छी तरह क्रियाशील बाजार साथ ही वित्तपोषण की कमी से झूझना पड़ता हैं।

उद्देश्यः

- विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी को खत्म करना है। आज भी विश्व में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। वर्तमान समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि विश्व से भुखमरी मिटाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से खेती की जाये। विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के मध्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है।

विश्व खाद्य दिवसः

- प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अन्य बहुत सारे संगठन जो खाद्य सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं जिनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आदि संगठनों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। हंगरी के प्रतिनिधिमंडल ने आम सम्मेलन के दौरान विश्व भर में विश्व खाद्य दिवस मनाने के विचार का सुझाव दिया। तब से यह 150 से अधिक देशों में हर वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा हैं।
- विश्व खाद्य दिवस नवंबर 1945 में एफएओ के 20वें आम सम्मेलन में एफएओ के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य विश्वभर में भूख एवं कुपोषण से पीड़ित लोगों की बुरी दशा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और कुपोषण तथा भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए व्यापक योजना शुरू करना। विश्व खाद्य दिवस सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1981 को आयोजित किया गया था। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए '16 अक्टूबर' को हर साल 'विश्व खाद्य दिवस' मनाने की घोषणा की गई थी।

खाद्य एवं कृषि संगठनः

- यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामजिक परिषद् के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गयी थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है. वर्तमान में इसके कुल 194 सदस्य हैं। यह संगठन बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है।

'ग्लोबल हंगर इंडेक्स':

- अभी हाल ही में 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' जारी किया गया था। इसमें दुनिया के कई देशों में खानपान की स्थिति का ब्योरा होता है। रैंकिंग भी जारी की जाती है। जीएचआई में भारत इस बार और नीचे गिरकर 103वें रैंक पर पहुंचा है। इस सूची में कुल 119 देश ही हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 85 करोड़ 30 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। अकेले भारत में भूखे लोगों की तादाद लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना भारतीय 244 करोड़ रुपए यानी पूरे साल में करीब 89060 करोड़ रुपये का भोजन बर्बाद कर देते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

डेनमार्क ओपन बैडमिंटन: साइना नेहवाल ने रजत पदक जीता

- भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 21 अक्टूबर 2018 को डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। वे फाइनल में ताइपे की ताई जू यिंग के खिलाफ 13-21, 21-13, 21-6 से हार गईं। वे ताई के खिलाफ लगातार 11वां मुकाबला हारी हैं।
- हालांकि, टूर्नामेंट का फाइनल खेलने से साइना नेहवाल को वर्ल्ड वुमन सिंगल्स रैंकिंग में फायदा हुआ। वे फिर से टॉप-10 में पहुंच गई। अमेरिका की बेलवेन झांग को एक स्थान का नुकसान हुआ। वे 11वें नंबर पर पहुंच गई।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का निधन

- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना का लंबी बीमारी के बाद 27 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। उनके एक बेटे का अगस्त 2018 में निधन हो गया था। खुराना को छाती में संक्रमण था और पिछले कुछ दिनों से बुखार भी था। मदन लाल खुराना को वर्ष 2011 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। इसके बाद से ही उनकी सेहत खराब चल रही थी।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित भाजपा व अन्य दलों के नेताओं ने खुराना के निधन पर गहरा शोक जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, डॉ हर्षवर्धन और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

वनडे में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा

- रोहित शर्मा 01 नवम्बर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांचवें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा ने विंडीज के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे में अपनी नाबाद 63 रन की पारी में चार छक्के लगाने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।
- हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही दूसरा छक्का जड़ा वह एकदिवसीय क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। रोहित शर्मा यह उपलब्धि हासिल करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे भारतीय और ओवरऑल 7वें बल्लेबाज बन गए हैं।

पंकज आडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय

- पंकज आडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पंकज आडवाणी ने यह उपलब्धि 31 अक्टूबर 2018 को चीन में आयोजित एशियन स्नूकर टूर के सेकेंड लेग में चीनी खिलाड़ी जु रेती को 6-1 हराकर हासिल की।
- पद्म भूषण से सम्मानित पंकज आडवाणी ने मार्च 2018 में एशियन बिलियर्ड्स चौंपियनशिप का खिताब जीता था। इस खिताब के जीतने के साथ ही पंकज ने होने वाली विश्व चौंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। पंकज आडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस हेमंत गुप्ता, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह और अजय

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस हेमंत गुप्ता, आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह और अजय रस्तोगी ने शपथ ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की शपथ दिलाई।
- राष्ट्रपति ने सबसे कम समय में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का आदेश पारित किया है। इन चारों जजों की नियुक्तियां उनके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या:

- चार नए जजों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल मंजूर पद 31 हैं, जिसमें अभी भी तीन पद खाली रह गए हैं। हाईकोर्ट में जज की सेवानिवृत्ति आयु 62 है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश:

- भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए बोबडे के कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर को इन चारों जजों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सरकार से सिफारिश की थी।

- ये चारों न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस मुकेश कुमार रसिकभाई शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी ऑल इंडिया हाई कोर्ट जजों की वरिष्ठता क्रम में 4,5,17 और 25वें नंबर पर आते हैं।

जस्टिस हेमंत गुप्ता

- जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी। जस्टिस गुप्ता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज और पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बतौर चीफ जस्टिस अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाए जाने के बाद अब वे 2022 में रिटायर होंगे।

जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

- जस्टिस आर सुभाष रेड्डी गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे. जस्टिस रेड्डी ने फरवरी 2016 में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। वे इस पद पर 2 वर्ष आठ महीने रहे। रेड्डी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कानून की डिग्री प्राप्त की है। आर सुभाष रेड्डी हैदराबाद उच्च न्यायालय में तेलंगाना और आध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्ययाधीश के पद पर भी कार्यरत रहे हैं।

जस्टिस एमआर शाह

- जस्टिस एमआर शाह पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। न्यायमूर्ति शाह को अगस्त 2018 में गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया था। जस्टिस एमआर शाह का जन्म 16 मई 1958 में हुआ था। शाह ने एलएलबी की डिग्री हासिल कर वर्ष 1982 में गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। गुजरात हाईकोर्ट में उन्हें 07 मार्च 2004 को एडिशनल जज बहाल किया गया और 22 जून 2005 को वह स्थायी जज बने।

जस्टिस अजय रस्तोगी

- इससे पहले जस्टिस अजय रस्तोगी त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस रस्तोगी जयपुर के हैं। गौरतलब है कि न्यायाधीश रस्तोगी 02 सितंबर 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। वे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया

- श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री के पद पर वापसी की है।

- राष्ट्रपति ने रानिल विक्रमसिंघे को अपदस्थ करके उनके स्थान पर महिंदा राजपक्षे को यह पदभार सौंपा है। इस फैसले से श्रीलंका में राजनितिक संकट गहराता हुआ लग रहा है। बर्खास्तगी के बाद विक्रमसिंघे ने संसद का आपात सत्र बुलाने की मांग की थी ताकि वह अपना बहुमत साबित कर सकें लेकिन राष्ट्रपति ने 16 नवंबर तक संसद को निलंबित कर दिया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महिंदा राजपक्षे

- महिंदा राजपक्षे का जन्म 18 नवम्बर 1945 को हुआ। वे 19 नवम्बर 2005 से 9 जनवरी 2015 तक श्रीलंका के छठे राष्ट्रपति रहे थे।
- पेशे के एक वकील, राजपक्षे को पहली बार 1970 में श्रीलंका की संसद के लिए चुना गया था।
- उन्होंने 6 अप्रैल 2004 से राष्ट्रपति बनने तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- राजपक्षे ने कोलंबो स्थित नालंदा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उन्होने वर्ष 1977 में अटॉर्नी एट लॉ की शपथ भी ग्रहण की थी।

जेयर बोलसोनारो ब्राजील के नये राष्ट्रपति चयनित किए गये

- ब्राजील राष्ट्रपति चुनावों में दक्षिणपंथी नेता जेयर बोलसोनारो को विजेता घोषित किया गया। सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने 28 अक्टूबर 2018 को उन्हें विजेता घोषित किया। आधिकारिक नतीजों में बोलसोनारा को 55.13 प्रतिशत वोट हासिल हुए जबकि उनके विरोध लेफ्ट पार्टी के फेरनांदो हाद्दाद को 44.87 प्रतिशत वोट्स मिले। बोलसोनारो (63) का कार्यकाल एक जनवरी 2019 से शुरू होगा।
- बोलसोनारो इससे पहले 07 अक्टूबर 2018 को पहले चरण का चुनाव भी जीत गए थे। बोलसोनारो ने अपने विजयी संबोधन में कहा कि वह आजादी के पैरवीकार हैं, जो ऐसी सरकार का संचालन करेंगे, जो उन नागरिकों की सुरक्षा करेगी, जो अपने कर्तव्यों का अनुसरण करते हैं और कानूनों का सम्मान करते हैं।
- गौरतलब है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान बोलसोनारो पर चुनावी रैली के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया था। इस हमले में उनके पेट में गहरे जख्म बन गए थे और उन्हें 23 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। उनके दो ऑपरेशन भी हुए थे।

जेयर बोलसोनारो

- 63 वर्षीय बोलसोनारो ब्राजीलियन सेना के पूर्व कप्तान हैं।
- वे कन्जरवेटिव सोशल लिबरल पार्टी से आते हैं।
- गर्भपात, नस्लवाद, प्रवासन, समलैंगिकता और बंदूक से जुड़े कानूनों पर बोलसोनारो के उग्र विचारों के चलते उन्हें 'ब्राजील का ट्रंप' भी कहा जाता है।
- उनकी जीत ब्राजील में आए दक्षिणपंथी रुझान को दर्शाती है। ब्राजील 1964 से 1985 तक सैन्य शासन में रहा है। उन्होंने सैन्य शासन का खुलकर समर्थन किया था।
- बोलसोनारो आखिरी समय में सोशल मीडिया के जरिए ही प्रचार कर रहे थे। जब से उन पर चाकू से हमला हुआ था, वे जनसभाएं नहीं कर रहे थे।
- बोलसोनारो अब राष्ट्रपति माइकल टेमेर का स्थान लेंगे। टेमेर डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी (एमडीबी) के सदस्य हैं।

एशियाई हॉकी चौंपियंस ट्रॉफी 2018: भारत-पाकिस्तान संयुक्त विजेता

- एशियाई हॉकी चौंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। बारिश के चलते मैच नहीं हो सका, इसलिए दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।
- इससे पहले मलेशिया ने जापान को शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने अब तीन-तीन बार इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल कर ली है। भारत के हरमनप्रीत सिंह इस बार दूसरे सर्वाधिक गोल (6) करने वाले खिलाड़ी रहे।
- ओमान के मस्कट में भारतीय समय के अनुसार यह मैच 28 अक्टूबर 2018 को रात 10.40 बजे शुरू होना था। लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद टूर्नामेंट के निदेशक ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के कोच से चर्चा के बाद फाइनल को रद्द करने का फैसला किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत ने 27 अक्टूबर 2018 को जापान की टीम को 3-2 से हराकर एशियन चौंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया था। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अन्य सेमीफाइनल में मलयेशिया को शूटआउट में 3-1 से पराजित किया कर फाइनल में प्रवेश किया था। इस मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 4-4 से बराबरी पर थीं।
- भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में ओमान को 11-0 से, दूसरे मैच में पाकिस्तान को 3-1 से, इसके बाद जापान को 9-0 और कोरिया को 4-1 से हराया था।

भारत और पाकिस्तान दो-दो बार खिताब जीत चुके है:

- भारत और पाकिस्तान एशिया में दो सबसे मजबूत हॉकी टीमें हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान दो-दो बार एशियाई हॉकी चौंपियन का खिताब जीत चुके हैं। भारत ने वर्ष 2011 और वर्ष 2016 में एशियाई चौंपियन ट्राफी हॉकी के खिताब को जीता था।
- वहीं पाकिस्तान ने दो बार लगातार वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में इस खिताब को जीता था। इससे पहले भारत और पाकिस्तान इसी टूर्नामेंट के राउंड-रॉबिन मुकाबले में भिड़े थे जहां भारत ने पाकिस्तान पर 3-1 से आसान जीत दर्ज की थी। एशियाई चौंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी।

टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 2018 को वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 के टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने यह फैसला किया है। निर्णायक मंडल में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, एन. गोपालास्वामी और डॉ. विनय सहस्रबुद्धे शामिल हैं।

टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के विजेता:

वर्ष	विजेता	विजेता के बारे में:
2014	राजकुमार सिंहजीत सिंह	वे मणिपुर नृत्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे एक अध्यापक, परफॉर्मर तथा कोरियोग्राफर हैं।
2015	छायानाट	यह एक बांग्लादेशी संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गयी थी। इस संगठन ने बंगाली संस्कृति, संगीत तथा साहित्य में टैगोर के कार्य के प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्ठ कार्य किया है।
2016	राम वनजी सुतार	राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र में धूलिया जिले के गोन्दुर गाँव में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में गाँधी सागर बांध पर चम्बल स्मारक के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे पद्मभूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं।

पहला टैगोर पुरस्कार:

☞ पहला टैगोर पुरस्कार वर्ष 2012 में भारत के महान सितारवादक पंडित रविशंकर को और दूसरा टैगोर पुरस्कार वर्ष 2013 में जुबीन मेहता को प्रदान किया गया।

पुरस्कार:

- टैगोर पुरस्कार में एक करोड़ रुपये की धनराशि, प्रशस्तिपत्र, पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी/हथकरघा से बना उत्कृष्ट उपहार प्रदान किया जाता है।

टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार:

- भारत सरकार ने वर्ष 2011 में गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मोत्सव पर टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार का गठन किया था। यह पुरस्कार किसी भी देश के व्यक्ति/संस्था को प्रदान किया जा सकता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सियोल शांति पुरस्कार-2018' हेतु चयनित

- भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2018 के 'सियोल शांति पुरस्कार' के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया जायेगा।
- पुरस्कार समिति ने भारत में अमीर और गरीब के बीच के सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी 'मोदीनॉमिक्स' को सराहा है। सियोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक फाउंडेशन के चेयरमैन क्वॉन ई-हायोक की अध्यक्षता में सियोल के जंग-यू में हुई चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता ओसामू शिमोमुरा का निधन

- जापान के वैज्ञानिक तथा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता ओसामू शिमोमुरा का 22 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे।
- आसिमू शिमोमुरा ने वर्ष 2008 में रसायन शास्त्र में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीता था। वे वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक प्रोफेसर भी थे। उन्हें अमेरिका के मार्टिन चाल्फी और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोजर वाई त्सायेन के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

चीन ने विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया

- चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर 2018 को चीन और मकाओ को हॉन्ग-कॉन्ग से जोड़ने वाले समुद्र पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल 55 किलोमीटर लंबा है।
- चीन के शहर झुहाई को हांगकांग और मकाऊ से जोड़ने वाला विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल 24 अक्टूबर 2018 को सड़क यातायात को खोल दिया जाएगा। यह समुद्री पुल हांगकांग, मकाऊ और मेनलैंड चीन को जोड़ रहा है।
- इस पुल के खोले जाने के बाद हांग-कांग से झुहाई के बीच का यात्रा का समय कम हो जाएगा। हांग कांग से झुहाई जाने में अभी 3 घंटे लगते हैं जो 30 मिनट में सिमट जाएगा। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से झुहाई तक जाने में चार घंटे का वकघ्त लगता है, जो अब घटकर 45 मिनट रह जाएगा।

पुल के बारे में:

- इस पुल में डुअल थ्री लेन है। इसकी गहराई 44 मीटर तक है। पुल का बाकी हिस्सा जमीन पर बना है। सुरंग के दोनों तरफ दो कृत्रिम द्वीप हैं। ये दोनों 10 लाख वर्ग फुट के ज्यादा इलाके में बने है। ये पर्ल रिवर एश्चुअरी के छिछले क्षेत्र में बना है ताकि पुल और सुरंग के इलाकों के बीच में ट्रांसिट मिल सके।
- समुद्र के नीचे जो सुरंग बनी है, वो 33 ब्लॉक से तैयार हुई है। इनमें से हरेक 38 मीटर चौड़ा, 11.4 मीटर ऊंचा और 80 हजार टन वजनी है। इस पुल में 4 लाख टन स्टील लगा है, जो रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है।
- इस पुल की खासियत ये है कि पुल के साथ स्नैकिंग सड़क क्रॉसिंग और एक सुरंग भी बनाया गया है। यह पुल 22.9 किलोमीटर समुद्र के ऊपर जबकि 6.7 किलोमीटर समुद्र के नीचे सुरंग से गुजरता है।
- यह पुल हांगकांग और मकाऊ समेत दक्षिण चीन के 11 शहरों को जोड़ता है। साथ ही ये अगले 120 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। यात्रा में लगने वाला समय 60 प्रतिशत तक घटेगा।
- पर्ल नदी पर बने इस 55 किलोमीटर लम्बे पुल के अंदर सुरंग भी बनाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पुल से जहां कई शहर एक दूसरे के करीब आ जाएगें वहीं व्यापार भी बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि:

- इस परियोजना का विचार वर्ष 2003 में आया था और दिसंबर 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस पर कुल 120 अरब युआन (17.3 अरब डॉलर) का खर्च आया है।
- इसका खर्च हांगकांग, झुहाई और मकाऊ की सरकारें मिलकर उठा रही हैं। हांगकांग और मकाऊ दोनों अतीत में यूरोपीय ताकतों की कॉलोनी रहे हैं और वर्ष 1990 से इनका नियंत्रण चीन को मिला है।

अदेल अब्दुल महदी इराक के नए प्रधानमंत्री बने

- अदेल अब्दुल महदी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए है। उन्होंने 24 अक्टूबर 2018 को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 22 कैबिनेट मंत्रियों में से 14 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसके लिए संसद का अधिवेशन आधी रात के बाद तक चला।
- आठ मंत्रालयों के बारे में अभी फैसला होना है, जो दो नवंबर की आखिरी तारीख से पहले लिया जाएगा। नए प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी के सामने इस्लामिक स्टेट संगठन के साथ संघर्ष के बाद देश के पुनर्निर्माण की भारी जिम्मेदारी है।

बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने

- भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने 22 अक्टूबर 2018 को विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में रजत पदक जीता। जापान के ताकुटो ओटुगुरो ने उन्हें पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट कटिगरी के फाइनल में 16-9 से हराकर स्वर्ण पदक जीएता।
- पूनिया इस हार के बावजूद रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे.। वह इस टूर्नमेंट में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विदित हो कि उन्होंने वर्ष 2013 में फ्रीस्टाइल कुश्ती के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी का निधन

- उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का 18 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. एनडी तिवारी का निधन उनके जन्मदिन के दिन हुआ। वे 93 वर्ष के थे। नारायण दत्त तिवारी देश के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें दो-दो राज्य का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे नेहरू-गांधी के दौर के उन चंद दुर्लभ नेताओं में थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान दिया।
- वे उत्तर प्रदेश के तीन बार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड को आर्थिक और औद्योगिक विकास की रफ्तार से अपने पैरों पर खड़ा करने में एनडी तिवारी ने अहम भूमिका निभाई।

एना बर्न्स ने उपन्यास 'मिल्कमैन' के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 जीता

- उत्तरी आयरलैंड की लेखिका एना बर्न्स को वर्ष 2018 के मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास 'मिल्कमैन' के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही एना बर्न्स इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली नॉर्दन आईरिश लेखिका बन गई हैं। यह उनका तीसरा उपन्यास था।
- बर्न्स को इस पुरस्कार के साथ 50 हजार पाउंड भी दिए जाएंगे। बर्न्स की किताब को लेकर जजों ने कहा कि मिल्कमैन अद्भुत किताब है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस किताब में उस युवती के दर्द का बखूबी अहसास कराया गया है। बर्न्स द्वारा लिखित 'मिल्कमैन' उपन्यास एक महिला के शादीशुदा शख्स के साथ अफेयर की कहानी है। साथ ही यह महिला एक ऐसे शख्स का सामना कर रही थी, जो यौन उत्पीड़न के लिए पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक दबाव और राजनीतिक निष्ठा जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारतीय मूल की मीनल पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया

- भारतीय मूल की अमेरिकी महिला मीनल पटेल डेविस को अमेरिका के प्रतिष्ठित प्रेजिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने उन्हें ह्यूस्टन में मानव तस्करी से लड़ने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया।
- मीनल पटेल ह्यूस्टन के मेयर सिलवेस्टर टर्नर की मानव तस्करी पर विशेष सलाहकार भी हैं। पुरस्कार पाने के बाद डेविस ने कहा, मैं अमेरिका में जन्म लेने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य थी। कई साल पहले मेयर कार्यालय से अब वाइट हाउस तक आना अविश्वसनीय है। यह इस क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है।

मीनल पटेल

- जुलाई, 2015 में विशेष सलाहकार नियुक्त की गयीं डेविस ने अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर में नीतिगत स्तर पर और व्यवस्था में बदलाव लाकर मानव तस्करी से निबटने पर स्थानीय स्तर पर बड़ा योगदान दिया।
- डेविस ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से एमबीए और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है।
- वर्ष 2015 में वह मेयर कार्यालय में विशेष सलाहकार के पद पर नियुक्त हुई थीं।
- उन्होंने वहां देश के चौथे बड़े शहर से मानव तस्करी खत्म करने के लिए शानदार काम किया।
- वर्तमान में, वे टर्नर के 'एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लान' के क्रियान्वयन पर काम कर रही हैं। पटेल संयुक्त राष्ट्र के 'विश्व मानवतावादी सम्मेलन' को भी संबोधित कर चुकी हैं।
- मीनल ह्यूस्टन के मेयर की विशेष सलाहकार भी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति पदक

- संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति पदक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों के सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों में विशेष रूप से उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह पुरस्कार अमेरिकी नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, जबकि यह एक नागरिक पुरस्कार है, इसे सैन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया जा सकता है और वर्दी पर पहना जा सकता है।

आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने पद से इस्तीफा दिया

- पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित देश आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने 16 अक्टूबर 2018 को देश में जल्द संसदीय चुनाव करवाने के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- पाशिनयान ने आर्मेनिया के राष्ट्रपति सर्ज सरगिसयान के खिलाफ दो सप्ताह तक चले प्रदर्शनों के बाद मई 2018 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पाशिनयान देश में जल्द चुनाव करवाकर अपने प्रतिद्वंदियों को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं।

स्मरणीय तथ्य

- निकोल पाशिनयान के इस्तीफे को आर्मेनिया के राष्ट्रपति अर्मेन सर्किसियन ने स्वीकार कर लिया है। निकोल पाशिनयान ने 8 मई, 2018 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था।
- आर्मेनिया में 10 दस साल तक राष्ट्रपति रहे सर्ज सरगिसयान को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो उनकी नियुक्ति के विरोध में आर्मेनिया में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए।
- इसके बाद सर्ज सरगिसयान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, उनके स्थान पर निकोल पाशिनयान को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
- प्रधानमंत्री व सरकार के इस्तीफे के बाद अब संसद का विघटन होगा तथा इसके पश्चात् नए सिरे से चुनाव कराये जाने की घोषणा की गई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आईआरसीटीसी ने 'Ask Disha' चौट बॉट लॉन्च किया

- भारतीय रेलवे के आईआरसीटीसी ने रेल यात्रा संबंधी पूछताछ का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया चौट-बॉट शुरू किया है। इस सुविधा द्वारा रेलवे यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर यात्रा, ट्रेन, टिकट और कैटरिंग से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकेंगे।
- सुविधा आरंभ किये जाने के बाद आईआरसीटीसी ने दावा किया है कि देश में वह पहला सरकारी विभाग है, जिसने इस तरह का सिस्टम शुरू किया है. आईआरसीटीसी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चौट-बॉट As Disha लॉन्च किया गया है। यह आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दायीं ओर नीचे की ओर दिया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक पॉल एलेन का निधन

- माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलेन का 15 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। पॉल एलेन कैंसर से पीड़ित थे तथा लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे।
- उन्होंने 70 के दशक में बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। गौरतलब है कि पॉल एलेन ने दो सप्ताह पहले ही सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्हें दोबारा नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा (एक प्रकार का कैंसर) ने घेर लिया है। नौ साल पहले भी इसका इलाज कराया था, लेकिन बीमारी दोबारा लौट आई।

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस: 15 अक्टूबर

- विश्व भर में 15 अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था – सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वीमेन गर्ल्स।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना हैं। विदित हो विकासशील देशों में लगभग 43 प्रतिशत महिलाएँ कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं।

मुख्य तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यदि ग्रामीण परिवेश की एक महिला को सशक्त बना दिया जाये तो वह अपने पूरे परिवार को स्वयं सशक्त बना सकती है।
- साथ ही, सतत विकास लक्ष्य जैसे गरीबी, भुखमरी, खाद्य सुरक्षा तथा महिला अधिकारों को बेहतर रूप से लागू किया जा सकता है।
- यह दिवस ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करते हुए उन्हें सशक्त बनाने हेतु मनाया जाता है।
- ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पालने के लिए उन्हें पशु भी मुहैया करा रही है।

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाकर ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 में की गई थी। ग्रामीण महिलाएं विकसित और विकासशील देशों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें संचार शक्ति योजना भी शामिल है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं के साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी उनके फोन पर उपलब्ध कराई जाती है। साल 2012 में शुरू हुई 'आनंदधारा' योजना ग्रामीण गरीबों के लिए एक गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए लागू कराया जाता है। ग्रामीण महिलाएँ जो अपने जीवनयापन के लिए कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं विश्व की एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नोवाक जोकोविच ने चौथी बार जीता शंघाई मास्टर्स ओपन खिताब

- सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक को 6-3, 6-4 से हराकर 14 अक्टूबर 2018 को चौथी बार शंघाई मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया। दूसरी सीड जोकोविच ने पुरुष एकल के फाइनल में 13वीं सीड कोरिक को एक घंटे 37 मिनट में पराजित किया। इससे पहले जोकोविच ने वर्ष 2012, वर्ष 2013 और वर्ष 2015 में जीत हासिल किया था।
- इस खिताबी जीत के बाद जोकोविच विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज राफेल नडाल के रैंकिंग अंक के करीब पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में चल रहे 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच का यह लगातार 18वीं जीत है।
- जोकोविक ने शंघाई मास्टर्स का खिताब जीतने से पहले इस वर्ष विंबलडन, अमरीकी ओपन और सिनसिनाटी मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया था। जोकोविक ने अगस्त में सिनसिनाटी मास्टर्स का भी खिताब जीता था और अब वह सभी नौ मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

पर्यावरणविद प्रोफेसर जी डी अग्रवाल का निधन

- गंगा मुद्दे पर लंबे समय से अनशन कर रहे पर्यावरणविद जी.डी. अग्रवाल का 11 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। जी.डी. अग्रवाल का निधन उस समय हुआ जब उन्हें हरिद्वार से दिल्ली लाया जा रहा था। आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके जी.डी. अग्रवाल इंडियन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सदस्य भी रह चुके थे।
- हालांकि अब वह संन्यासी का जीवन जी रहे थे। वे गंगा एक्ट की मांग को लेकर 111 दिन से अनशन पर बैठे थे। जी डी अग्रवाल उर्फ ज्ञानस्वरूप सानंद का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीन बार केंद्रीय मंत्री उमा भारती को बतौर प्रतिनिध भेजकर अग्रवाल से अनशन खत्म करने का आग्रह किया था।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने इस्तीफा दिया

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद निक्की संयुक्त राष्ट्र में एक महीने के लिए अस्थायी राजदूत के पद पर रहेंगी। निक्की ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी बतौर यूएन राजदूत अपनी सारी जिम्मेदारियों को हटा लिया है।
- हेली के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जारी हुआ है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि निक्की हेली ने शानदार काम किया। वह ब्रेक लेने के लिए साल के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि निकी हेली 2020 राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, मगर निकी हेली ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि ट्रंप के समर्थन में प्रचार करेंगी

नोबेल पुरस्कार 2018: विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर अर्थशास्त्र श्रेणी में विजेता घोषित

- नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को संयुक्त रूप से वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। मेडिसिन, फिजिक्स, केमेस्ट्री और शांति श्रेणी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद अब अर्थशास्त्र में पुरस्कारों की घोषणा की गई है।
- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स ने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार देने का फैसला किया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- दोनों अर्थशास्त्री, विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर, मैक्रोइकनॉमिक्स (सूक्ष्म अर्थशास्त्र) से संबंध रखते हैं। उन्होंने प्रकृति और मार्केट इकनॉमी के बीच के संबंध को विस्तार देने वाले मॉडल बनाए हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के तरीकों पर खोज की है।

मुख्य तथ्य

- दोनों अर्थशास्त्री अमेरिका के नागरिक हैं तथा विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।
- इन्हें ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक विकास के बीच के संबंध पर शोध के लिए यह सम्मान मिलेगा।
- इन दोनों को ही पुरस्कार राशि के रूप में 90 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 7.35 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- इससे पहले मेडिसिन, फिजिक्स, केमेस्ट्री और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा हुई थी।
- येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नॉर्डहॉस पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था और मौसम के बीच होने वाले प्रभावों पर एक मॉडल तैयार किया।
- प्रो.रोमर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने शोध में दर्शाया कि आखिर कैसे आर्थिक शक्तियां कंपनियों को नए आइडिया और तकनीके तैयार करने के लिए प्रेरित करती हैं।

अन्य श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार-2018

- इससे पहले डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। वहीं फिजिक्स के लिए आर्थर अशकिन और गेर्राड मौरोउ और दोन्ना स्ट्रिकलैंड के नाम की घोषणा की गई थी। उससे पहले मेडिसिन के लिए जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो को संयुक्त रूप से चुना गया था। फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री का नोबेल भी तीन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें फ्रांसेस एच. एरनॉल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेग्रॉरी पी विंटर का नाम शामिल है।

कनाडा की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ली

- कनाडा की संसद ने म्यांमार की नेता आंग सान सू की को सम्मानपूर्वक प्रदान की गयी कनाडा की मानद नागरिकता को वापस ले लिया है। यह सम्मान अब तक छह लोगों को दिया गया था. आंग सान सू की पहली ऐसी व्यक्ति हैं, जिनसे यह नागरिकता वापस लिया गया।
- दरअसल, उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हिंसक कार्रवाई कर रहे म्यांमार के सैनिकों के खिलाफ कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया था। रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ म्यांमार की सेना के अत्याचारों पर चुप्पी साध ने के चलते आंग सान सू की की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी खराब हुई है।

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 01 अक्टूबर 2018 को भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इस पद पर पहुंचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं। उनसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी आईएमएफ में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं।
- गीता गोपीनाथ की नियुक्ति की घोषणा करते हुए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्दे ने कहा कि "गोपीनाथ दुनिया के उत्कृष्ट अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड बेहद शानदार है और उन्हें वृहद अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल है।

गीता गोपीनाथ के बारे में जानकारी

- गीता गोपीनाथ ने अपनी एमए की डिग्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से हासिल की है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र की जॉन ज्वानस्त्रा प्रोफेसर हैं।
- गीता गोपीनाथ केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी हैं और हार्वर्ड में प्रकाशित उनके जीवन परिचय के मुताबिक, इस मानद पद पर उनकी नियुक्ति साल 2016 में हुई थी और उन्हें मुख्य सचिव का रैंक दिया गया है।
- वह भारत के वित्त मंत्रालय के जी-20 सलाहकार समिति में प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में शामिल रही हैं।
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अर्थशास्त्र और व्यापार पर किए गए शोध से साल 2001 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की है।
- गीता गोपीनाथ वर्ष 2005 में हार्वर्ड में शामिल हुईं, उससे पहले वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं।
- गीता अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू की सह-संपादक और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (एनबीइआर) में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मैक्रोइकनॉमिक की सह-निदेशक भी
- उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से हासिल की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'चौंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किये गये

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के उत्कृष्ट पर्यावरण पुरस्कार यूनाइटेड नेशन्स चौम्पियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनिया गुतेरेज 03 अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम करने वाली हस्तियों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करता है।
- भारत के साथ-साथ फ्रांस को भी इस पुरस्कार के लिए इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि दोनों ही देशों ने समान प्रयासों के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है।

पृथ्वी शॉ बने टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय

- पृथ्वी शॉ ने 04 अक्टूबर 2018 को राजकोट (गुजरात) में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलते हुए टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए। पृथ्वी शॉ ने 99 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है।
- पृथ्वी शॉ (18 वर्ष और 329 दिन) ने यह शतक जड़ते हुए 59 साल पुराना अब्बास अली बेग का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 20 वर्ष और 126 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। पृथ्वी शॉ टेस्ट डेब्यू मैच में सबसे तेज शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पृथ्वी शॉ से आगे शिखर धवन और वेस्टइंडीज के ड्वेन स्मिथ हैं।

वैज्ञानिकों को पहली बार सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा का साक्ष्य मिला

- खगोल वैज्ञानिकों ने हब्बल एवं केपलर अंतरिक्ष दूरबीनों की मदद से हमारे सौरमंडल के बाहर पहले चंद्रमा (एक्जोमून) का पता लगाया है। यह धरती से 8,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय गैसीय ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब सौरमंडल के बाहर किसी चंद्रमा की खोज गई है।
- 'साइंस एडवांसेस' पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार यह एक्जोमून अपने बड़े आकार (नेप्चून के व्यास की तुलना में) के कारण अनोखा है। यह अपने आप में एक पहली घटना है। दरअसल हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित ग्रह को एक्जोप्लैनेट (बहिर्ग्रह) और इसके चंद्रमा यानी उपग्रह को 'एक्जोमून' कहते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नोबेल पुरस्कार 2018: रसायन विज्ञान श्रेणी के लिए तीन वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा

- नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने 03 अक्टूबर 2018 को तीन वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की। इन वैज्ञानिकों में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसेस अर्नोल्ड (Frances H Arnold), जॉर्ज पी स्मिथ (George P Smith) और ब्रिटिश अनुसंधानकर्ता ग्रेगोरी विंटर (Gregory P Winter) शामिल हैं।
- रसायन विज्ञान श्रेणी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में एक महिला और दो पुरुष वैज्ञानिक हैं। रॉयल स्वीडिश अकैडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि इस साल जिन तीन हस्तियों को रासायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है उन्होंने एंजाइम्स और ऐंटीबॉडीज को विकसित करने के लिए क्रमिक विकास की शक्ति का इस्तेमाल किया है जिससे नए फार्मास्युटिकल और बायोफ्युल का निर्माण हुआ है।

ELITE IAS